

**ASPECTS OF ECONOMIC HISTORY
OF
EASTERN UTTAR PRADESH
IN
EIGHTEENTH CENTURY**



**THESIS SUBMITTED FOR THE DEGREE
OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
IN HISTORY**

THESIS SUBMITTED BY
Smt. Anno Srivastava

SUPERVISOR
Prof. C. P. Jha

DEPARTMENT OF HISTORY
(Medieval & Modern)
University of Allahabad.

University of Allahabad.

1997

विषय-सूची

पृष्ठ

प्राक्कथन

A - E

अध्याय (प्रथम)

भूमिका

१ - १५

अध्याय (द्वितीय)

उद्योग एवं व्यवसाय

१६ - ५०

अध्याय (तृतीय)

कर, चुंगी, एवं बैंकिंग प्रणाली

५१ - ८७

अध्याय (चतुर्थ)

भाग (१) भू-राजस्व व्यवस्था

८८ - ११९

अध्याय (पंचम)

भाग (२) भू-राजस्व व्यवस्था

१२० - १४६

अध्याय (षष्ठम्)

उपसंहार

१४७ - १६२

परिशिष्ट

(अ) आयात एवं निर्यात के महत्वपूर्ण केन्द्र उद्‌गारहवीं शताब्दी में

१६३ - १६४

(ब) विभिन्न फसली वर्षों में की गई राजस्व की माँग बनारस जनपद में

१६५ - १६५

(स) विभिन्न फसली वर्षों में की गई राजस्व की माग मिर्जापुर जनपद में

१६६ - १६६

(द) विभिन्न फसली वर्षों में की गई राजस्व की माग जौनपुर जनपद में।

१६७ - १६७

(य) विभिन्न फसली वर्षों में की गई राजस्व की माग गाजीपुर जनपद में

१६८ - १६८

विशिष्ट शब्दावली की सूची

१६९ - १७८

अनुक्रमणिका-(मूलस्रोत)

१७९ - १९०

सहायक ग्रन्थों की सूची

१९१ - २०४

प्राक्कथन

प्राक्कथन

भारत का सांस्कृतिक इतिहास अपनी विभिन्न विशिष्टताओं को सजोये हुये समन्वयवादिता के लिए विश्व प्रसिद्ध है। विदेशी ग्रहणीय तत्वों को आत्मसात करने की इसमें विलक्षण क्षमता अनादि काल से विद्यमान रही है। अपनी इस विशिष्टता के कारण अत्यन्त प्राचीन होते हुये भी इसके विकास की धारा निरन्तर प्रवाहित होती रही है। सार्वजनीयता, सहिष्णुता, और बौद्धिकता इसकी मुख्य विशेषता रही है। इन गुणों से सुसज्जित यह संस्कृति विश्व में बेजोड़ रही है।

भारत का पूर्वी उत्तर प्रदेश अपनी वैभवशाली सांस्कृतिक परम्पराओं के लिए सदैव से विशिष्ट रहा है। ऐतिहासिक दृष्टि से यह प्रदेश कौतुकपूर्ण रहा है। इतिहास के विद्यार्थी का इसके प्रति आकर्षण स्वाभाविक है। धर्म आस्था, परम्परा और ऐतिहासिक गौरव के इस प्रदेश का सर्वाधिक आकर्षित करने वाला भाग बनारस मण्डल अद्वितीय है। पूर्वी उत्तर प्रदेश का यह क्षेत्र सांस्कृतिक विशिष्टताओं के साथ ही साथ व्यापार और उद्योग धंधों का विशिष्ट केन्द्र भी रहा है। ऐसे ही स्थल पर अपने शोध कार्य को केन्द्रित करने का उद्देश्य कम से कम क्षेत्र का अधिक से अधिक जानकारी एकत्रित कर और शोध प्रबंध के रूप में प्रस्तुत करना सेवा का एक लघु प्रयास है।

अठ्ठारहवीं शताब्दी का पूर्वी उत्तर प्रदेश बनारस मंडल, गोरखपुर मंडल और फैजाबाद मंडल के दो जिलों से मिल कर बनता है। किन्तु मैंने इस विस्तृत क्षेत्र को अपने शोध में सम्मिलित न करके मात्र बनारस

मडल को ही लिया है। मेरे शोध निदेशक महोदय ने मुझे परामर्श दिया कि पूर्वी उत्तर प्रदेश के उन्ही भू-भाग को शोध कार्य के लिए सम्मिलित किया जाय जो ठीक १७०० से १८०० के मध्य मडल की स्थिति में थे। निःसन्देह यह परामर्श विषय के प्रति मेरे रुझान और अधिकाधिक जानकारी प्राप्त करने की ललक के अनुकूल था। पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल पर अनेक शोध कार्य हो चुके हैं। इससे सम्बन्धित शोध ग्रन्थों और शोध पत्रों की एक लम्बी श्रृंखला है। किन्तु उद्योग धंधों से सुसज्जित इस व्यापारिक स्थली पर ऐसा कोई कार्य अलग से नहीं हुआ है जिससे इसके आर्थिक पहलू का स्पष्ट और उचित मूल्यांकन किया जा सके। इसी अभाव को पूर्ण करने का मेरा यह प्रयास है।

हमारा शोध कार्य १८वीं शताब्दी के पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल पर केन्द्रित है। मुख्य विषय तत्कालीन आर्थिक पहलू की गवेषणा है किन्तु इसी के साथ तत्कालीन बैंकिंग प्रणाली, कम्पनी शासन द्वारा की गई चुंगी, कर और राजस्व व्यवस्था का अध्ययन इस शोध प्रबन्ध को महत्वपूर्ण अंग है। मैंने इस शोध प्रबन्ध को छ अध्याय में विभक्त किया है जो इस प्रकार है —

प्रथम अध्याय— भूमिका, द्वितीय अध्याय—उद्योग एवं व्यवसाय, तृतीय अध्याय—कर, चुंगी तथा बैंकिंग प्रणाली, चतुर्थ अध्याय—भू-राजस्व व्यवस्था भाग (१), पंचम अध्याय—भू-राजस्व व्यवस्था भाग (२), षष्ठम् अध्याय—उपसंहार,

उक्त अध्यायों के अन्तर्गत मैंने क्रमशः बनारस मडल का संक्षिप्त इतिहास, सम्पूर्ण मण्डल में होने वाले उद्योग और व्यवसाय तथा उनके

प्रति ब्रिटिश नीति, कर राजस्व की व्यवस्था हेतु ब्रिटिश शासन के प्रयास और व्यवस्था, कम्पनी शासन द्वारा, पूर्वी उत्तर प्रदेशके बनारस मंडल में गुगलकालीन भू-राजस्व व्यवस्थाके परिप्रेक्ष्य में किये गये परिवर्तन, सुधार कार्य एवं विस्तृत अध्ययन के आधार पर तथ्यों का मूल्यांकन और उपसंहार प्रस्तुत किया गया है।

इस शोध कार्य में विषय सम्बन्धी मूल अभिलेख, राजकीय रिपोर्ट, ट्रेवेलर्स एकाउन्ट, परिशियन स्रोत, उर्दू स्रोत, संस्कृत स्रोत, हिन्दी स्रोत, पत्र पत्रिकाएँ, समाचार पत्र एवं आवश्यकतानुसार विशिष्ट ग्रन्थों के तथ्यों को आधार बनाकर कार्य किया गया है।

अपने शोध कार्य के सन्दर्भ में मैंने इलाहाबाद विश्वविद्यालय पुस्तकालय, स्टेट लाइब्रेरी इलाहाबाद, पब्लिक लाइब्रेरी इलाहाबाद, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू रेकार्ड रूम लखनऊ, इलाहाबाद म्युजियम, नेशनल लाइब्रेरी कलकत्ता, काशी राज विद्या मंदिर ट्रस्ट वाराणसी, कारमाइकल लाइब्रेरी वाराणसी, राष्ट्रीय अभिलेखागार दिल्ली, राजकीय अभिलेखागार लखनऊ, क्षेत्रीय अभिलेखागार इलाहाबाद, सम्बन्धित जनपदों के कलेक्ट्रेट रेकार्ड आदि से प्राप्त सामग्री का अवलोकन और अध्ययन किया है तथा प्राप्त तथ्यों के आधार पर शोध ग्रन्थ की रचना किया है। अध्ययन स्थलों के सम्बन्धित अधिकारियों और कर्मचारियों द्वारा प्रदत्त सहयोग ~~से~~ उनके प्रति अपना धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ।

इस शोध कार्य में मुझे मेरे शिक्षकों, सहयोगियों, मित्रों, परिवारजनों ने जो परामर्श और सहायता दिया है उससे मैं निश्चित रूप से लाभान्वित हुई हूँ। स्व० डा० राधेश्याम जी के निर्देशन में शोध कार्य के लिए मेरा

नामाकन हुआ। यद्यपि उनकी अस्वस्थता के कारण उनके निर्देशन में मेरा कार्य पूर्ण नहीं हो पाया किन्तु निःसन्देह उन्हींके विशेष आशीर्वाद के फलस्वरूप आज मैं यह शोध प्रबन्ध प्रस्तुत करने में समर्थ हो सकी हूँ। पूज्य स्व० राधेश्याम जी के प्रति यह मेरी श्रद्धाजलि है।

मैं विशेषरूप से अपने वर्तमान निर्देशक प्रोफेसर श्री सी०पी० झा साहब जो स्नाकोत्तर स्तर पर मेरे गुरु भी रहे हैं के प्रति ऋणी और कृतज्ञ हूँ जिन्होंने मुझे अपना निर्देशन प्रदान करने की सहमति देकर मुझ पर महान कृपा की है। इतना ही नहीं इस शोध प्रबन्ध को पूर्ण करने में मेरा मार्गदर्शन बड़ी ही सहृदयता से किया। उनके द्वारा कार्य का सूक्ष्म निरीक्षण, सुझाव और सशोधन का प्रतिफल है मेरा यह शोध प्रबन्ध। मैं पूर्ण विनम्रता के साथ बारम्बार उनके प्रति अपना आभार व्यक्त करती हूँ। विभागाध्यक्ष डा० श्रीमती रेखा जोशी के प्रति मैं ससम्मान आभार प्रकट करती हूँ जिन्होंने कार्य के मध्य आये अनेक व्यवधानों को दूर करने में मेरी सहायता किया।

रीडर श्री विनय चन्द्र पाण्डेय जी, जो स्नाकोत्तर स्तर पर मेरे सहपाठी भी रहे हैं के द्वारा उदारतापूर्णक दिये गये बहुमूल्य परामर्श का स्मरण मेरा सुखद कर्तव्य है। प्रो० श्री एन० आर० फारुकी एव रीडर श्री पी० एल० विश्वकर्मा के सहयोगात्मक भाव के लिए मैं अपना आभार व्यक्त करती हूँ।

कम्प्यूटर कम्पोजिंग के निमित्त सलग्न श्री विनय शुक्ला, स्वामी लक्ष्मी कम्प्यूटर सेटर ४६/५ बी०१ मालवीय रोड, जार्ज टाउन, इलाहाबाद ‡

दूरभाष — ६०६१५३, जो कि मेरे पुत्र समान है। उन्हे विशिष्ट रुप से धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ एव आशीर्वाद प्रदान करती हूँ।

अन्त मे मै पुन अपने समस्त गुरुजनो, सहयोगियो और मित्रो के प्रति सादर धन्यवाद एव आभार प्रकट करती हूँ।

अन्नो श्रीवास्तवा
२२/१२/९९
(श्रीमती अन्नो श्रीवास्तवा)

दिसम्बर १९९७

भूमिका

भूमिका

पूर्वी उत्तर प्रदेश के जिले अपने प्राचीन गौरव एव गरिमा के लिए प्रसिद्ध है। जहाँ एक ओर बनारस जनपद अपनी सभ्यता और सस्कृति का एक मुक्त क्षेत्र है। वही जौनपुर भी अपनी प्राचीनता के लिए यमदग्नि ऋषि की पावन तपोभूमि के रूप में सर्वविदित है।^१ गाजीपुर जनपद गांधी नायक की सजीव कथाओं से परिपूर्ण है तथा मौर्य वंश के शासकों के कारण अपना विशेष अस्तित्व रखता है।^२ मिर्जापुर विन्ध्यवासिनी देवी के पूजन और आस्था के लिए प्रसिद्ध है।^३ पूर्वी उत्तर प्रदेश के समस्त जनपद एक समृद्ध और वैभवशाली सभ्यता एव सस्कृति अपने में सजोये हुये हैं। गंगा के किनारे पर स्थित भारत का प्रमुख धार्मिक नगर बनारस है जहाँ के असंख्य मन्दिर और मस्जिद अपनी गौरवपूर्ण इतिहास के उदाहरण हैं।^४ इस पवित्र नगरी का सृजन ईश्वर ने स्वयं ही वरुणा और अस्सी नदियों के निकट किया था। यह पवित्र स्थली समस्त दरिद्रताओं से मुक्त है।^५ यह भारत में नदियों के किनारे बसे नगरों में सर्वाधिक सुन्दर है। पवित्र गंगा के किनारे स्थित प्राचीन नगर बनारस ऐतिहासिक वैभव से युक्त है। बनारस निश्चय ही भागीरथी के शीतल तथा पवित्र जल के तट पर बसे

१ बलदेव उपाध्याय — काशी में पाण्डित्य परम्परा — पृष्ठ — १

२ भारत' समाचार पत्र, १३ सितम्बर १९८६

३ इम्पीरियल गजेटिपर ऑफ इण्डिया, जिल्द — १२ पृष्ठ २२४

४ 'कल्याण' पत्रिका विशेष संस्करण—पृष्ठ—१३८

५ ई० बुड— दि रिवोल्ट इन हिन्दुस्तान' — पृष्ठ—३२

६ स्कंद पुराण—काशी—खण्ड—३०—पृष्ठ २०—२१

नगरो मे अद्वितीय है जो पडितो, पुजारियो तथा धर्म के प्रति आस्थावान जन सामान्य का आश्रय स्थल है। यह नगर न केवल धर्मस्थल है बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश का सर्वविदित व्यापारिक स्थल भी है। बनारस नगर जहाँ विष्णु, शिव व शिवलिंग पूजा के लिए अपना विशेष महत्व रखता है वही इसी नगर का सम्भाग मिर्जापुर विन्धवासिनी देवी के पूजन अर्चन और आस्था के लिए प्रसिद्ध है।⁷

मुगल शासक औरंगजेब ने अपने सकल्प के अनुरूप बनारस के तमाम मन्दिरों को ध्वस्त एवं धराशायी कर दिया। उसने नगर की मौलिकता को नष्ट करने के प्रयास में इसका नाम परिवर्तित करके 'मुसलमानों का नगर' कर दिया किन्तु यह नया नाम मात्र उसके उत्तराधिकारियों द्वारा चलाये गये सिक्को तक ही सीमित रह गया। यह स्थिति तब तक बनी रही जब तक कि ईस्टइण्डिया कम्पनी द्वारा बनारस का अवध के नवाब से अधिग्रहण नहीं हो गया।⁸

१७१६ में फर्रुखशियर का कत्ल कर दिया गया और सितम्बर माह में मुहम्मद शाह को बनारस का दायित्व सौंपा गया। किन्तु यह व्यवस्था बहुत दिन तक नहीं चल सकी। मुर्तजा खॉ जो एक दरबारी था, के हाथ में बनारस, जौनपुर, गाजीपुर और चुनारगढ़ की जागीर दे दी गयी।⁹ मुगल

7 डब्ल्यू ० क्रुक—दि नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया, देयर हिस्ट्री इथनोलाजी एण्ड ऐडमिनिस्ट्रेशन—पृष्ठ २४६-२४८

8 प्रयाग दयाल—कैटेलाग ऑफ क्वायन्स ऑफ किंग्स ऑफ अवध पृष्ठ-२ (परिचय)

9 ए० एल० श्रीवास्तव—'दि फर्स्ट टू नवाब ऑफ अवध पृष्ठ ४२ एवं डगलस डेवर—ए हेन्डबुक टू दि इंग्लिश प्रीम्पूटनी रेकार्ड पृष्ठ-२५८ एवं, ए० एन० शिंह गाजीपुर जनपद इतिहास पृष्ठ २८

शासन के अन्तिम चरण में बनारस प्रान्त एक राजा के अधीन था जिसे सम्राट के शासनादेश से उपाधि मिली थी।। औरंगजेब की मृत्यु के तत्काल बाद मुगल राज्य की शक्ति और वैभव का क्षय प्रारम्भ हो गया। केन्द्रीय सरकार शक्तिहीन होती गई और प्रान्तीय अधिपति व्यावहारिक रूप से स्वतंत्र होने लगे। मुर्तजा खा ने इन जिलों को अवध के नवाब के वजीर सआदत खॉ को सात लाख रुपया के पट्टे पर दे दिया। उपरोक्त पट्टे को समाप्त कर के ये जिले मीर रूस्तम अली को आठ लाख रुपये में दे दिये गये।¹⁰ मीर रूस्तम अली ने सम्पत्ति की व्यवस्था एक भूमिहार ब्राह्मण को सौंप दिया जो वर्तमान बनारस के सत्तारूढ परिवार का संस्थापक था। मनसारां एक योग्य व्यक्ति था और शीघ्र ही इन जिलों का संस्थापक एवं वास्तविक शासक बन बैठा। नवाब के मीर रूस्तम अली से असन्तुष्ट होने पर वह उनका कानूनी पट्टेदार हो गया।¹¹ इसके तुरन्त बाद १७३८ में मनसारां की मृत्यु हो गयी और उसके पुत्र बलवन्त सिंह ने दिल्ली के सम्राट, महमूद शाह के शासनादेश से राजा की उपाधि प्राप्त की तथा बनारस, जौनपुर और चुनार का क्षेत्र सरकार के पुराने पट्टे पर १३ लाख वार्षिक राजस्व देकर प्राप्त किया। बलवन्त सिंह महत्वाकांक्षी तथा योग्य शासक था। उसमें स्वतंत्रता की भावना तीव्र थी। दस वर्षों तक उसने नये नवाब सफदरजंग को नियमित रूप से राजस्व दिया किन्तु जब १७४८ में अफगानों के उदय से उसकी शक्ति क्षीण हो गयी तो उसने राजस्व देना बन्द कर दिया और नवाब के प्रतिनिधि को भगा दिया।¹²

10 खैर-उद्दीन-मोहम्मद- तोहफा-ए-ताज (बलवन्तनामा) पृष्ठ-२ (अनुवाद फ्रेड्रिक करवेन)

एवं 'हिस्ट्री आफ बनारस-प्रो० ए० एस० अल्टेकर पृष्ठ-५६

11 वही-पृष्ठ-२, एवं गोकुल नाथ बदीजन 'चेत चन्द्रिका' पृष्ठ-३

12 प्रो० ए० एस० अल्टेकर- हिस्ट्री आफ बनारस पृष्ठ-६० एवं बलवन्त नामा-पृष्ठ-६

अफगान अहमद शाह बगश की विकसित शक्ति ने बलवत सिंह को उससे सधि करने के लिए विवश किया जिसमे उसे गंगा के उत्तरी क्षेत्र का त्याग करना पडा। किसी तरह से मराठो से सहायता प्राप्त करके सफदरजग ने अहमद शाह बगश को पराजित किया और इससे उत्साहित होकर बलवत सिंह ने बिना गोली चलाये अफगानो द्वारा छीना गया अपना क्षेत्र प्राप्त कर लिया।¹³ अब उसे नवाब वजीर का सामना करना था जो उसे दड देने के लिए बनारस आया। बलवत सिंह को उसने मिर्जापुर पहाडियो मे स्थित किले मे जाने के लिए विवश किया। लेकिन नवाब उसे पकडने या पराजित करने मे असमर्थ था। वह उसे पहाडियो मे भेजने के लिए विवश नही कर सका क्योकि इसी बीच दिल्ली के सम्राट ने उसे अहमद शाह अब्दाली के प्रकरण का निराकरण करने के लिए आमत्रित किया। दिल्ली प्रस्थान करने के पूर्व उसे मार्च १७५२ मे बलवत सिंह के साथ सन्धि करनी पडी। सफदरजग के साथ सधि करने के पश्चात बलवत सिंह को विश्राम का समय मिला जिसका उपयोग उसने अपनी स्थिति को सुदृढ बनाने के लिए किया। वजीर के साथ हाल के युद्धो ने उसे किलो के महत्व से अवगत करा दिया था और वह १७५२ मे रामनगर मे एक किले के निर्माण के लिए प्रवृत्त हुआ। १७५४ मे जब सफदर जग की मृत्यु हुई बलवन्त सिंह ने एक बार फिर स्वतत्रता की घोषणा की किन्तु वह फिर असफल रहा। १७६५ मे इलाहाबाद मे अंग्रेजो और शाह आलम के मध्य हुई सन्धि के अन्तर्गत बनारस अवध के नबाव को इस शर्त पर दिया गया कि बलवत सिंह को पूर्ववत शासक बना रहने दिया जाय।¹⁴

13 प्रो० ए० एस० अल्टेकर— हिस्ट्री आफ बनारस पृष्ठ—६०

14 वही— पृष्ठ—६२

इस सन्धि से किसी भी प्रकार से नवाब और बलवत सिंह के सम्बन्धों में सुधार नहीं हुआ। उसने दो बार नबाव को हटाने का असफल प्रयत्न भी किया। एक प्रयास अंग्रेजों के द्वारा भी किया गया। बाद में नबाव ने बलवत सिंह को देय धन में दस लाख की वृद्धि करने के लिए विवश किया। १७७० में बलवन्त सिंह की मृत्यु हो गयी। उसके बाद उत्तराधिकार के लिए उसकी पुत्री के पुत्र महीपनारायण सिंह तथा उसके अवैध पुत्र चेतसिंह के मध्य विवाद हुआ। उत्तराधिकारी बालक था और चेतसिंह ने स्वयं उत्तराधिकार प्राप्त करने के लिए नवाब को तेइस लाख रुपये घूस देने की व्यवस्था की। १७७२ में बनारस में वारेन हैस्टिंग्स तथा नवाब वजीर शुजाउद्दौला ने आपसी बातचीत में चेतसिंह को राज्य का उत्तराधिकार २२ १/२ लाख रू० वार्षिक राजस्व लेकर देना निश्चित किया। १७७५ में शुजाउद्दौला की मृत्यु के पश्चात् उसके उत्तराधिकारी आसफउद्दौला ने बनारस प्रान्त अंग्रेजों को दे दिया। किसी तरह चेतसिंह को अंग्रेज रेजीडेंट के अधीन बनारस का अधिपति बने रहने की स्वीकृति मिल गई।¹⁵ इसके तुरन्त बाद वारेन हैस्टिंग्स तथा उसकी परिषद के सदस्यों में विवाद उत्पन्न हो गया और चेतसिंह ने आन्तरिक झगड़ों को दूर कर के अपनी स्थिति सुदृढ़ करना चाहा। बनारस का प्रथम रेजीडेंट फ्रांसिस का मित्र था और चेतसिंह ने गवर्नर जनरल के विरुद्ध उसका साथ दिया। कर्नल मौनसन की मृत्यु के बाद हैस्टिंग्स का पक्ष सबल हो गया और उसने फ्रांसिस का साथ देने के कारण चेतसिंह को दण्डित करने का निश्चय किया। उसने ग्राहम को बनारस का नया रेजीडेंट

¹⁵ वही—पृष्ठ—६३

नियुक्त किया जिसने विभिन्न तरीको से चेतसिह को परेशान करना प्रारम्भ किया। चेतसिह अपने पिता की भौति सामजस्य करने वाला नहीं था। इस लिए वह परिवर्तित स्थिति का सामना नहीं कर सका।¹⁶ यहाँ तक कि ग्राहम के सहायको ने भी चेतसिह को मूर्ख बनाया और धमकाया। ग्राहम के एक समर्थक अलाउद्दीन ने एक बार चेतसिह से कहा कि रेजीडेन्ट अस्वस्थ है। हकीम ने उसके लिए लाल चीटो के सिर से बनाये गये तेल की औषधि निर्धारित की है और चार मन लाल चीटो की तत्काल आवश्यकता है। लाल चीटे दुर्लभ होने के कारण बनारस में उपलब्ध नहीं थे। अतः चेतसिह ने सारे जिले से उन्हें एकत्रित करने का आदेश जारी किया लेकिन वह पर्याप्त मात्रा में एकत्र करने में सफल न हो सका और रेजीडेन्ट के क्रोध से आतंकित हो गया। चतुर एवं धूर्त मुशी को औषधि ग्रहण करने का तरीका बदलना था। यह उसने बिना किसी कठिनाई के कर दिया। जबकि वास्तविकता यह थी कि हकीम ने ऐसे किसी भी तेल और औषधि के विषय में अपनी स्वीकृति नहीं दी थी।¹⁷ यह घटना चेतसिह की योग्यता और सामान्य बुद्धि की रूप रेखा प्रकट करने के लिए पर्याप्त है। चेतसिह की वास्तविक कठिनाई १७७८ में इंग्लैण्ड और फ्रान्स के मध्य युद्ध प्रारम्भ होने पर हुई।¹⁸ पाँच लाख की एक असाधारण राशि की मांग हैस्टिंग्स द्वारा की गई जिसे चेतसिह ने बहुत अनिच्छापूर्वक पूरा किया। १७७६ और १७८० में माँग पुनः दोहराई गयी। हैस्टिंग्स ने किसी भी प्रकार चेतसिह को लूटने का निश्चय कर लिया था और इस उद्देश्य से

16 वही— पृष्ठ — ६३

17 वही — पृष्ठ ६४

18 म्यूथिएट— 'स्माइलिंग बनारस' पृष्ठ—५२

उसने उस पर एक झगडा आरोपित किया। १७८० के लगभग उसने चेतसिंह से २००० घुडसवार सेना की आपूर्ति करने को कहा। चेतसिंह ने स्वाभाविक रूप से असीमित माँगों के विरुद्ध प्रतिवाद किया। यही हैस्टिंग्स चाहता था। मैकाले के शब्दों में उसकी योजना यह थी कि 'अधिक से अधिक तब तक माँगा जाय जब तक कि (राजा) उसका विरोध न करे। फिर उसके प्रतिवाद को अपराध मानकर उसकी सारी सम्पत्ति को लेकर उसे दंडित किया जाय। अतः अब अवसर आ चुका था। इसलिए उसने योजना को पूर्ण करने के लिए बनारस आने का निर्णय लिया। इससे चेतसिंह स्वयं को शक्तिहीन समझने लगा और वह गवर्नर जनरल के स्वागत के लिए ६० मील दूर गया और व्यक्तिगत घूस के रूप में २ १/२ लाख रु० तथा कम्पनी को अर्थ दण्ड के रूप में २२ लाख रुपये देने के लिए कहा किन्तु कुछ परिणाम न निकल सका। हैस्टिंग्स दयाहीन था।^{१९} उसने ५० लाख की माँग की। हैस्टिंग्स जुलाई १७८१ में बनारस आया और उसने कबीर चौरा स्थित माधोबाग को अपना मुख्यालय बनाया तथा चेतसिंह से उसके आचरण के लिए स्पष्टीकरण मागा। चेतसिंह ने स्वाभाविक रूप से अपने ऊपर लगाये गये आरोपों से बचने की चेष्टा की। हैस्टिंग्स ने चेतसिंह के उत्तरों को आधार रहित बताया और चेतसिंह को बन्दी बनाने का आदेश दे दिया। चेतसिंह शिवाला किले में रहता था और दो कम्पनियाँ उसे बन्दी बनाने के लिए गई थी। उन्होंने बिना किसी प्रतिरोध के अपना उद्देश्य पूरा कर लिया। किन्तु जब चेतसिंह की गिरफ्तारी की सूचना रामनगर में उसकी सेनाओं को मिली तो

^{१९} वही पृष्ठ -५२

उन्होंने नदी पार करके अग्रेज टुकड़ियों को घेर लिया। अग्रेजों को अपने हथियारों की प्रतिष्ठा में इतना विश्वास था कि उन्होंने अपने सैनिकों को रसद देने की प्रारम्भिक सावधानी नहीं बरती।²⁰ मेजर पोपहम के रसद सहित पहुँचने के पहले ही रामनगर की सेना ने अग्रेज टुकड़ियों को विजित करने में सफलता पायी और सभी अग्रेज अधिकारियों को मार डाला गया। प्रारम्भिक सफलता से उत्साहित चेतसिंह के सैनिकों ने पोपहम को भी पीछे खदेड़ दिया। किले के बाहर चल रहे संघर्ष की गड़बड़ी में चेतसिंह रक्षकों से नजर बचाकर किले की नदी के ओर की खिड़की से पहाड़ियों की सहायता से नदी में कूद गये और नाव की सहायता से उन्होंने 'रामनगर' की ओर प्रस्थान कर दिया।²¹ वहाँ से वह अपने परिवार और खजाने सहित अपने किले लतीफपुर भाग गया। यह पता चलने पर कि चेतसिंह रामनगर से भाग गया है वारेन हैस्टिंग्स ने उस किले पर अधिकार करने की चेष्टा की। उद्देश्य पूर्ति करने के लिए उसने दो अधिकारियों की संरक्षता में सेना भेजी। चेतसिंह की सेना के लिए यही श्रेयस्कर था कि वह अग्रेजों की सेना को पीछे खदेड़ दे जो उसने किया। अग्रेजों की सेना का प्रधान स्वयं कायरता से भाग गया था तथा उसकी सेना को पराजय का मुँह देखना पड़ा। इस परिस्थिति ने बनारस में हैस्टिंग्स की स्थिति को काफी दुर्बल कर दिया। चेतसिंह की सेनाओं के शक्तिशाली पड़ने के कारण खतरा सन्निकट था। इसलिए उसने अपने विरोधी शहर का त्याग करना उचित समझा और वर्षापूर्ण

20 प्रो० ए० एस० आल्टेकर — 'हिस्ट्री ऑफ बनारस' पृष्ठ-६४

21 वही— पृष्ठ-६४

रात्रि के अधेरे में भाग गया।²² वह और उसके सहयोगी रातभर तीव्र गति से चलने के कारण प्रातःकाल चुनार पहुँच गये। जब अगले दिन उसके जाने का समाचार फैला तो चेतसिंह की सेनाओं ने वारेन हैस्टिंग्स का मुख्यालय लूट लिया और उसके सहयोगी और सहायकों को बन्दी बना लिया। किन्तु सेनाओं की विजय से उद्देश्य की पूर्ति नहीं हो सकी। अंग्रेजों का विरोध करने से कुछ नहीं होगा—यह समझ कर उसने अन्ततः अंग्रेजों के विरुद्ध शरण प्राप्त करने के लिए महादजी सिंधिया के पास जाना निश्चित किया। शीघ्र ही सैनिक रसद मिल जाने से अंग्रेजों ने बिना किसी कठिनाई के रामनगर और लतीफपुर के किलों पर अधिकार कर लिया जब कि चेतसिंह जा चुका था। हैस्टिंग्स के बनारस निवास काल में महीप नारायण सिंह ने हैस्टिंग्स से गुप्त याचना की थी और तदनुसार हैस्टिंग्स ने ४० लाख रु० वार्षिक राजस्व लेकर उसे चेतसिंह का उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया। इस प्रकार मागा गया राजस्व १७८२ में ४० लाख हो गया।²³ गवर्नर जनरल वारेन हैस्टिंग्स का व्यवहार राजा चेतसिंह के साथ वास्तव में निर्दयतापूर्ण एवं उत्पीडक था। इस ऐतिहासिक झलक की पृष्ठभूमि से परिचित होने के साथ ही उस सूक्ष्मता से अवगत हर व्यक्ति को यह समझने में जरा भी देर न लगेगी कि वास्तव में इस सन्देहास्पद बात की वास्तविकता क्या है।²⁴ इन्हीं तथ्यों को देखते हुए ग्रे का कथन था कि “हैस्टिंग्स द्वारा किसी क्षण प्रकट की गयी राय उस क्षण विशेष के बाद ही महत्वहीन हो जाया करती थी।”²⁵ यह प्रश्न अत्यन्त

22 वही — पृष्ठ-६५

23 वही— पृष्ठ —६५

24 डॉक्टर जे० एल० — वारेन हैस्टिंग्स ए बायोग्राफी— पृष्ठ-६

25 हिस्ट्री ऑफ ट्रायल आफ वारेन हैस्टिंग्स भाग (१) पृष्ठ ३२०-३२१

विचारणीय है तथा इस बात का प्रत्युत्तर प्राप्त करने के लिए तीन मुख्य बातों का मनन आवश्यक है कि (अ) राजा चेतसिह एक जमींदार की स्थिति रखता था अथवा राजा की। (ब) क्या वह अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोही था, (स) हैस्टिंग्स द्वारा अत्यधिक कर लगाना क्या न्याय सगत था।²⁶

यद्यपि चेतसिह एक जमींदार की हैसियत रखता था किन्तु उसे राजा से कम सम्मान प्राप्त नहीं था। यह भी सत्य है कि कम्पनी से उसकी मित्रता थी, साथ ही साथ उसे कम्पनी का संरक्षण भी प्राप्त था।²⁷ जहाँ तक राजा और जमींदार शब्द के सम्बोधन और उसके पद तथा प्रतिष्ठा की बात है यह बात हैस्टिंग्स की बातों से स्पष्ट है कि हैस्टिंग्स चेतसिह को राजा के रूप में ही स्वीकार करता था। एक स्थल पर वारेन हैस्टिंग्स ने कहा था कि, “ बनारस प्रान्त अवध और बिहार का सीमान्त प्रान्त है, इसलिए बनारस के राजा और कम्पनी के बीच मैत्रीपूर्ण व्यवहार अथवा मित्रवत् सम्बन्ध का विशेष महत्व है। ऐसी परिस्थिति में बनारस के राजा और कम्पनी को स्थिर सम्बन्ध रखना चाहिए।²⁸ अंग्रेजी शब्द (ally) जो बनारस के राजा और कम्पनी के सम्बन्ध की गहराई पर प्रकाश डालता है, तथा जो इस सन्दर्भ में प्रयुक्त हुआ है— यह शब्द विशेष किसी राष्ट्र या किसी ज़मींदार जमींदार या साधारण लोगों के लिए नहीं प्रयुक्त होता है। १७७५ के कौंसिल के वक्तव्य में हैस्टिंग्स ने सकेत किया था कि

²⁶ करसपान्डेन्स ऑफ़ दी एजेन्ट टू दी गर्वनर जनरल ऐट बनारस अप्रैल १२, १३, (१८१४)

पृष्ठ— १५७ — १५८

²⁷ हिस्ट्री आफ़ ट्रायल' भाग (१) पृष्ठ — १८

²⁸ होम पब्लिक कन्सलटेशन लेटर फ़्रॉम कोर्ट, २८ अगस्त १७८२ भाग २, पैरा—४७ पृष्ठ—१४६

चेतसिंह को स्वतन्त्र रखने की मेरी इच्छा है क्योंकि भारत में पराधीनता के साथ हजारों बुराइयों जुड़ी हुई हैं।²⁹ वारेन हैस्टिंग्स ने यह भी कहा था कि यदि राजा अपने देय के प्रति स्वामिभक्त सिद्ध होगा, अपनी सरकार के प्रति आज्ञापालक सिद्ध होगा, तो उससे अतिरिक्त माँग नहीं की जायेगी। उसके साथ ही साथ व्यक्तिगत रूप से उसके अधिकारों में कोई हस्तक्षेप नहीं किया जायेगा।³⁰ हैस्टिंग्स ने इस बात पर भी जोर दिया था कि चेतसिंह कम्पनी को किराया देता था, प्रतिज्ञाबद्ध धनराशि नहीं—अतः उसकी स्थिति एक जमींदार की है किन्तु कहीं-कहीं उसे उसने स्वयं राजा की स्थिति में स्वीकार किया। दृष्टान्त के रूप में १७७५ में हैस्टिंग्स ने यह प्रस्ताव रखा कि चेतसिंह अपना राजस्व कलकत्ता में देगा, बनारस में नहीं क्योंकि यह प्रस्ताव राजा की स्वतन्त्र स्थिति पर प्रभावहीन होगा।³¹ इससे यह स्पष्ट होता है कि चेतसिंह को एक राजा के रूप में माना जाता था और जमींदार के पद का प्रयोग केवल वैधानिक था। चेतसिंह वास्तव में अंग्रेज शासकों के विरुद्ध क्रान्तिकारी था—यह प्रश्न भी चेतसिंह और वारेन हैस्टिंग्स के बीच उत्पन्न हुए सम्बन्धों की दोषयुक्त व्याख्या है। यद्यपि हैस्टिंग्स ने अपने कलापो के निमित्त राजा को दोषी एवं क्रान्तिकारी लक्ष्यों से युक्त माना है। उसका स्पष्ट कथन यह है कि राजा ने अमुक धृष्टता स्वयं अपनी इच्छा से की है। उसने क्रान्ति को पूर्व नियोजित भी माना है।³² समय की गति को प्रतिकूलता प्रदान करने का

29 स्पीचेज ऑफ एडवर्ड वर्क ऑन वारेन हैस्टिंग्स जिल्द २, भाग २ पृष्ठ २२२ ४७ पृष्ठ — १४६

30 होम पब्लिक लेटर्स फ्रॉम कोर्ट, अगस्त २८, १७८२, पैरा ४७ पृष्ठ १४६

31 कॉमन्स कमिटी रिपोर्ट ऑफ ईस्ट इन्डिया कम्पनी जिल्द—५, पृष्ठ—६१८, ६१९

32 वर्क— पूर्व उद्धृत, पृष्ठ २५८, २५९

कार्य कुछ सूचनाओं एवं अफवाहों ने किया। जब हैस्टिंग्स तक भ्रम युक्त यह सूचना पहुँची कि राजा चेतसिंह मराठों से गुप्त वार्तालाप कर रहा है तो उसके विश्वास को और दृढ़ता प्राप्त हुई।³³ कोलब्रुक कोमेक्स ने राजा की निन्दा इस आधार पर की कि उसने शर्त का उल्लंघन किया है। उसने यह भी स्पष्ट किया कि राजा अपनी सीमा के अन्तर्गत कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उत्तरदायी था, साथ ही साथ उससे बचनबद्ध धनराशि की आशा की जाती थी। किन्तु वास्तव में राजा ने यह दोनों कार्य नहीं सम्पन्न किया था। यह भी कहा गया है कि बनारस में होने वाले प्रतिदिन के कत्ल, डकैती तथा खुले अपराधों का एकमात्र कारण स्वयं राजा ही है। उसके ही कारण अंग्रेजी सरकार पर तरह-तरह के आक्षेप किये जा रहे हैं। व्यक्तिगत रूप से राजा के ऊपर यह भी आरोप लगाया गया कि उसने मैत्री एवं स्वामिभक्ति दोनों के विरुद्ध व्यवहार किया है।³⁴ जब राजा के बन्दी बनाये जाने की सूचना उसके महल रामनगर में उसकी सेना को मिली तो सेना क्रुद्ध हो गई और एक बड़ी संख्या में सेना के जवानों ने शस्त्रों से लैस होकर नदी को पार किया और अचानक ब्रिटिश सेना की टुकड़ियों पर आक्रमण कर दिया। चूँकि कम्पनी के सैनिक शस्त्रों से लैस नहीं थे इसलिए कोई प्रतिरोध न कर सके।³⁵

जहाँ एक ओर इस प्रकार की घटनाएँ घटित हुईं, वहीं दूसरी ओर चेतसिंह ने हैस्टिंग्स के सम्मान को रखने के लिए १२ अगस्त को उसके

³³ वारेन हैस्टिंग्स—पूर्व उद्धृत पृष्ठ—६

³⁴ सीक्रेट सेलेक्टेड कमेटी रिपोर्ट, सितम्बर ४, १७८१ जिल्द—३ पृष्ठ ७८३

³⁵ महादजी सिन्डे हैकी केज्ड पैट्रन न०—१२७ पैरा—२ न०—११५

बक्सर सीमा क्षेत्र में पहुँचने पर उसका भव्य स्वागत किया और उसकी गोद में अपनी पगड़ी तक उतार कर इस आशा से रख दिया कि उसका आक्रोश कुछ कम हो जाय किन्तु राजा का सरल स्वभाव भी हैस्टिंग्स को सन्तुष्ट एवं प्रसन्न न कर सका।³⁶

उपरोक्त तथ्यों से यह स्पष्ट है कि प्रारम्भ में वारेन हैस्टिंग्स के प्रति चेतसिंह बहुत ही स्वामिभक्त, वफादार और सहृदय था, लेकिन हैस्टिंग्स के कपटपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण अपने सम्मान की रक्षा के लिए उसे विद्रोही बनना पड़ा। लेकिन वह स्वदेशी शासकों से समर्थन न प्राप्त कर सका था। अतः वह अपने प्रयास में असफल रहा।

हैस्टिंग्स द्वारा राजा पर असीमित कर लगाना न्यायसंगत था अथवा नहीं? इस प्रश्न पर ग्रे ने अपने विचार व्यक्त करते हुए दो बातों को स्पष्ट किया है। प्रथम, हैस्टिंग्स द्वारा चेतसिंह से की गई मांग उस मौलिक सधि के प्रतिकूल थी, जो राजा और कम्पनी के बीच हुई थी। द्वितीय यह द्वेष एवं भ्रष्टाचार का प्रभाव था।³⁷ इन बातों की पुष्टि मैकाले के भी विचारों से होती है। उसने स्पष्ट रूप से यह कहा है कि इस प्रकार का निर्णय मात्र अपमानित करने के उद्देश्य से ही हैस्टिंग्स ने लिया था। “चेतसिंह को लूटने एवं उसे युद्ध में बाँधने के लिए वह दृढ़ प्रतिज्ञा था।³⁸ चेतसिंह और वारेन हैस्टिंग्स के बीच किसी भी प्रकार का गठबन्धन क्यों था तथा राजा

³⁶ ट्राटर—पूर्व उद्धृत, पृष्ठ—२५६

³⁷ वर्क—पूर्व उद्धृत, पृष्ठ—२५६

³⁸ फॉरेस्ट—‘सेलेक्शन फ्रॉम लेटर्स डिस्पेचेज ऐण्ड अदर स्टेट पेपर्स इन दी फॉरेन डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इन्डिया। जिल्ड I (पृष्ठ—२२०)

चेतसिंह पर वारेन हैस्टिंग्स ने एक सीमित कृपा क्यो की थी— इसको वारेन हैस्टिंग्स ने स्वयं ही व्यक्त करते हुए कहा है कि उसका देश हमारी कम्पनी के लिए एक प्रबल आड है तथा उसके लिए हमें कुछ व्यय नहीं करना पड़ता, साथ ही साथ मुझे यह विश्वास रहता है कि जब कभी आवश्यकता पड़ी मुझे सहायता प्राप्त होगी। हैस्टिंग्स एक ऐसे सरक्षण एवं मध्यस्थता का आकांक्षी था जो उसे चेतसिंह के माध्यम से ही प्राप्त हो सकता था क्योंकि अवध के नवाब और राजा में पैतृक बैर के बीज सदैव से पनपे हुए थे। वारेन हैस्टिंग्स यह अच्छी तरह जानता था कि चेतसिंह नवाब के लिए अदम्य है।³⁹

हैस्टिंग्स द्वारा लगाया गया असीमित कर उपरोक्त तथ्यों के आधार पर न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता। क्योंकि राजस्व एकत्रित करने का कार्य महीपनारायण सिंह को सौंप देने पर भी अंग्रेजों ने बनारस में न्यायाधीश नियुक्त करने का अधिकार अपने पास रखा। महीप नारायण सिंह अल्पवयस्क था। यह तर्क देकर कि राजस्व—संग्रह का कार्य सतोषप्रद नहीं हो रहा है, लार्ड कार्नवालिस की सरकार ने उसे यह कार्य अंग्रेजों को सौंप देने के लिए विवश कर दिया।⁴⁰ महीप नारायण ने इस प्रस्ताव का विरोध करने का प्रयास किया किन्तु अन्ततः उसे स्वीकार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। १७६४ में उसने राजस्व और न्याय प्रशासन अंग्रेजों को समर्पित कर दिया और इस प्रकार राजकुमार का स्तर उसने खो दिया। १७६४ जुलाई में डकन ने सूचना दी कि राजा बनारस अंग्रेजी प्रशासनिक

³⁹ सम्पूर्णानन्द— चेतसिंह और काशी का विद्रोह—पृष्ठ—२३

⁴⁰ प्रो० ए० एस० अल्टेकर—‘हिस्ट्री ऑफ बनारस’ पृष्ठ—६६

ढग लागू करने के लिए सहमत है, किन्तु शर्त यह है कि उसके पारिवारिक जिले और सम्पत्ति पूर्ववत् व्यवस्था में रहे। अक्टूबर माह में स्वीकार पत्र पर हस्ताक्षर हो गये और बगाल, बिहार तथा उड़ीसा के ढग का नया प्रशासन प्रारम्भ हुआ।⁴¹ इस प्रकार १७७५ में बनारस राज्य का प्रशासन बगाल की तरह हो गया। एक न्यायाधीश और परीक्षक बनारस, मिर्जापुर, गाजीपुर, जौनपुर में नियुक्त किये गये और एक जिलाधीश पूरे प्रान्त के लिए नियुक्त किया गया। प्रथम जिलाधीश श्री एलेक्जेंडर डकन थे जिन्होंने डकन रेजीडेन्ट के अनुसार कार्य प्रारम्भ किया। १७६६ तक यही व्यवस्था बनी रही और कार्य होता रहा। सैमुअल डेविस बनारस का प्रथम न्यायाधीश और मैजिस्ट्रेट, कोलब्रुक मिर्जापुर के, जानरैली जौनपुर और जैकब राइटर गाजीपुर के थे। रैली एक कनिष्ठ अधिकारी थे, इसलिए उन्होंने अल्पकाल तक ही कार्य किया उनका स्थान ए० वेलेन्ड ने लिया। १८०० में गाजीपुर में जज का पद समाप्त कर दिया गया और यह क्षेत्र जौनपुर, एव मिर्जापुर के जजों में विभक्त कर दिया गया।⁴² इस प्रकार क्रमशः ब्रिटिश शासन द्वारा बनारस मडल के निकट के जनपदों को भी अधिकृत कर लेने का प्रयास होने लगा। उनके प्रभाव में १८०० में सर्वप्रथम जौनपुर, तत्पश्चात् गाजीपुर और फिर मिर्जापुर भी आ गया।⁴³

41 डेवर डगलस—‘ए हैन्डबुक ऑफ दी इंगलिश प्रीम्यूटनी रेकार्ड्स पृष्ठ—२६०

42 वही— पृष्ठ २६१

43 डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जौनपुर पृष्ठ—३०३, एव इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इन्डिया जिल्द १४, पृष्ठ ७५

उद्योग एवं व्यवसाय

उद्योग एवं व्यवसाय

किसी भी शासन की आधारशिला उसके राजनीतिक स्थायित्व एवं आर्थिक सुदृढता पर आधारित होती है। किन्तु इन मूल लक्षणों से परे मुगल शासन काल में शासनात्मक सकट और आर्थिक अस्थिरता ने भारत में उनके पतन का मार्ग प्रशस्त किया।¹ मुख्यरूप से यह कहना अनुचित न होगा कि मध्यकालीन समाज एवं उसकी सम्पूर्ण उत्पन्न होने वाली परिस्थितियाँ ही इसके उत्तरदायित्व के कारण के मूल में थी। इस सन्दर्भ में समस्या के समाधान हेतु मात्र शहशाह अकबर और शाहजहाँ द्वारा ही प्रयास किया गया। औरंगजेब के शासनकाल में जटिलताएँ उत्तरोत्तर बढ़ती ही गईं।²

उद्योग और व्यवसाय के क्षेत्र में जिन लोकप्रिय वस्तुओं को मुगलशासन में प्रश्रय दिया गया था उन्हीं को ईस्ट इण्डिया कम्पनी ने भी न्यूनाधिक रूप में अपनाकर अपने उद्योग और व्यवसाय का मार्ग प्रशस्त किया।³

पूर्वी उत्तर प्रदेश में अधिकांश शहरी उद्योग ग्रामीण क्षेत्र के उत्पादित कच्चे माल पर आधारित थे। अतः यहाँ के उद्योग और व्यवसाय को शहरी एवं ग्रामीण स्तर पर विभाजित करना उचित प्रतीत होता है।

1 सतीशचन्द्र—उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास पृष्ठ—२३

2 मोरलैण्ड—मुस्लिम भारत की ग्रामीण व्यवस्था पृष्ठ २०३—२०७

3 वही—पृष्ठ २०३—२०७

पूर्वी उत्तर प्रदेश के उद्योग और व्यवसाय को हम दो रूप में विभाजित कर सकते हैं— (१) कृषि पर आधारित उद्योग (२) सामान्य उद्योग।

पूर्वी उत्तर प्रदेश में उक्त दोनों प्रकार के उद्योग का प्रचलन था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में मुख्यरूप से नील, अफीम, नमक, शोरा, रेशमी, तथा सूतीवस्त्र के उद्योग के अतिरिक्त धातु उद्योग, सोने चाँदी के तार खींचना, चादी के हौदे, कुर्सियाँ, पालकी, मूर्तियाँ, फूलदान, थाल तथा अन्य घरेलू कार्य के निमित्त उपयोग में आने वाले बर्तनों का निर्माण तथा छोटे उद्योग में इत्र, केवड़ाजल, गुलाबजल, आदि प्रचलित थे। कालीन आदि के व्यापार भी प्रचलन में थे।⁴

नील

नील की खेती भारत वर्ष में प्राचीनकाल से ही होती आयी है। १७वीं शताब्दी तक नील ही निर्यात के लिए ईस्ट इण्डिया कम्पनी की प्रमुख वस्तु थी। किन्तु बाद में वेस्ट इण्डीज में नील का उत्पादन होने से भारत में नील का उत्पादन कम हो गया और १६२४ में ब्रिटिश बाजारों में इसकी माँग बिल्कुल बन्द हो गई। १८वीं शताब्दी के मध्य में वेस्ट इण्डीज में भी नील का उत्पादन बन्द हो जाने के कारण इंग्लैण्ड अमरीका से नील मगाने लगा। स्वतन्त्रता संग्राम छिड़ जाने के कारण अमरीका ने नील की आपूर्ति बन्द कर दिया जिसके परिणामस्वरूप भारत में नील की खेती पुनः बृहद पैमाने पर होने लगी। योरोप के लोगों ने यहाँ के रैयत से 'खेती

4 के० के० दत्ता—सर्वे आफ इण्डियन सोशल लाइफ एण्ड एकोनामिक कन्डीशन इन एट्टीन सेन्चुरी (१७०७—१८०३)। पृष्ठ—६०

समझौता' कर लिया जिसका प्रमुख ठेकेदार जे० टी० फ्रिकशाप १७८४ तक रहा।⁵

नील के उत्पादको ने धीरे-धीरे नील की महत्ता को अनुभव किया। १७८७ में सर्जन गिल्प्रिस्ट जो कम्पनी की नौकरी में थे तथा चार्ट्स ने अपने पदों से त्यागपत्र देकर गाजीपुर के निकट स्वयं नील की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। इससे पूर्व अंग्रेज अपने उपयोग के लिए अल्पमात्रा में ही नील का उत्पादन करते थे। उपयोग के उपरान्त बचे हुए नील को सवा दो रुपये या तीन रुपये तक प्रति सेर की दर से बेच दिया करते थे। गिल्प्रिस्ट ने नील बनाने की कला वेस्ट इण्डोज से सीखा था।⁶ शीघ्र ही नील उत्पादको के मध्य झगडा व्याप्त हो गया। १७८६ में गाजीपुर के कासिम ने डकन से इस आशय की शिकायत किया कि गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स उन्हें नील के उत्पादन हेतु अधिकाधिक भूमि देने के लिए बाध्य कर रहे हैं। स्थानीय नील उत्पादको के मध्य व्याप्त झगडे को देखते हुए डकन ने कासिम को उसकी भूमि लौटा दिये जाने का आदेश जारी किया। किन्तु गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स ने भूमि लौटाने से होने वाली क्षति की ओर डकन का ध्यान आकर्षित करते हुए यह शिकायत किया कि कासिम ने जमींदार

5 के० के० दत्ता— सर्वे आफ इण्डियाज सोशल लाइफ एण्ड एकोनामिक कन्डीशन इन एट्टीन सेन्चुरी (१७०७—१८१३)। पृष्ठ—६०

एव एस०एन०सिन्हा 'सूबा आफ इलाहाबाद अण्डर दी ग्रेट मुगल्स' (शोध ग्रन्थ) पृष्ठ—१४४ मनुची खड (२) पृष्ठ ४२४,

6 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स—१४ सितम्बर १७८६

विशेष सदर्भ यह है कि इस क्षेत्र के लाभप्रद उद्योग को देखते हुए ब्रिटिश अधिकारी भी अत्यधिक लाभ लेने के दृष्टिकोण से स्वयं भी व्यापार से जुड गये। उदाहरणार्थ गिल्प्रिस्ट, चार्ट्स, फ्रान्सिस फोक्स, थामस, ग्राहम (१७७०—८०) विलियम माखन (१७८१—८३) जेम्स ग्रान्ट (१७८६—८७) (के०पी०मिश्रा—१०४) बनारस आफेयर्स—(१७८८—१६१०) द्वारा जी० एन० सालीटोर जिल्द (१) पृष्ठ—१५२—१५३

को अधिक जमा पर पट्टा लिखा है जिससे उन्हें ४५५२/— का घाटा होने की सम्भावना थी। कासिम का कहना था कि जमीदार ने स्वेच्छा से भूमि लिया है। डकन द्वारा निरीक्षण किये जाने पर यह ज्ञात हुआ कि कासिम ने नील की खेती के लगान की दर नहीं अदा किया है। उसने हिसाब लगाया कि लगान की औसत दर चार रुपये बारह आना होना चाहिए।⁷ गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स डकन के इस फैसले से सन्तुष्ट नहीं थे। उन्होंने फैसले पर पुन विचार किये जाने हेतु आवेदन किया जिसे सरकार के पास अग्रसारित कर दिया गया। उन्हें आदेश दिया गया कि यदि ताल्लुका उनके पास अब भी हो तो उन्हें वे छोड़ दे। बनारस मण्डल में नील के उत्पादन को बढ़ाने तथा उससे कम्पनी तथा देश को लाभ पहुंचाने के लिए कुछ नियमों की आवश्यकता हुई। २७ जनवरी १७६० को योरोपियन उत्पादकों को यहा रखने का आदेश हुआ। ऐसे रैयतों को अग्रिम राशि दिये जाने का आदेश हुआ जो नील के उत्पादन और उसकी आपूर्ति के लिए तैयार थे। इसकी दर बिहार में प्रचलित दर के अनुसार रखी गई। सरकारी आदेश की एक प्रति गिल्प्रिस्ट और चार्ट्स के पास भेज दी गई जिसे दोनों ने ही स्वीकार किया।⁸ बाद में अन्य योरोपियन भी मण्डल में नील उत्पादकों के रूप में बस गये। अनेक ने अपनी बुद्धि और चाल से कार्य प्रारम्भ भी कर दिया। गाजीपुर जिले में उनसे कुछ झगडा हो गया। उदाहरणार्थ मिस्टर पुघ लेखनासार परगना की सरहद पर बस गये और सेनगढ के जमीदार से उनका तनाव हो गया। उत्पादन के लिए उन्होंने

7 बनारस रेजीडेन्सी करसपाडेन्स-१४ सितम्बर १७८६-पृष्ठ-३६५-३६६

8 वही- पृष्ठ-४४२-४४३

एक बड़ी भूमि प्राप्त कर लिया। इस प्रकार के अनेक झगड़े गाजीपुर में होते रहे।⁹

विभिन्न झगड़ों को दृष्टि में रखते हुए गवर्नर द्वारा योरोपियनों को यह आदेश दिया गया कि मार्च १७६४ में वे कोई भूमि सम्पत्ति स्वरूप ले सकते हैं। यह भूमि मात्र नील उत्पादन हेतु पर्याप्त होनी चाहिए। आवश्यकता से अधिक भूमि वे लीज पर नहीं ले सकते। चूँकि इस आदेश का नील उत्पादकों पर अच्छा प्रभाव नहीं पड़ा अतः उन्होंने डकन को एक प्रार्थनापत्र प्रेषित किया जिसे अपनी टिप्पणी सहित डकन ने गवर्नर को प्रेषित कर दिया।¹⁰

शीघ्र निरीक्षण की दृष्टि से डकन ने कानूनगो के नाम एक आदेशपत्र जारी किया जिसके अनुसार दस दिन के अन्दर वर्तमान तथा भविष्य की दशाओं की लिखित रिपोर्ट प्रस्तुत करना था। रिपोर्ट के आधार पर डकन ने १० मई १७६४ को लिखे गये अपने पत्र में सरकार से कई प्रस्तावों को अध्यादेश की धारा में सम्मिलित कर लिये जाने की सिफारिश किया। डकन की राय में नील की खेती देश की उन्नति के लिए तो आवश्यक थी ही, इसके साथ ही साथ बेकार पड़ी भूमि का उपयोग कृषि कार्य में हो सकता था। गरीब, मजदूर हरवाहे तथा घसियारे इस कार्य में लगाये जा सकते थे।¹¹

9 वही—पृष्ठ ५१७—५१८ एवं ५१९

10 वही—पृष्ठ—५१९

11 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स, मई १७६४—पृष्ठ—६७—१२६

डकन ने यह अनुभव किया कि नील की खेती कुछ मामलो मे कुछ लोगो के लिए लाभप्रद थी। यह निश्चितरूप से सत्य है कि तत्कालीन जमींदार और किसान अपनी हक की भूमि देने को बाध्य ही नहीं हुए वरन अग्रेजो द्वारा लिए जाने वाले लगान को भी स्वीकार कर लिया।¹²

डकन नील उत्पादन की बुराइयो से भी सतर्क था। इससे सरथा को भी काफी क्षति पहुँची और उसने सुधार करना स्वीकार किया। डकन के अनुसार निम्नलिखित बुराइया प्रमुख थी—

(१) उनके मकानो को हटाने के लिए, दूसरा स्थान ढूँढने के लिए और समय—समय पर योरोपियन नील उत्पादको के नौकरो द्वारा जबरन उन्हे दबाये जाने के लिए था। भूसा देना भी रोक दिया गया था क्योकि यह बाजार से लाया जाता था।

(२) मालिक की आज्ञा के बिना पेड काट लिये जाते थे और उनको काटे गये पेड का उचित मूल्य भी नहीं दिया जाता था।

उक्त कठिनाइयो को दूर करने के उद्देश्य से डकन ने कुछ नियम बनाकर स्वीकृति हेतु सरकार के पास प्रेषित किया। नियमानुसार कोई भी भूमि आमिल, जमींदार या किसान द्वारा जिसे रेजीडेन्ट की स्वीकृति न प्राप्त होगी, नील की खेती के लिए देना उचित न होगा। रेजीडेन्ट को सख्त आदेश था कि वह स्वीकृति तभी प्रदान करे जबकि

¹² वही—पृष्ठ १७६—१८१

जमीदार स्वयं कारस्त से और खेतवाले का वसीयतनामा लाकर सतुष्ट कर दे कि सम्बन्धितभूमि पर नील की खेती होती है।¹³

यूरोपीय नील उत्पादकों के नौकर यदि किसानों से भूसा छीनते थे तो उन्हें फौजदारी अदालत में जाना पड़ता था। यदि वे अपने मालिक के लिए किसी कारीगर मजदूर को जबरन ले जाते थे तो उन्हें दण्ड का भागी होना पड़ता था। जिले के आमील द्वारा स्वीकृति मिलने और मूल्य निर्धारित होने पर ही कोई यूरोपीय नील उत्पादक पेड खरीद सकता था।¹⁴

डकन ने यह सिफारिश किया कि रेजीडेन्ट की आदालत में विभिन्न शिकायतों से सम्बन्धित प्रश्नों का उत्तर देने के लिए उत्पादक अच्छे और योग्य वकीलों को ही रखें।

यूरोपीय उत्पादकों के आवेदन तथा डकन के सुझाओं पर विचारोपरान्त गर्वनर जनरल ने २३ मई १७६४ को नील की खेती के बाबत कुछ अध्यादेश निकाले जिसके अनुसार रेजीडेन्ट को निर्देश दिया गया कि नील उत्पादकों को हर प्रकार का प्रोत्साहन प्रदान किया जाये जिससे वे रैयत से बीघा के आधार पर ठेका कर सकें। मेहदी अली खॉ को सूचित किया गया कि वे आमिल के रूप में किसी रैयत को न तो मजबूर करेंगे और न ही कोई अनुचित अधिकार जमायेंगे। यह भी सूचित किया गया कि यदि रैयत नील की खेती करे और उत्पादकों को दे दे (जैसा बंगाल में हो रहा था।) तो सरकार सतुष्ट रहेगी। यूरोपीयन उत्पादकों को प्रारम्भ

13 वही—पृष्ठ—१८२—१८३

14 वही— पृष्ठ—१८४—१८५

में खर्च के लिए अग्रिम धनराशि देना पड़ता था।¹⁵ उन्हें यह भी स्पष्ट किया गया कि रैयत से ठेका द्वारा फसल लेने में जो विलम्ब होता है उसके लिए सरकार का उत्तरादाइत्व न होगा।

डकन के सुझाओ के अतिरिक्त सरकार ने अध्यादेश निकाला जिसके अनुसार —

(१) वर्तमान में नील उत्पादन की ऐसी समस्त भूमि जो योरोपीयन उत्पादको द्वारा मार्च १७६४ के पहले ले ली गई है उनके अधिकार में उनकी मृत्यु तक रहेगी।

(२) लीज पर योरोपियनो द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ली गई भूमि ७ मार्च १७६४ से व्यर्थ समझी जायेगी और ऐसी लीज का विक्रय कर दिया जायेगा।

(३) विगत वर्ष का समझौता समाप्त होने पर कोई भी योरोपियन न तो अपने नाम से और न ही दूसरे के नाम से प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष किसी भी रूप में भूमि अपने पास रख सकता है। यह नियम ५० बीघा से अधिक के लिए नहीं लागू था।

उक्त बातों से ऐसा स्पष्ट होता है कि सरकार योरोपियन उत्पादको द्वारा नील के उत्पादन के विरोध में नहीं थी। किन्तु वह ठेके की प्रथा को कम करने के पक्ष में थी जिससे नील उत्पादक किसान एवं कर्मचारी के बीच झगडा न हो।¹⁶ प्रत्येक योरोपियन को इस अध्यादेश पर हस्ताक्षर

¹⁵ वही—पृष्ठ—१८६, १८७, २३६

¹⁶ वही—२३ मई १७६४—पृष्ठ—३२५ (जून १७६४ के प्रोसीडिंग में उपलब्ध है।)

करके इसका पालन करना पड़ता था। इस अध्यादेश का उल्लघन करने वाले को प्रथम बार ५००/- जुर्माना स्वरूप देना पड़ता था और यदि वह दूसरा उल्लघन करता था तो उसे कलकत्ता भेज दिया जाता था।¹⁷

१२ जुलाई १७६४ को रेजीडेन्ट ने एक नोटिस निकाल कर यह घोषित किया कि एक शर्त पर योरोपियन सरकार के पट्टेदारों से नील बनाने के काम का ठेका कर सकता है। इस नोटिस में मुख्यरूप से यह दर्शाया गया था कि मात्र सरकार के पट्टेदार ही इस प्रकार का ठेका करने के लिए योग्य हैं। पट्टेदार रैयत की भूमि को बिना उसकी स्वीकृति के सरकार को नहीं दे सकते थे। इस प्रकार एक कठोर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। चूँकि इसमें अधिक कठिनाई थी अतः डकन को शर्तों में संशोधन करना पड़ा। डकन ने २६ जुलाई १७६४ को सरकार को लिखा कि मैंने उत्पादकों को आदेश दिया है कि वे पट्टेदार की स्वीकृति के बिना ही अपने ठेकों को समाप्त करें।¹⁸

२१ जून १७६५ को रेजीडेन्ट ने कुछ और धाराएँ जो १७६५ के ३३वें अध्यादेश में सम्मिलित की गई थी, सरकार को भेजा। उसने परामर्श दिया कि कोई भी योरोपियन एक दूसरे के बहुत निकट काम न शुरू करे और न ही झगड़े की भूमि पर दूसरे के साथ नील का उत्पादन करे।¹⁹ १२ जुलाई १७६५ में रेजीडेन्ट ने यह भी परामर्श दिया कि योरोपियन को ऋण के रूप में अग्रिम राशि रैयत के लिए मागने की मनाही हो क्योंकि इससे जमींदार पट्टेदार लालच में आ जाते हैं और उन्हें अपनी भूमि से वंचित

17 वही।

18 वही।

19 वही—जून १७६६ पृष्ठ—३३३

होना पड़ता है। एक ही पट्टा रखने वाले पट्टेदारों के बीच होड़ लग जाती है और झगड़ा शुरू हो जाता है। इसके अनेक उदाहरण प्रस्तुत किये गये।²⁰

उक्त परामर्श और सुझाव पर अपनी स्वीकृति देते हुए रेजीडेन्ट ने उन्हें अध्यादेशों में सम्मिलित कर लिया। इस प्रकार नील की धारा से सम्बन्धित डकन की चिन्ता दूर हुई।²¹

नवाब वजीर के देश से आने वाली सम्पूर्ण नील पर १७६७ में १५ प्रतिशत कर लगा दिया गया। बनारस के टैक्स कलेक्टर को प्रति माह अपनी लिखित सूचना बनारस मण्डल में भेजनी पड़ती थी। कुछ कार्यवाही जो कम्पनी सरकार ने नील उत्पादकों के लिए किया वह व्यर्थ और प्रभावहीन सिद्ध हुए। नील उत्पादकों के कुछ भारतीय नौकरों ने बहुत साधन एकत्रित कर लिया। नील उद्योग किसी भी प्रकार से साधारण लोगों के हितार्थ नहीं था। किन्तु इंग्लैंड के लिए एक आर्थिक लाभ का स्रोत अवश्य था।²²

अवध सूबा में नील का उद्योग बड़ी मात्रा में होता था। सरकार लखनऊ ने नील उत्पादन में ख्याति अर्जित किया था। तडक भडक पसंद और सफेद कपड़े पहनने वाले परिवार के लोग नील का विशेष उपयोग करते थे। खैराबाद से भी नील विदेशों को निर्यात किया जाता था। प्रायः अवध सूबा से खरीदा हुआ नील अहमदाबाद ले जाया जाता था। इसी क्रम

20 वही—पृष्ठ—३३३—३३४

21 वही—जुलाई १७६४—पृष्ठ ३३७, १२१, १२२

22 बंगाल रेग्यूलेशन—(१) एपेन्डिक्स—पृष्ठ—३७२

मे यह सन्दर्भ भी आवश्यक है कि प्राकृतिक विपदा के कारण वियना में नील की खेती क्षतिग्रस्त हो गई थी जिसके कारण अंग्रेज व्यापारियों को नील के लिए अवध पर आश्रित होना पड़ा।²³

प्राचीन पीढ़ी की समाप्ति ज्यों-ज्यों होती गई नील की खेती की कला और तकनीक से लोग अनभिज्ञ होते गये। १८वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में मात्र रंगरेज लोग ही इसके जानकार रह गये थे। किन्तु बाद में पुनः एक बार नील उद्योग में वृद्धि हुई।²⁴

अफीम

ऐसा विश्वास किया जाता है कि चीन और भारत में अफीम का प्रचलन अरब वालों द्वारा चलाया गया। भारतवर्ष में अफीम उद्योग पर वाराणसी मण्डल का पूर्ण आधिपत्य था। यही से छोटे-छोटे कारखानों को अग्रिम धनराशि के आधार पर व्यक्तिगत ठेका प्रदान किया जाता था। मुगल साम्राज्य की अवनति के पश्चात् ईस्ट इण्डिया कम्पनी के अन्तर्गत पटना के कार्यकर्त्ताओं एवं अनेक पड़ोस के लोग भी अच्छे प्रकार के अफीम का उत्पादन करने लगे थे तथा व्यक्तिगत लाभ के उद्देश्य से इन्होंने अपना अफीम का व्यापार भी प्रारम्भ कर दिया था। अठारहवीं शताब्दी के मध्यकाल में छोटे कारखानों और योरोपीय कारखानों में अफीम के व्यापार को लेकर स्पर्धा की भावना व्याप्त हो गई। स्पर्धा की इस

23 दी इंगलिश फैक्टरीज (१६५१-५४) पृष्ठ-२२२ इम्पीरियल गजेटियर ऑफ इण्डिया-पृष्ठ-२०-३०४ एवं आर्शीवादी लाल "अवध के प्रथम दो नवाब"- पृष्ठ-२७६ (हिन्दी रूपान्तर)।

24 वही।

भावना के फलस्वरूप अफीम का मूल्य १००/— प्रति मन की दर से बढ़कर १५०/— प्रति मन हो गया।²⁵ वर्ष १७७३ में वारेन हेस्टिंग्स ने अफीम सम्बन्धी सम्पूर्ण, आधिपत्य अपनी सरकार को सौंप दिया। बिहार का सम्पूर्ण उत्पादन कलकत्ता को ३२०/— प्रति पेटी की दर से देने के लिए मीर मुनीर की नियुक्ति की गई। यही मूल्य गाजीपुर में भी प्रति पेटी की दर से निर्धारित किया गया। इतने ही वजन के अफीम की आपूर्ति डचवालो को टैक्स सहित किया जाने लगा।²⁶ वर्ष १७८५ में स्थिति बदल गई और नीलामी के आधार पर सर्वाधिक बोली लगाने वालों का अफीम उद्योग पर आधिपत्य स्थापित हो गया। ६ अप्रैल १७८८ को गवर्नर जनरल की कौंसिल ने मण्डल के सभी कलेक्टरों के पास एक अध्यादेश प्रेषित किया जिसके प्रत्युत्तर में उनसे निम्नलिखित²⁷ बिन्दुओं पर सूचनाओं की अपेक्षा की गई —

(१) ठेके की नीति कृषकों के लिए सुविधाजनक है अथवा नहीं? यदि रैयत को स्वयं उत्पादन की छूट दे दी जाय तो क्या अफीम उत्पादन वाली भूमि द्वारा बढ़ोत्तरी लगान प्राप्त करना सम्भव होगा और इस प्राप्त रकम से प्रत्येक परगना में जमा धनराशि में कितनी वृद्धि हो सकेगी?

(२) क्या रैयत को अफीम उत्पादन की छूट थी? यदि उन्हें अपनी स्वेच्छा से उत्पादन करने की छूट दे दी जाय तो अफीम के गुण और परिणाम पर अध्यादेश का क्या प्रभाव पड़ेगा? अफीम उत्पादन की शर्तों से क्या रैयत दूसरे मण्डल के रैयत की तुलना में सुखी रह सकेगी। यदि

²⁵ *रिपोर्ट आफ दी रायल कमेटी आन ओपियम—१८६४-६५ जिल्द III पृष्ठ ३६

²⁶ वही—पृष्ठ—३७ पॉंचवा रिपोर्ट जिल्द—I—पृष्ठ ४०

²⁷ सेक्सपियर—पूर्व उद्धृत—जिल्द II—पृष्ठ १५७-१५८ एव गिन्च—अरली ट्रेवल्स—पृष्ठ—१४२

उन्हे स्वेच्छा पूर्वक विक्रय की छूट दे दी जाय तो उत्पादन और परिणाम पर क्या प्रभाव पड़ेगा? एजेन्सी के अन्तर्गत उन्हे ठेके से क्या आपत्ति या असुविधा हो सकती है?

(३) यदि ठेके की नीति जारी रही तो रैयत के सुख और बचाव के लिए क्या किसी अन्य अध्यादेश को जारी करने की आवश्यकता होगी ? यदि अफीम का व्यापार सर्वथा खुला छोड़ दिया जाये तो उत्तरी एवं पश्चिमी प्रान्तों को बिहार द्वारा कितनी मात्रा में अफीम की आपूर्ति सम्भव हो सकेगी? देश में ऐसे साधन उपलब्ध होने में कमी या बढ़ोत्तरी की आशंका तो नहीं की जा सकती? यदि कम्पनी प्रारम्भिक नीलामी पर अपना अधिकार हटा लेती है तो क्या छोटी संस्थाएँ जिन्हें आधिपत्य प्राप्त है, असुविधा का अनुभव नहीं करेगी?²⁸

डकन ने रामचन्द्र पंडित को अफीम के क्षेत्र में अनुभवी व्यक्ति समझा और उनके आवश्यक परामर्श से सतुष्ट भी हुए। रामचन्द्र पंडित के परामर्श से यह स्पष्ट हो गया था कि कम्पनी के द्वारा अफीम सम्बन्धी व्यवस्था सुचारु रूप से न चल सकेगी। उन्होंने यह सुझाव दिया था कि अफीम उत्पादकों के लाभ को दृष्टि में रखते हुए बनारस मण्डल में 'प्रतिनिधि' की व्यवस्था की जाय। डकन ने रामचन्द्र पंडित के परामर्श और सुझाव को एक रिपोर्ट के रूप में तैयार करके सरकार के समक्ष प्रस्तुत किया। रामचन्द्र पंडित को ही प्रतिनिधि नियुक्त किया गया। उन्होंने उत्पादकों से पट्टा लिखवाया और उत्पादन हेतु उत्पादकों को अग्रिम

²⁸ वही—पृष्ठ १५७-१५८ तक

धनराशि प्रदान किये जाने की व्यवस्था भी करायी।²⁹ पट्टे द्वारा यह निश्चय किया गया की उत्पादित अफीम ठेकेदार को न देकर सीधे सरकार को दिया जायेगा। जमींदार वर्ग ठेकेदारी व्यवस्था के विरुद्ध था अतः उन्होंने रैयतो को आगाह किया कि यदि अफीम के अतिरिक्त अन्य प्रकार की उपज पर प्रतिबन्ध है तो कृषि कार्य ही न हो। अन्ततः सरकार और रैयत दोनों को ही हानि उठानी पड़ी। सरकार और ठेकेदारों के बीच अफीम देने की व्यवस्था थी अन्यथा ठेकेदारों द्वारा सरकार को जुर्माना देना पड़ता था जिन्हें वे रैयतो को क्षति पहुँचा कर पूर्ण किया करते थे। तौलने वालों की धोकाधड़ी से भी रैयतो को क्षति पहुँचती थी।

इन अनेकानेक कठिनाइयों को दृष्टिगत रखते हुए रामचन्द्र पंडित ने व्यवस्था में व्याप्त त्रुटियों को दूर करने के उद्देश्य से रैयतो का बचाव करते हुए निम्नलिखित सुझाव प्रस्तुत किया।³⁰

(१) कोटेशन के कम मूल्य से संचालित न होकर ठेकेदारों को दिये जाने वाले मूल्य के बराबर ही रैयतो को भी मूल्य दिया जाय।

(२) रैयतो पर पोश्ते की खेती के लिए किसी प्रकार का दबाव न डाला जाय।

(३) रैयत को व्यक्तिगत रूप से किसी व्यक्ति को अफीम बेचने पर रोक लगा दी गई जिससे अफीम की अच्छाई और परिणाम में कमी न आने पाये।

²⁹ वही-१६ जुलाई, पृष्ठ-२५८-२६६-रामचन्द्र पंडित और सरकार के बीच हुई वार्ता जो प्रश्न और विरोध के सदर्थ मेथी उसी का हिन्दी रूपान्तर।

³⁰ वही-पृष्ठ २६६-२६९

रामचन्द्र पंडित ने अफीम की खेती को बढ़ाने के लिए सरकार से एक लाख रुपये अग्रिम धनराशि देने का भी प्रस्ताव किया। रैयतो को यह बता दिया गया कि किसी प्रकार की मिलावट होने पर वे दण्ड के भागी होंगे। तराजू को हाथ से उठाकर तौलने की प्रथा समाप्त करके तराजू को जमीन में गाड़ देने का सुझाव देते हुए तौल की प्रणाली में परिवर्तन का प्रस्ताव रखा गया। रैयतो को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से अफीम का मूल्य १८०/- प्रति पेटी से बढ़ा कर १६०/- प्रति पेटी कर दिया गया। गाजीपुर से अफीम का कारखाना हटा कर बनारस में स्थापित करने का विचार भी प्रस्तावित किया गया। उक्त समस्त सुझावों एवं प्रस्तावों को सरकार द्वारा २१ जनवरी १७८६ में स्वीकार किया गया³¹।

प्रतिनिधि प्रथा को लागू करते हुए भी सरकार ने ठेकेदारी की प्रथा को जारी रखा। यह कार्य मात्र इसलिए किया गया जिससे बनारस मण्डल को अन्य मण्डलों की बराबरी में लाया जा सके। जे० विलियम को ठेके का कार्य सौंपा गया और उन्हें यह निर्देश दिया गया कि वे बनारस में ५०० पेटिया प्रतिवर्ष तैयार कराये। रैयतो को ठेकेदारों द्वारा रुपये को सिक्कों में अग्रिम धनराशि स्वरूप देने को कहा। डकन का विचार था कि यदि रैयतो को और अधिक अफीम उत्पादन करने को कहा जायेगा तो बंगाल और बिहार की भाँति बनारस मण्डल में भी मिलावट का कार्य प्रारम्भ हो जायेगा। ठेकेदारों को ५०/- प्रति पेटी अधिक की धनराशि देने को कहा गया जिससे उनके माध्यम से उत्पादन बढ़ाया जा सके।³² ६

31 वही पृष्ठ-१४३-१४४

32 वही पृष्ठ-७२

नवम्बर १७८६ को एक अध्यादेश जारी किया गया जिसके द्वारा २ १/२ प्रतिशत कर लेकर नवाब वजीर के राज्य से माल बाहर भेजने की व्यवस्था की गई।

ठेकेदारी प्रथा से सम्बन्धित २६ जुलाई १७८६ की २०वीं धारा के शर्त में यह उल्लिखित था कि बगाल और बिहार में यदि कोई रैयत अफीम बेचते हुए पकड़ा गया तो उसे ४/— प्रति सेर की दर से जुर्माना देना होगा तथा उसका सम्पूर्ण अफीम यदि सरकार जब्त नहीं करती तो रैयत को १४/— प्रति सेर की दर से जुर्माना का भुगतान करना होता था। १६ फरवरी १७९० को अफीम के ठेकेदारों ने अपनी कुछ सुविधाओं को सुरक्षित रखने के उद्देश्य से गवर्नर को एक प्रत्यावेदन दिया। एक अध्यादेश इस विषय का पारित किया गया कि यदि कोई अग्रेज नियम के विरुद्ध कार्य करता हुआ पाया गया तो उसे योरप भेज दिया जायेगा। और यदि कोई भारतवासी दोषी पाया गया तो उसे ३७५/— प्रति मन की दर से जुर्माने की धनराशि का भुगतान करना पड़ेगा। रैयतों को इस बात की सुविधा प्रदान की गई कि वे गत वर्ष में बचे हुये अतिरिक्त अफीम का क्रय-विक्रय कर सकते हैं।^{१३}

चूँकि उक्त धाराएँ सरकार की नियमावली में सम्मिलित नहीं थीं अतः रेजीडेन्ट ने निम्नांकित नियम बनाये और गवर्नर द्वारा उनकी स्वीकृति प्राप्त कर लिया—

^{१३} वही—सितम्बर १६, १७८६ पृष्ठ ४४३—४४४

(१) निर्धारित सीमा से अधिक अफीम का विक्रय करने वाले को ४/- प्रति सेर की दर से जुर्माना देना होगा।

(२) यदि रैयत पहले वर्ष के उत्पादन का विक्रय करता था तो उसे ८७५/- प्रति मन की दर से जुर्माना देना पड़ता था।

उक्त नियमों को कार्यान्वित करने का मात्र इतना ही उद्देश्य था कि अफीम की तस्करी को प्रोत्साहन न मिल सके।

बनारस मण्डल के अफीम के ठेकेदार जे० एल० विलियम ने १३ जून १७६१ को गवर्नर से इस आशय का अनुरोध किया कि बनारस मण्डल में देश के अन्य हिस्सों की भाँति एक स्थाई नियम बनाया जाय और एक अधिकारी की नियुक्ति की जाय जिससे ठेकेदार और रैयत के मध्य सुविधा और सुरक्षा सम्बन्धी कार्य सुचारु रूप से किया जा सके। रैयतों को इसका आभास भी कराये जाने की अपील की गई थी कि वे सरकारी नियमों और आदेशों का उल्लंघन न करें। रेजीडेन्ट ने कई अदालतों के न्यायाधीशों से परस्पर बातचीत के दौरान गवर्नर के उक्त सुझाव का भी सदर्थ दिया। इस सुझाव या घोषणा के विरुद्ध अफीम खरीदने और बेचने वालों को दण्डित किये जाने का निर्णय लिया गया तथा अदालत में ऐसी स्थिति में दुगना दण्ड भुगतने का फैसला हुआ^{१४}

रेजीडेन्ट ने बंगाल और बिहार की भाँति इन नियमों को बनारस मण्डल में लागू करने का आदेश दिया जिसे सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो गई। चूँकी आगामी ३१ अगस्त १७६३ को बंगाल, बिहार और बनारस

^{१४} वही—१४ जून १७६१, पृष्ठ ८६—६१

मण्डल में लागू पुरानी शर्तें समाप्त होने लगी थी^{१५} अतः २८ जनवरी १७६३ को सरकार द्वारा भविष्य में अफीम की आपूर्ति के लिए नये प्रस्ताव की माँग की गई जिसमें निम्नलिखित^{१६} शर्तें रखी गई —

(१) यदि डायरेक्टर ठेके की शर्त को स्वीकार करते हैं या परिवर्तन करते हैं तो आवश्यकतानुसार गवर्नर उसे रद्द करने के लिए अधिकार सम्पन्न होगा।

(२) ठेका चार वर्ष के लिए दिया जायेगा जो १ सितम्बर १७६३ से प्रारम्भ होगा।

(३) २ मन से भरी हुई प्रति पेटी की दर से ६०० पेटिया प्रतिवर्ष ठेकेदारों द्वारा देय होगी।

(४) ठेके का रुपया सिक्को में दिया जायेगा। यद्यपि सरकार द्वारा ठेकेदारों को अग्रिम धन दिया जायेगा किन्तु ठेकेदार को रैयत को अग्रिम धन देने का अधिकार नहीं होगा।

(५) प्रथम वर्ष दिये जाने वाली अफीम की पेटी बनारस में स्वीकृत किये गये अफीम की ही भाँति होगी।

(६) निर्धारित मात्रा के अनुसार पेटी में अफीम होना चाहिए था और यदि किसी की पेटी में अफीम की मात्रा कम होती थी तो ठेकेदारों को ३००/- प्रति पेटी की दर से जुर्माना देना होता था और सरकार द्वारा

^{१५} वही— १६ जून १७६२—पृष्ठ ५४६—५५०

^{१६} वही— पृष्ठ ५५०—५५१

प्रदत्त अग्रिम धनराशि भी लौटा देनी पड़ती थी। यदि दुर्भाग्यवश दैवी प्रकोप के कारण कभी फसल नष्ट हो जाती थी तो ठेकेदार को कुछ रियायत दे दी जाती थी।

(७) रैयत द्वारा प्रदत्त अफीम पूर्णतः ठेकेदार कम्पनी या उसके एजेंट को देता था। यदि कभी वह किसी अन्य व्यक्ति को अफीम का कुछ हिस्सा बेच देता था या किसी वस्तु के बदले में दे देता था तो ऐसे कार्य के लिए दोषी पाये जाने पर उसे ७५०/- की धनराशि जुर्माना स्वरूप देनी पड़ती थी।

(८) कलकत्ता में स्थित व्यापार परिषद् को अफीम अपने खर्च से ठेकेदार भेजता था।

(९) ठेकेदार वजीर के राज्य से बाहर जितनी अफीम भेजता था उसपर २ १/२ प्रतिशत कर स्वरूप बनारस के राजा को देना पड़ता था।

(१०) बंगाल और बिहार में उत्पादित अफीम को ठेकेदार न तो स्वयं ले सकता था, न किसी को दे सकता था और न ही बाहर भेज सकता था।

(११) शुद्ध अफीम के प्रति एक सेर पर ढाई रुपये ठेकेदारों को कर देना पड़ता था और प्रति एक मन पर ढाई सेर वजन की अफीम अधिक देनी पड़ती थी जिससे सुखाने के बाद अफीम का वजन पूर्णतः एक मन बना रहे।

(१२) अफीम की खेती के लिए निश्चित बीघा जमीन के आधार पर ठेकेदार अफीम देने का वचन देता था न कि उससे उत्पादित सम्पूर्ण अफीम।

(१३) किसी प्रकार के दैवी प्रकोपवश यदि खेती को क्षति होती थी तो ठेकेदार द्वारा खर्च वहन करने पर रेजीडेन्ट एक अमीन की नियुक्ति करता था जो हुई क्षति का अनुमान लगा कर बताता था।

(१४) रेजीडेन्ट या उसके प्रतिनिधि द्वारा प्रतिवर्ष तराजू का निरीक्षण हुआ करता था।

(१५) निर्धारित मात्रा में अफीम रैयत द्वारा न दिये जाने पर निम्नलिखित परिणामों को भुगतना पड़ता था—

(अ) यदि रैयत दोषी नहीं पाया जाता था तो उसे प्राप्त धनराशि (अग्रिम रूप में) के कुछ भाग पर २ प्रतिशत की दर से वार्षिक ब्याज का भुगतान करना पड़ता था।

(ब) यदि ठेकेदार को इसका सन्देह होता था कि रैयत की लापरवाही से ऐसा हुआ है तो अदालत या रेजीडेन्ट उससे अग्रिम धनराशि का साढ़े बारह प्रतिशत ब्याज वसूल करता था।

(स) यदि रैयत कभी अपनी जिद के कारण कच्चा माल किसी अन्य को बेच देता था तो इसकी शिकायत ठेकेदार रेजीडेन्ट से या अदालत में करता था। ऐसा मात्र रैयत के सुधार हेतु किया जाता था।

(१६) यदि वजन बढ़ाने के उद्देश्य से रैयत कच्चे माल में पानी मिलाता था तो उसकी धर्म परीक्षा के लिए अफीम उत्पादन करने वाले दो सम्मानित व्यक्तियों की नियुक्ति ठेकेदार द्वारा की जाती थी।

(१७) यदि रैयत कच्चा माल तैयार करने वालों को मिलावट करके अफीम देता था तो उसका सम्पूर्ण माल जब्त कर लिया जाता था।

(१८) ठेकेदार द्वारा रैयत से किसी प्रकार का शुल्क अथवा दस्तूर लेने की प्रथा नहीं थी। यदि कोई इस का उल्लंघन करता था तो उसे दस्तूर में लिए गये धन का तीनगुना देना पड़ता था।

(१९) ठेकेदार या अफीम उत्पादक अपनी शिकायतों को मुफलिस अदालत के भारतीय न्यायाधीश के समक्ष प्रस्तुत कर सकता था। अदालत के निर्णय का दावा रेजीडेन्ट के पास होता था। ऐसा तभी होता था जबकि मुकदमे का धन धारा के निश्चित धन से कम नहीं होता था।

उक्त अध्यादेश से यह स्पष्ट है कि डकन ने कृषकों और सरकार की उन्नति हेतु प्रयत्न किया। उन्होंने बनारस में शुद्ध अफीम के उत्पादन पर बल दिया जिससे सरकार को अत्यधिक लाभ हुआ और कृषकों को भी क्षति नहीं पहुँची।³⁷

किन्तु १७६६ के अध्यादेश से अफीम के व्यापार में गिरावट आ गई। सर जॉन शोर ने डकन को लिखा कि आमदनी में यह कमी इस वर्ष छूट

37 होल्डन फर्बर-रिपोर्ट ऑफ इण्डियन गवर्नर जनरलशिप-पृष्ठ-८८

से अधिक हो गयी। जब यह पत्र डाइरेक्टर की अदालत में प्रस्तुत किया गया तो उसका विपरीत प्रभाव पड़ा।

बगाल, बिहार तथा बनारस से चार हजार सात सौ तिहत्तर पेटियो का मूल्य ७ लाख ४२ हजार ५ सौ ४२ रुपये आये। इस कमी का कारण गत वर्ष बाजार में अफीम का अधिक माल निर्यात होना था। अफीम के व्यापार में गिरावट आ जाने से डाइरेक्टर की अदालत परेशान थी। विदेशी बाजारों में माल खराब होने से कीमत में कमी हो गयी।

अफीम व्यापार के लिए ठेकेदारी और एजेन्सी में से कौन सी नीति लाभप्रद होगी इस विषय पर विचार करने हेतु बगाल सरकार को लिखा गया। १५ मई १७६६ में डाइरेक्टर की अदालत ने सरकार को एक पत्र द्वारा अफीम का परिमाण बनाये रखने हेतु बाध्य किया।^{१४} फिर भी बजारों में इसकी प्रतिष्ठा बनाये रखने के लिए कहा गया। उन लोगों ने बगाल की अफीम का नियम गवर्नर की इच्छा से समाप्त करना स्वीकार कर लिया।

गत वर्षों में अफीम के व्यापार में आई गिरावट को सुधारने तथा व्यापार को बढ़ाने की दृष्टि से ११ जुलाई १७६६ में ठेकेदारी के स्थान पर एजेन्सी का नियम लागू किया गया। एजेन्टों को अफीम उत्पादक किसानों को परेशान करने की बिल्कुल मनाही कर दी गयी।^{१५}

^{१४} वही-पृष्ठ- ११३

^{१५} सेपरेट रेवेन्यू पत्र कोर्ट के नाम ६, ७ मार्च १७६६ पैरा-२

पोस्ते की खेती करने के लिए सरकार की स्वीकृति लेनी पड़ती थी। एजेन्ट कृषको को अग्रिम राशि देने से पूर्व भाव, वजन आदि निश्चित कर लेते थे। इस निश्चय की एक प्रति व्यापार परिषद के पास विचारार्थ भेज दी जाती थी। व्यापार परिषद् द्वारा स्वीकृति प्राप्त हो जाने पर कृषको को अग्रिम राशि दे दी जाती थी। इस समझौते की एक प्रति उस क्षेत्र के न्यायधीश के कक्ष में भी लगा दी जाती थी।

प्रत्येक परगना के मूल्य का निर्धारण एजेन्टों द्वारा होता था। पोस्ता बोनेंके समय एजेन्ट कृषको से बीघा निश्चित कर लेता था। निश्चित बीघे से कम में खेती करने वाले किसान को अग्रिम धनराशि का तीनगुना जुर्माना स्वरूप देना पड़ता था। खेत में उत्पन्न सम्पूर्ण पोस्ता किसान को देना पड़ता था। एजेन्सी की नीति काफी लाभदायक सिद्ध हुई। गत वर्ष से विक्रय मूल्य में वृद्धि हुई। बनारस की अफीम २५ प्रतिशत प्रति पेटी अधिक हो गई। दूसरा विक्रय जो १६ फरवरी, १७६६ में हुआ अपेक्षाकृत अच्छा था। ११ जून १८०० में डाइरेक्टर की अदालत के पत्र द्वारा इस विक्रय की प्रशंसा करते हुए एजेन्सी नीति को श्रेष्ठ बताया गया। अफीम की गुणवत्ता में भी सुधार हुआ। गवर्नर ने कहा कि एजेन्सी द्वारा यदि अधिक आय न भी होगी तब भी बराबर तो अवश्य ही रहेगी।⁴⁰

अब कम्पनी सीधे अपने कर्मचारियों द्वारा अफीम बनाने वालों से सम्बन्ध स्थापित करने लगी। धीरे-धीरे एजेन्सी नीति में भी त्रुटि आने लगी। कम्पनी के लोगो द्वारा अफीम उत्पादक त्रस्त किये जाने लगे।

40 बंगाल रेग्युलेशन, जिल्द — प्रथम पृष्ठ — ४०२—४०४

१७६६ के अध्यादेश में १८०७ में कुछ परिवर्तन हुआ। परिवर्तन द्वारा बिहार तथा बनारस के बाहर अफीम का उत्पादन नहीं होना था। फलतः तस्करी और छिपे रीति से व्यापार प्रारम्भ होने लगा। इसे रोकना कम्पनी के लिए कठिन था।

१८०७ में बनारस के लिए एक पृथक एजेन्सी स्थापित की गई। अफीम का उत्पादन सीमित करते हुए यह घोषणा कर दी गई थी कि प्रति वर्ष १५०० मन से अधिक उत्पादन नहीं होना चाहिए।⁴¹

इस प्रकार १८वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में अफीम के निर्यात में २०० प्रतिशत से भी अधिक की वृद्धि हुई। सम्भवतः अवध से इस क्षेत्र में आयातित अफीम भी इस वृद्धि का एक मुख्य कारण थी।⁴²

नमक

बनारस में नमक का जो उद्योग होता था वह साम्भर, उदयनगर और जोधपुर से आता था। बनारस में इसका मूल्य ४५० रु० प्रतिमन था। इसका उपयोग मध्यमवर्ग तक ही सीमित था। गरीब जनता द्वारा प्रयोग किये जाने वाले नमक को बबेहा कहते थे।⁴³ गरवारा, रारी, सिगरामउ, जफराबाद तथा गोपालपुर में नमक बनाया जाता था। नमक की वार्षिक उपज ७०,००० मन तक था जिसमें ४०,००० मन नमक का

41 सेपरेट रेवेन्यू लेटर—कोर्ट को लिखित सितम्बर, १८०० से जून १८०० तक क्रमशः पृष्ठ ८, पैरा ३, ८, ११, १२, एव एच० आर० घोसाल—एकोनामिक ट्रान्जिशन इन बंगाल प्रेसीडेन्सी—पृष्ठ—१२५

42 ए० शेक्सपियर्स—सेलेक्शन फ्रॉम दी डकन रेकार्ड, जिल्द—द्वितीय, पृष्ठ १७६—१७७

43 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स—अगस्त १७८७ पृष्ठ—१६३ एव मार्टिन हिस्ट्री ऑफ एन्टीक्वेट टोपोग्राफी एण्ड स्टैटिस्टिकल सर्वे आफ इस्टर्न इण्डिया पृष्ठ ५४६—५०

उत्पादन केवल मुगरा ही करता था। अच्छा और उत्तम माल २/५० प्रति मन, द्वितीय श्रेणी का १-२५ प्रति मन से १-१५ तक तथा तृतीय श्रेणी का माल १/- प्रति मन की दर से बेचा जाता था।

१७६० में जौनपुर में साल्ट महल बनाया गया। एक अन्य महल बनाकर १८०००/- प्रति वर्ष की दर से शिवराज दुबे को पांच वर्ष के लिए लीज पर दे दिया गया।⁴⁴

यह भी प्रासंगिक है कि अच्छा माल जौनपुर और बनारस जिलो में पाया जाता था। दूसरी श्रेणी का माल वजीर नवाब के राज्य में भेज दिया जाता था।

अध्यादेश ६ धारा ४ के अनुसार बनारस मण्डल को बालम्बा, काशी, नेला, नमिट, जूलिया, ऊटसोचाल और लाहौर नामक नमक के आयात का आदेश था। इस अध्यादेश के अनुसार १-०० प्रति मन की दर से टैक्स लगता था। सोलम्बा और बालम्बा नामक नमक पर सवा दो रुपये प्रति मन की दर से टैक्स लगता था जिसका परिणाम यह हुआ कि इनका आयात ही बन्द हो गया। साम्भर नमक की गुणवत्ता भी कम हो गई। इन नमकों का मूल्य बाजार में ८० प्रतिशत बढ़ गया।⁴⁵

१८०१ अध्यादेश की धारा ६ के अनुसार सरकार की अनुमति के बिना नमक बनाना मना था। इस अध्यादेश का उल्लंघन करने वालों को

44 गाजीपुर करसपान्डेस-२५ नवम्बर, १७६६ जिल्द ११८ पृष्ठ- ७८-७९ एव मीरात-उल-आमल फुटनोट ३६ ८१, आलमगीरनामा पृष्ठ - २२२ एव बचनान-ए जर्नीफ्राम मद्रास थू मैसूर केनरा एण्ड मालावार।

45 बंगाल रेग्यूलेशन -(१)- अपेन्डिक्स, पृष्ठ- ४८७

५०००/- जुर्माना स्वरूप देना पड़ता था। इस कड़े अध्यादेश के परिणाम स्वरूप नमक व्यापार को क्षति पहुँची। नमक व्यापार में लगे हुए अधिकांश लोग बेकार हो गये। कुछ नमक व्यापारी बेलहरा परगना में और कुछ नवाब वजीर के प्रान्त में जाकर बस गये। ऐसे लोग अवैध रूप से नमक का व्यापार करने लगे। बेलहरा और बिलकौर से बनारस मण्डल में लगातार तस्करी होने लगी।⁴⁶

नमक के अवैध व्यापार को रोकने के लिए नमक के आयात और विक्रय का उत्तरदायित्व मजिस्ट्रेट और पुलिस अधिकारियों का हो गया। भूमि टैक्ट वसूलने वाले कलेक्टर को अध्यादेश १८०१, के अध्यादेश ६ की धारा ६ के अन्तर्गत नमक के अवैध व्यापार को रोकने के लिए लोगों से सहायता प्रदान करने का आदेश दिया गया। उक्त अध्यादेश के अन्तर्गत नमक की चौकियों के अधीक्षक और एजेंट नमक के मूल्य के ३५ प्रतिशत के बराबर पुरस्कार के अधिकारी होते थे। नमक का मूल्य उस जिले या क्षेत्र के निर्धारित मूल्य के अनुसार ही आका जाता था।⁴⁷ १८०१ के अध्यादेश ६ की धारा २७वीं के अन्तर्गत नमक चौकियों के लिए दरोगा नियुक्त किये गये। उन्हें अपना पद ग्रहण करने से पूर्व १०००/- की जमानत देना होता था। यदि तस्करी के मामले में उनका सहयोग किसी प्रकार से सिद्ध हो जाता था तो वे दण्ड के भागी होते थे और उनकी जमानत जब्त कर ली जाती थी।⁴⁸

46 वही पृष्ठ-४८८ एव खुलासात तवारीख पृष्ठ ५८

47 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स-१६ नवम्बर १८०२, पृष्ठ २०३

48 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स-१२ अक्टूबर, १८०२, पृष्ठ १६६ एव बंगाल रेग्यूलेशन (१) अपेन्डिक्स पृष्ठ-४८८

शोरा

शोरा का उत्पादन बनारस से लगभग दस मील की दूरी पर बारा परगना के निकट चवसा केवली ग्राम में और गाजीपुर जिले के खेतीपुर ग्राम में होता था। वार्षिक उपज २०,००० मन की थी। यह पौने तीन रुपये मन की दर से बिकता था और ढाई प्रतिशत कर लगता था। यद्यपि यह दर पहले की अपेक्षा कम थी किन्तु फिर भी इसे पहले की व्यापारिक सन्धि के अनुसार समझा जाता था। शोरा अधिकांशतः बारूद बनाने के काम आता था। १८वीं शताब्दी में योरोपीय जाति द्वारा युद्ध में इसकी मांग अधिक हो गई थी। वजीर नवाब के राज्य से शोरा का बनारस मण्डल में आयात होने लगा था।⁴⁹

रेशम

प्राचीन काल से ही बनारस नगर अपने सुन्दर जरी बूटी के रेशमी वस्त्रों के लिए प्रसिद्ध रहा है। मुगलकाल में कमरबन्द, पगडी और स्त्रियों के वस्त्रों के लिए बनारस को विशेष ख्याति प्राप्त थी।⁵⁰ एक फ्रांसीसी डाक्टर जो शाहजहाँ के शासनकाल के अन्तिम चरण में भारत आया था और कई वर्षों तक भारत में रहा उसने बनारस के विषय में लिखा है कि ,
“ बड़े-बड़े कमरे जो कारखाने कहे जाते थे अनेक स्थानों पर देखने को मिले जिसमें कारीगर काम करते थे। एक कक्ष में दरी बनाने वाले कारीगर

49 वही—पृष्ठ ४६३ तथा वी आर सी २४ अगस्त १७८७ पृष्ठ १७१ एव आइने अकबरी जिल्द—१ पृष्ठ ५८ एव बंगाल सेलेक्ट्रेड कमीटी प्रोसीडिंग्स—११ जून १७६१ पृष्ठ १०७, एव पी० मुन्डी ट्रेवेल्स पृष्ठ ७६-७७

50 एफ० बर्नियर, ट्रेवेल्स इन द मुगल इम्पायर (१६५६-१६६८) पृष्ठ २५८-२५९

नियुक्त थे जो एक मालिक के निरीक्षण में कार्य करते थे। दूसरे कक्ष में सुनार तीसरे कक्ष में चित्रकार, चौथे में पीतल और वार्निश चढ़ाने वाले, पाँचवें में बढई, दर्जी, मोची कार्य करते थे। छठे कक्ष में रेशमी जरी के कपड़े बनाने वाले और पगड़ी जिस पर सुनहरे फूल बने होते थे तथा स्त्रियों के लिए रेशमी वस्त्र बनाने वाले कारीगर कार्य करते थे।⁵¹

मुगलों के पतन के साथ ही ये कारखाने भी धीरे-धीरे समाप्त हो गये। अब बुनकरो द्वारा नकद मूल्य पर वस्तुओं का विक्रय प्रचलित हुआ। सरकार को बिना असुविधा पहुँचाये यह व्यापार व्यापारियों द्वारा किया जाता था। इसका दर माल के सिद्धान्तों के ऊपर निर्धारित किया जाता था और उन दलालों के माध्यम से खरीदा जाता था जो बुनकर और विक्रेता के बीच बिचौलियों का काम करते थे। इन बिचौलियों को विक्रेता से कमीशन प्राप्त होता था।⁵² दलाल वस्तुओं के निर्माता और व्यापारियों को एक दूसरे के निकट लाकर व्यापार में उन्नति करते थे जिससे अधिक लाभ होता था। १७८६ में इन दलालों को कारखानों के एजेंट से बुनकरो और सौदागरों को देने के लिए माल प्राप्त होता था।⁵³

⁵¹ गाजीपुर करसपॉन्डेन्स २७ अगस्त १७८७, जिल्द-८६, पृष्ठ १५ एव फिज अर्ली ट्रेवेल्स इन इण्डिया पृष्ठ-२८, ट्रेवनियर भाग-२ पृष्ठ २०

यदुनाथ सरकार-औरगजेब (खण्ड-५) पृष्ठ -३४१, एव ट्रेवनियर-अर्ली ट्रेवेल्स इन इंडिया-पृष्ठ-२

⁵² वही-पृष्ठ-११ एव एम एम खान-पृष्ठ २०७ अप्रकाशित शोध ग्रन्थ।

⁵³ ई० थर्सटन-हिस्ट्री ऑफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी क्वायनेज (जर्नल आफ ऐसीयाटिक सोसाइटी आफ बंगाल) जिल्द १८६३ खण्ड १ पृष्ठ-५५ एव हेनरी एडवर्ड फेने फाइव इयर्स इन इण्डिया- जिल्द-१ पृष्ठ-४७, मनुची ट्रेवेल्स जिल्द-२ पृष्ठ ६२८ एव एरिश-ए रहीस-ए- महफिल-पृष्ठ १०१

बनारस का मिन्ट सोना चॉदी का तार एव सूत बनाने वालो का माध्यम था और कीमती वस्त्र जरीदार वस्त्र बनाने वाले एव बुनकरो का भी इसमे साथ था। जी० एल० बालों ने अपनी पुस्तक मे बनारस मण्डल के सिक्का निर्माण रीति का वर्णन किया है कि सोना चॉदी का तार व सूत बनाने वाले तथा मिन्ट के मध्य परस्पर सम्बन्ध था और इन वस्तुओ का निर्माण इनके व्यापार की उन्नति पर निर्भर करता था। मिन्ट के समाप्त हो जाने पर उन वस्तुओ के निर्माताओ ने दूसरी वस्तु की माग किया। सिल्क उद्योग का केन्द्र बनारस जिले मे कई स्थानो पर था। किमखाब, जरीदार कपडा, चादी, सोने के तार, साटिन एव कई अन्य प्रकार के कपडे जो गुलदान और चारखाना के नाम से प्रसिद्ध थे बनाये जाते थे। मैकाले ने लिखा है कि “ यह अतिशयोक्ति नही है कि बनारस मे तैयार किया गया बारीक रेशम सेन्टजेम के बाल को सुशोभित करता था।” बनारस अपने मुख्य उद्योग कलाबत्तू के लिए प्रसिद्ध था जिसकी माग किमखाब बनाने के लिए बहुत अधिक थी। बनारस मे बना हुआ सलमा भारत के दूसरी श्रेणी मे आता था।⁵⁴

छीट (बढ़िया कपड़ा)

बनारस मण्डल मे उच्चकोटि की छीट का कपडा बनाया जाता था। जैसा कि वार्ड ने लिखा है, “भारत की यह मूल कला भी, छीट का बनाना,

५४ वही— ५५-५६, एव टी० बी० मैकाले-एशेआन वारेन हैस्टिंग्स— पृष्ठ-५५ एव हाप्सन जाप्सन—पृष्ठ ३८४

अपनी अधिक सुन्दरता और अच्छाई के कारण योरप मे बिना किसी सशोधन के उसी रूप मे प्रयोग होता था।^{५५}

सूत

खासा, काशिमाबाद, रगोली, हबेली, गाजीपुर और रसडा मे सूती कपडे का निर्माण होता था। बलिया मे गारा, मोहम्मदाबाद मे मारसे और जौनपुर मे मलमल बनता था। अच्छे किस्म का सादा और धारीदार तन्जेब बनारस मे बनाया जाता था। सूती कपडो की रगाई और छपाई अधिकाशत लोहता मे होती थी। बनारस मे प्रति वर्ष लगभग ६ लाख रुपये का कपडा बनता था जिसकी अधिकाश खपत बनारस मे ही हो जाती थी। शेष माल को कलकत्ता भेज दिया जाता था। बुनकरो को सरकार अग्रिम राशि देकर सारा माल देश के लगान के रुपये से खरीद लेती थी। वस्तुओ के मूल्य की सूची जो कलकत्ता भेजी जाती थी। निम्नवत है—

कपडा	प्रतिथान	चार्ज	योग
बबता 36'x2'	87-8 आना	8-00	96-8 आना
घरहा 36'x2'	67-8 आना	7-00	79-8 आना
इमरतिस 8'x3/4'	60-00 रु	6-00	66-80 रु
लखौरी 28'x2'	46-8 आना	5-00	52-8 आना

⁵⁵ डब्ल्यू ० वर्ड० —व्यू ऑफ हिस्ट्री लिट्रेचर एण्ड रेलीजन ऑफ हिन्दूज, जिल्द प्रथम—पृष्ठ—६६

कम्पनी द्वारा बनारस के बने वस्त्रों का निर्यात भी प्रारम्भ हुआ। व्यापारियों को इसके मूल्य की जानकारी कराने के लिए बनारस, गाजीपुर, जौनपुर और मिर्जापुर के चुगीघरों में कपड़ों के नमूने दर सहित रख दिये जाते थे। व्यापारी अपना माल व्यक्तिगत रूप से न बेचकर कम्पनी को देने के लिए अधिक उत्सुक रहने लगे। सरकार कम मूल्य पर उनका सारा माल क्रय कर लेती थी। इससे व्यापारी को अपनी बिक्री का मूल्य तुरन्त प्राप्त हो जाता था। प्रथम बाजार में जहाँ कपड़े बेचे जाते थे ५ प्रतिशत टैक्स लगाया गया और उनपर उस स्थान की मुहर लगा दी जाती थी जिससे अन्य स्थानों पर उनसे टैक्स न लिया जाये।

बनारस मण्डल में सूती कपड़ा बनाने के लिए जो कपास प्रयुक्त होता था वह जमुना नदी के दक्षिणी किनारे के राज्यों से आता था। इन राज्यों में कपास की पैदावार बहुतायत में होती थी। दक्षिण से भी कपास, मगाया जाता था। एक लाख नब्बे हजार पाँच सौ छिहत्तर मन पौने दो सेर कपास का मूल्य एक लाख सोलह हजार छ सौ उन्चास रुपये आठ आना (रु० ११६ ६४६—८ आना) होता था। जालौन और अहमद नगर के कपास की अपेक्षा नागपुर का कपास अधिक अच्छा होता था।⁵⁶

धातु

कीमती धातु का कार्य केवल सोना चाँदी के तार बनाने तक ही सीमित नहीं था। बनारस नगर में ऐसे बहुत से स्वर्णकार थे जो जवाहरात

⁵⁶ बनारस रेजीडेन्सी करसर्पोडेन्स— २७ अगस्त १७८७ पृष्ठ — ४१, ४२, ४३, एव आइने अकबरी जिल्द—२ पृष्ठ १६६

के साथ ही साथ सोने चाँदी के बर्तन भी बनाते थे। चाँदी के हौदे, कुर्सियाँ, पालकी आदि बनाकर जरीदार कपड़ों से ढकने का कार्य भी होता था। सौदागर भारी मात्रा में इनका व्यापार नेपाल से करते थे और इसके बदले में सोने की ईंट प्रति वर्ष ४ से ५ लाख रुपये तक का वहाँ से लाते थे। इस सोने पर टैक्स लगता था। टैक्सों को वसूल करने वाले कार्यालय को सोना महल कहा जाता था⁵⁷ जिसकी स्थापना राजा बलवन्त सिंह द्वारा की गई थी।⁵⁷

पीतल

बनारस और मिर्जापुर पीतल उद्योग के मुख्य केन्द्र थे। इस उद्योग के मालिक बनिया या कसेरे होते थे। ये मजदूरों को पीतल का औजार देते थे। कच्चा पीतल प्रायः बाहर से मगाकर बनारस में नक्काशीदार बर्तन निर्मित किये जाते थे। पीतल की मूर्तियाँ, रूप तथा थालों में चित्रकारी का कार्य मुख्य था। थालों तथा अन्य फैन्सी वस्तुओं पर उभार का कार्य होता था। बड़ी-बड़ी तश्तरियाँ, थाल गंगा-जमुना ट्रे, कटोरे, फूलदान, सुराही, लोटा, मोर, पन्तास, तसला तथा अन्य दूसरी वस्तुओं का निर्माण भी होता था।⁵⁸

⁵⁷ वही— पृष्ठ ४१, ४२, ४३ एव बंगाल पास्ट एण्ड प्रेजेन्ट (जर्नल) पृष्ठ—७

⁵⁸ जी० बी० डैमपियर—ए मोनाग्राफी ऑन ब्रास एण्ड कापर वायर्स ऑफ (एन० डब्ल्यू० पी०) एण्ड अवध पृष्ठ—३२-३३

मिर्जापुर के पीतल, कासा जिसमे जस्ता और ताबा मिला रहता है, का भी उद्योग प्रसिद्ध था। बड़े सम्पन्न घरों में प्रयोग होने वाले प्रायः सभी बर्तन यहाँ बनते थे। सफेद धातु का कार्य यहाँ नहीं होता था।⁵⁹

इत्र एवं केवड़ाजल

गाजीपुर इत्र बनाने का प्रमुख केन्द्र था। यहाँ भारी मात्रा में गुलाब जल बनता था। गुलाब की खेती साधारण किसानों द्वारा नगर के आसपास होती थी। जिन्हे इत्र निर्माताओं से अग्रिम राशि मिल जाती थी। मार्च और अप्रैल माह के मध्य में गुलाब एकत्र किया जाता था जिसका विक्रय सख्या के अनुसार होता था। यहाँ पर उच्चकोटि का सस्ता गुलाब जल तैयार होता था। गुलाबजल को बड़े-बड़े बर्तनों में रात्रि से प्रातः तक खुली हवा में रखा जाता था। प्रातः काल गुलाब जल पर एक हल्की तेल की पर्त जम जाती थी जिसे समेट कर इत्र बनाया जाता था। इस प्रकार इत्र सस्ता होता था। एक रुपयों भर इत्र के लिए दो हजार गुलाब के अच्छे फूल की आवश्यकता होती थी।⁶⁰

केवड़ा जल जौनपुर में बनाया जाता था। बी० एच० ओलपर का कहना है कि "इस इत्र की अधिकतम माग योरोप के तेल कारखानों में होती थी।" जौनपुर सुगन्धित तेल उद्योग के लिए प्रसिद्ध था। गुलाब की भौंति चमेली और बेला की भी खेती होती थी। इत्र का बनाना फारस से शर्की सुल्तान के जमाने से प्रारम्भ हुआ। खस घास की जड़ से बनता

⁵⁹ वही पृष्ठ-३२-३३

⁶⁰ पी० हेबर- ए नरेटिब ऑफ जर्नी थ्रू दी अपर प्राविन्सेज ऑफ इण्डियन-जिल्द- प्रथम पृष्ठ २६६

था। जौनपुर शहर के आस पास चमेली और बेला की खेती अधिक मात्रा में होती थी। गुलाब गाजीपुर से आता था। गाजीपुर और जौनपुर का माल अधिकतर बंगाल और बिहार में तथा कुछ राजस्थान और पंजाब में बेचा जाता था।⁶¹

लकड़ी के खिलौने

लकड़ी के खिलौने का प्रमुख उद्योग अलईपुर, तेलियानाला, रामापुरा, भेलूपुरा, कुबरवापुरा, और खोजवा में था। इन खिलौनों के लिए कोरया नामक सफेद और मुलायम लकड़ी का प्रयोग किया जाता था जो हजरौरा, पालामउ, धनूपुर, भगवा से आता था। रगाई के लिए लाख और रंग के मिश्रण का प्रयोग होता था।⁶²

ईंट उद्योग

पूर्वी उत्तर प्रदेश में ईंट उद्योग अपनी उत्कृष्टता की चरमसीमा पर था। ईंट की पथाई, भराई एवं पकाई के पश्चात् उसकी निकासी की जाती थी। तैयार ईंट की बिक्री की जाती थी। बड़े भवनो, हर प्रकार के मकानो के निर्माण में इसका प्रयोग किया जाता था।⁶³

61 डुप्लेन, पेपर ऑफ इण्डियन एसेन्सियल आयल प्रोसीडिंग आफ इण्डियन हिस्ट्री काग्रेस-१९०६ एंव मनुची ट्रेवेल्स खण्ड (२) पृष्ठ ४२८ एंव हेबर-नरेटिव ऑफ जर्नी थू दी अपर प्राविन्सेज इण्डिया जिल्द-१ पृष्ठ ३५०, एंव ए रहीसे महफिल पृष्ठ-१०६

62 एच० सी० चटर्जी -नोट्स आन इन्डस्ट्रीज इन यू० पी० पृष्ठ-३८-३९, एंव मनुची-ट्रेवेल्स खण्ड (२) पृष्ठ ४२८

63 जे० एन० सरकार० इन्डस्ट्रीज इन मुगल इण्डिया पृष्ठ-२१८,

पान

बनारस का पान उद्योग प्राचीनकाल से ही अपनी उन्नति की पराकाष्ठा पर रहा है। अठारहवीं शताब्दी में 'बनारसी पान' विश्वस्तर पर प्रसिद्ध था और हर छोटी बड़ी महफिलों, उत्सवों की शान था। पान का सेवन प्रायः सभी वर्ग के लोग करते थे। पान की खेती, कत्था, सुपारी, और विभिन्न प्रकार के तम्बाकूओं का निर्माण और विक्रय बनारस के व्यापार का मुख्य स्रोत था। तम्बाकू की अनेक श्रेणियाँ होती थीं ‡ जिनका मूल्य उनकी गुणवत्ता और सुगन्ध पर आधारित होता था।⁶⁴

६४ आईने अकबरी जिल्द एक पृष्ठ-७७, (जैरेट) अनुवाद, मनूची, जिल्द (१) पृष्ठ ६३, ट्रेवेनियर ट्रेवेल्स जिल्द (१) पृष्ठ-२६४, गुलबदन बेगम, हुमायूनामा-पृष्ठ-३३, एम० पी० श्रीवास्तव 'सोसायटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इन्डिया पृष्ठ १०८ वर्नियर ट्रेवेल्स- पृष्ठ-१३

उधर सुरग जनु खाए तबोला

अब ही जानु चाहे हँसि बोला।

(हिन्दी) चित्रावली-पृष्ठ ६४-७२

कर, चुंगी
एवं
बैकिंग प्रणाली

कर चुँगी और बैंकिंग प्रणाली

प्रायः सम्पूर्ण प्रशासन में कर की व्यवस्था एक प्रकार की होती थी। यद्यपि इसकी एकरूपता बनाये रखने के लिए विशेष ध्यान दिया जाता था किन्तु कहीं-कहीं क्षेत्र विशेष में कर के स्वरूप में अन्तर भी पाया जाता था।

मुगलकाल में हिन्दुओं से 'जजिया' कर और मुसलमानों से 'जकात' कर लिया जाता था। जकात से प्राप्त होने वाली धनराशि का उपयोग मस्जिदों, मदरसों एवं धार्मिक कृत्यों में किया जाता था। इन करों को वसूलने के लिए कर्मचारी नियुक्त किये जाते थे।¹ कुछ शासकों ने इन धार्मिक करों में अपने शासन काल में छूट भी दिया किन्तु औरंगजेब ने अपने राज्य काल में इस हेतु कोई छूट नहीं दिया।²

कुछ मुगलकालीन शासकों ने 'तम्बाकू' पर विक्रय कर लगाया था किन्तु औरंगजेब ने तम्बाकू, अफीम, गोंजा, भाग, मद्य आदि नशीले पदार्थों की बिक्री पर प्रतिबन्ध लगा दिया और इनके निमित्त सारे लाइसेन्स रद्द

1 हरिशंकर श्रीवास्तव—'मुगल प्रशासन' पृष्ठ १२६-१३० एवं ह्यूम्स टी०पी०—डिक्शनरी ऑफ इस्लाम पृष्ठ ६६६-६०० एवं अथनाइड्स, एन० पी०—मुहम्मदन थ्योरीज आफ फाइनेन्स पृष्ठ २०७, २६७, ३१८ एवं त्रिपाठी राम प्रसाद—सम आसपेक्ट आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन पृष्ठ-२४५

2 कुरैशी—दि ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ दि मुगल इम्पायर पृष्ठ १४७, जहीरुद्दीन फारुकी—औरंगजेब एण्ड हिज टाइम्स—पृष्ठ-१६४, १७०, ४७६

कर दिया।³ मुगलकाल में सूतीवस्त्र निर्माण में लगे कारीगरो अथवा व्यवसायियों को तैयार माल पर कर देना पड़ता था। इसके अतिरिक्त वृक्षो, फल के बाग तथा भवन निर्माण पर $2\frac{3}{4}$ प्रतिशत राजस्व लगाया गया था।⁴

ऐसे भी अनेक दृष्टान्त आये हैं जिनसे यह ज्ञात होता है कि सरकारी क्षति की परवाह किये बिना व्यापारिक सुविधा को ध्यान में रखकर राजस्व में भारी छूट दी गयी। मिर्जापुर और बुन्देलखण्ड के सौदागर को कपास पर अपेक्षाकृत अधिक कर देना पड़ता था जिसे अन्य की बराबरी पर लाने के उद्देश्य से डकन ने प्रत्येक मन पर १५ प्रतिशत से १० प्रतिशत और २ प्रतिशत कम कर दिया। यद्यपि इससे शासन को हानि हुई किन्तु मिर्जापुर से बिहार और बंगाल को अधिक कपास जाने लगा। यह नवाब के फूलपुर के बाजार की अपेक्षा अधिक था।⁵ दक्षिण के व्यापारियों की सुरक्षा के लिए डकन ने जमींदारी चौकियों की व्यवस्था किया। पश्चिमी सीमा से लेकर मिर्जापुर तक पहरेदारी की व्यवस्था की गई। यह

3 डी० पन्त—दि कामर्शियल पालिसी आफ मुगल पृष्ठ—२३१—२३२, एव ए० एल०

श्रीवास्तव—‘मुगलकालीन भारत’ पृष्ठ ३७२ मोरलैण्ड ‘इंडिया ऐट दी डेथ आफ अकबर’ पृष्ठ १५८, प्ले सर्ट ‘इंडिया’ पृष्ठ ३५, तजुक—ए—जहाँगीरी भाग (१) पृष्ठ ३१० (रोजर्स अनुवाद)

4 सरकार—फरमान आफ औरंगजेब, कमेन्ट्री पृ० १२२—१८४

तम्बाकू का पौधा सर्व प्रथम गुजरात में लगाया गया १६१३ ई० में जहाँ से इसकी पत्तियाँ उपलब्ध हुईं। १६०५ में पुर्तगालियों ने इसका प्रचलन शुरू किया। जहाँगीर ने भोंग के सेवन पर प्रतिबन्ध लगा दिया क्योंकि निर्धन लोग इसका सेवन करते थे। उसका कथन था कि यह स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। किन्तु कुछ शासकों ने गोंजा, अफीम, भाग पर से प्रतिबन्ध हटा दिया क्योंकि वे स्वयं उसमें रुचि रखते थे एवं उसके सेवन के आदी थे। हुमायूँ एवं बाबर गोंजा, भोंग का सेवन करते थे। अकबर भी इसका सेवन करता था। इस काल में गोंजा बुरहानपुर से आता था।

विशेष विवरण के लिए देखिये—(१) मोरलैण्ड ‘इंडिया ऐट दी डेथ आफ अकबर’ पृष्ठ—१५८, (२) प्ले सर्ट ‘इंडिया’ पृष्ठ—३५, (३) तजुक—ए—जहाँगीरी भाग (१) पृष्ठ—३१० (रोजर्स० अनुवाद)

5 ओल्डम—हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेम्यार ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट—पृष्ठ—२११

व्यवस्था गंगा नदी के दूसरी ओर तक भी थी। चुनार में राजापुर तारा, अनन्तपुर तथा चादीपुर सीमा क्षेत्र के गावों में सिपाही रखने की सिफारिश की गयी थी। डकैती और चोरी के लिए सम्बन्धित चौकियाँ जिम्मेदार होती थीं। जिनपर १५८ रु० १ आना ०० पाई का अतिरिक्त व्यय होता था।⁶ मिर्जापुर के विस्तृत बाजार को देखते हुये डकन ने वहाँ टैक्स मालिक के कार्यालय में बढोत्तरी किया। इसका उद्देश्य उचित व्यवस्था स्थापित करना था।⁷

6 वही—१३ मार्च १७६०— पृष्ठ १६४—१६६

7 वही— पृष्ठ १६६—१६७

गंज की स्थापना

सौदागरो की सुविधा के लिए गज की स्थापना की गई थी जहाँ वे अपना माल लाकर जनता को बेचते थे। इनकी स्थापना चौकियों के निकट होती थी जिससे इनकी देख रेख होती रहे। प्रत्येक गज में चौधरी होता था जिसे योग्य और कुशल होना आवश्यक होता था। चौधरी दो प्रकार के होते थे। एक भूमि के लगान वसूली का कार्य देखता था। दूसरा टैक्स सम्बन्धी कार्य देखता था। चौधरी का कार्य झगडा रोकना, व्यापारियों के कार्य की देखभाल करना और उन्हें मिलाकर रखना था। उसे वस्तुओं के मूल्य के बारे में भी कोतवाली और चुगीघरो को सूचना देना होता था। निर्धारित मूल्य में मनमानी अन्तर न आये उसे इसका भी ध्यान रखना पड़ता था। उसे मजिस्ट्रेट के समक्ष गज से सम्बन्धित सही सूचना प्रस्तुत करना पड़ता था।* पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस जनपद में राजा और जनता के वार्षिक आय के लाभ के लिए चूना महल की स्थापना की गई थी जो चूने के क्रय-विक्रय पर स्वतंत्र अधिकार रखती थी। राजा बलवन्त सिंह के पहले और मीर रुस्तम खॉ के समय में किसी को चूना बनारस में बेचने की मनाही नहीं थी। व्यापारी लोग खुले बाजार में माल बनाते और बेचते थे। चूना एक प्रकार के कड़े चट्टान के पत्थर से बनता था और वह २५/- रु० में १०० मन की दर से बिकता था। राजा बलवन्त सिंह के समय में मराठा लोगो ने बनारस में बड़ी-बड़ी, इमारतों का निर्माण करना प्रारम्भ किया तथा मन्दिरों और घाटों का भी निर्माण किया जिसके परिणाम

८ वही— दिसम्बर १७८८—पृष्ठ—३७५—३८१

स्वरूप चूने की माँग काफी बढ़ने लगी। बढ़ती हुई माँग से व्यापारियों में प्रतिस्पर्धा बढ़ने लगी और धीरे-धीरे इस प्रतिस्पर्धा ने भयकर दगे का रूप ग्रहण कर लिया।⁹

दगे और इर्ष्या को समाप्त करने के उद्देश्य से मामले को राजा के समक्ष लाया गया। राजा ने घोषणा किया कि १०००/-रु० महल में वार्षिक जमा करने पर ही कोई चूना बना सकता है। अगले वर्ष इस धन-राशि को २०००/-रु० वार्षिक कर दिया। इस वृद्धि के कारण किसानों ने बाजार में चूने का भाव बढ़ा दिया जिससे चेतसिंह के राज्यकाल तक दर और जमा दोनों ही बढ़ गये। अब चूना ४०/-रु० प्रति १०० मन बिकने लगा।

किसानों द्वारा तैयार किया गया गुरखी ३११/-रु० प्रति १०० मन पर बिकने लगा। २८ अक्टूबर १७८६ के सरकारी आदेश द्वारा चूने का स्वतंत्र अधिकार समाप्त हो गया और सरकार को २०,०००/-रु० सालाना का घाटा हुआ। इस क्षति की पूर्ति कम्पनी के भविष्य के दूसरे लाभों से की गई।¹⁰

रेह — गाजीपुर जिले के ऊसर में और प्रान्त के अन्य भागों में इस प्रकार की नूनखार वस्तु बनायी जाती थी जिसे रेह कहते थे। इसमें अशुद्ध सोडा होता था। जिसे उबाल कर चमकीली रेह बनती थी। इस व्यापार का मुख्य केन्द्र रसडा था। सरजू नदी के किनारे यह एक उन्नतिशील गाँव था। रसडा के अनेक व्यापारियों की शाखा कलकत्ता में थी।

६ बनारस रेजीडेन्सी रिकार्ड— २५, नवम्बर १७८८—पृष्ठ ६४

10 वही— २३ अक्टूबर १७८६—पृष्ठ—२५

बनारस के राजाओं के समय में २०००/- वार्षिक देने वाले किसान को स्वतंत्र लीज पर उसके उत्पादन का कार्य दिया जाता था। डकन ने इस व्यापार को हॉनिकारक समझ कर १० अक्टूबर १७८८ में समाप्त कर दिया जिस पर १७ जून १७७६ को सरकार ने अपनी स्वीकृति प्रदान कर दिया।¹¹

लकड़ी और पत्थर

लकड़ी और पत्थरके स्वतंत्र व्यापार का लाभ बनारस के राजा तथा नबाव वजीर के अधीनस्थ चुनार कोर्ट के किलादार के बीच बट जाता था।। बलवन्त सिंह के समय में गंगा प्रसाद ने लकड़ी और पत्थर के दो महल बनवाये। ६५००/- राजा को उनका हिस्सा दोनों महलों के लिए दिया गया और आधा भाग चुनार के किलेदार सैदी जौहर को दिया गया। पाँच वर्ष की लीज समाप्त हो जाने पर उन्होंने परगना की जिम्मेदारी छोड़ दिया।¹²

लकड़ी पर जो दरे वसूल होती थी वह २०० गुटवाटा पर रुपये में ७ था। प्रत्येक गुटवाटा एक लकड़ी का टुकड़ा था जो वजन में २ सेर होता था। यह आमदनी का एक मुख्य स्रोत था। जलाने वाली लकड़ी पर २/- या ४/- प्रति १०० मन पर टैक्स लगता था। जलाने वाली लकड़ी दो प्रकार की होती थी— कुन्द और ओहिला जिन पर टैक्स की दर १०० मन पर क्रमश ३/- और ४/- था।

11 बनारस रेजीडेन्सी रेकार्ड २३ अक्टूबर १७८६ पृष्ठ २५ एवं वही— १७ जून १७८७—पृष्ठ ३८६

12 वही— पृष्ठ ६२-६६ (अक्टूबर १७८६)

चेतसिंह के समय में पत्थर और लकड़ी महल पर किराया अत्यधिक बढ़ गया। यह १६,०००/—रु० से ६४,०००/—रु० हो गया।

जहाँ तक पत्थर के ऊपर टैक्स लगाने का प्रश्न है वह स्थानीय खदानों को पहाड़ी स्थानों के पास होने पर सम्भव नहीं था। किले के पास से जल मार्ग द्वारा जाने वाले पत्थरों पर टैक्स लगता था। बनारस पहुँचने पर बेचने पर दूसरा टैक्स अदा करना पड़ता था। यह टैक्स राहदारी के रूप में वसूल होता था। यदि पत्थर पटना तक भेजा जाता था तो पहले इस पर चुनार के किलेदार द्वारा टैक्स लगाया जाता था और तत्पश्चात् बनारस के सेयर अधिकारी द्वारा टैक्स लगाया जाता था। बनारस में टैक्स लेने वाली एजेन्सियाँ थीं। किलेदार नवाब सुजाउद्दौला की जगह पर था और बनारस पर बलवन्त सिंह का अधिकार था।

लेकिन जो पत्थर किले के पास से नहीं जाता था किलेदार को उस पर कोई टैक्स वसूल करने का हक नहीं था। इमारत बनाने वाले पत्थरों पर टैक्स नहीं लिया जाता था। किन्तु कारखानों वाले तथा छोटे बड़े गोल पत्थरों पर चुनार में किले के टैक्स से सम्बन्धित टैक्स लिया जाता था।¹³

चुनार के किले पर अंग्रेजी आधिपत्य हो जाने के पश्चात् किलेदार का हिस्सा किले की सैनिक राशि में जुड़ गया था। सेना के लिए टैक्स वसूलने वाले सैनिकों का काम किले के आस-पास खानों से निकाले गये पत्थरों के ऊपर टैक्स लगाने तक ही सीमित नहीं था बल्कि वे बन्दूक लेकर दूर-दूर तक घूमते और अत्याचार करते थे। नवम्बर १७७६ में

¹³ वही पृष्ठ ६२-६६

इसकी सूचना डकन द्वारा सरकार को दी गई। एक वर्ष के पश्चात् सरकार द्वारा आदेश मिला कि पत्थर महल का लाभ सैनिक राशि में मिलाया जाय। किसानों को चेतावनी दी गई कि चेतसिंह को निकाले जाने से पूर्व की कीमत से अधिक कीमत की माँग के पत्थर के लिए न करे। घरों में प्रयोग होने वाले पत्थर पर पहले वाला दर ही लागू रहेगा। जलाने वाली लकड़ी और लकड़ी महल पर टैक्स समाप्त हो गया। १ नवम्बर १७८८ से अन्य प्रकार की लकड़ियों पर जो प्रान्त में एक भाग से दूसरे भाग को भेजा जाता था उस पर टैक्स लिया जाता था।

मई १७६३ में किसान ने पत्थर महल के ५० प्रतिशत नये निकाले गये खान के पत्थर पर टैक्स का दावा किया और ३३ प्रतिशत उस पत्थर का जो प्रान्त के किसी भाग में खडहर से निकाला जाता था।¹⁴

काँच पर एकाधिकार

काँच की बिक्री का अधिकार प्रान्त में पूर्णरूपेण सिक्का ढालने वाले बनारस के मालिक को दे दिया गया। इस महल की कीमत प्रान्त में बहुत अधिक हो गयी। ११ अगस्त १७८६ की अपनी रिपोर्ट में डकन ने इसे समाप्त करने की सिफारिश किया जिसे सरकार ने स्वीकार कर लिया।¹⁵

सोना एकाधिकार

¹⁴ वही — पृष्ठ ६२-६६

¹⁵ बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स—११ अगस्त १७८६ पृष्ठ— ७७-७८

सर्व प्रथम सोना एकाधिकार राजा बलवन्त सिंह द्वारा उनके एक निकटतम व्यक्ति को दिया गया, जिसके अनुसार सोना पर जो सौदागर धार्मिक संस्थाओं द्वारा इस व्यापार में लगे थे उन पर टैक्स लेना निश्चित हुआ था। बाद में यह लाइसेन्स मोनोपली के रूप में बदल दी गई। जब सन्यासी सौदागरो ने नेपाल में अपना व्यापार बन्द किया तो किसान को राजा से अलग सुविधाओं पर अधिकार का आदेश मिला। बालों की सिफारिश पर २६ दिसम्बर १७८७ को सरकार को भेजे अन्य मॉगों के साथ सोना पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया।¹⁶

पूर्वी उत्तर प्रदेश में चुंगी व्यवस्था

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस जनपद देश के विभिन्न व्यापारिक केन्द्रों के बीच बसे होने के कारण सर्वाधिक सम्पन्न एवं महत्वपूर्ण था। अधिकांश व्यापार बनारस और उससे सम्बद्ध जिलों द्वारा ही किया जाता था। अन्य व्यापारिक केन्द्रों में बंगाल, बिहार, पश्चिम प्रदेश, दक्षिण, उत्तरी प्रदेश मुख्य था। एक समय ऐसा भी था जब कि मिर्जापुर शहर में दक्षिण और पश्चिमी प्रदेशों के व्यापारी अपना सामान लाकर बेचते थे और नेपाल तथा तिब्बत देश की सामग्रियाँ खरीदते थे।¹⁷ कपास, नमक तथा सस्ती भारी वस्तुओं का मुख्य रूप से आयात होता था। रेशम, चौड़े कपड़े और मसालों का निर्यात होता था। इस व्यापार का लाभ सम्बन्धित स्थानों के अतिरिक्त बंगाल को भी होता था जो इन वस्तुओं की आपूर्ति करता था।

¹⁶ ओल्डम्— पृष्ठ उद्धृत — पृष्ठ २११

¹⁷ राजकीय अभिलेखागार यू०पी०—रेजिडेन्स करसर्पॉन्डेन्स २४ अगस्त १७८७, पृष्ठ ३३-३५

बलवन्त सिंह ने पूर्णरूप से इस व्यापार की महत्ता को समझा और यह व्यापार उनके समय में उन्नति के शिखर पर था। बलवन्त सिंह के बाद उसके पुत्र चेतसिंह की उदासीनता के कारण १७८१ में मिर्जापुर के व्यापार में काफी गिरावट आयी।¹⁸

१७७३ के पूर्व आयात और निर्यात पर जो टैक्स लगता था वह माल के वजन पर लगता था। १७७२ में हैस्टिंग्स ने कुछ वस्तुओं को इस टैक्स से मुक्त कर दिया किन्तु इसकी व्यवस्था मात्र २ नवम्बर १७८१ तक ही थी। तत्पश्चात् बनारस, गाजीपुर और मिर्जापुर में ही चुगीघर स्थापित करने का आदेश हुआ। जहाँ पर टैक्स पुस्तिका में निर्धारित ५ प्रतिशत मूल्य की दर से टैक्स वसूलने का निर्णय लिया गया।¹⁹ किन्तु यह नियम कुछ ही मालों पर लागू हुआ। व्यापारी प्रदेश के प्रत्येक भाग में चुगीघर खुल जाने से अत्यधिक नाराज थे।²⁰ ८ अप्रैल १७८२ के आदेशानुसार आयात की जाने वाली विभिन्न वस्तुओं पर टैक्स घटा कर ढाई प्रतिशत कर दिया गया। २१ अक्टूबर १७८१ में सरकार द्वारा टैक्स नियम में हुए परिवर्तन के अनुसार यह आदेश रेशम और रेशम से बने दूसरे माल पर भी लागू कर दिया गया। खाली नावों पर टैक्स बन्द करने का भी आदेश हुआ।²¹

१७८१ की भौति १७८४ के नियम का भी उचित ढंग से पालन नहीं होता था। देश के भीतरी भागों में चुगी भूमि मालिकों और किसानों द्वारा

18 सीक्रेट सेलेक्ट कमेटी रिपोर्ट, नवम्बर २३, १७८४ पृष्ठ—१११७

19 वही—पूर्व उद्धृत

20 बंगाल रेग्यूलेशन—ऐपेन्डिक्स (१) पृष्ठ २१७

21 वही— पृष्ठ २१८

अपने आश्रित चुगीघरो से पूरे देश में लिया जाता था। मिर्जापुर में भी खाली नावों पर टैक्स वसूलने की मनाही कर दी गई। रेशम पर निर्धारित सवा दो प्रतिशत टैक्स वसूलने की अवहेलना की जाती थी। फलतः नये टैक्स के कारण व्यापार पर बोझ बढ़ गया। बनारस के रास्ते माल आना बन्द हो गया।²²

उक्त परिस्थितियों पर विचारोपरान्त गर्वनर जनरल जी० आर० बालो ने व्यापार में गिरावट के कारणों की जाँच कराने का आदेश दिया तथा सुझाव प्रस्तुत करने को कहा जिससे बनारस और कम्पनी के बीच व्यापार करने वाले व्यापारियों को अधिक सुरक्षा प्राप्त हो सके। बालो ने विस्तृत रूप से परिस्थितियों का निरीक्षण करके व्यापार को पुनः प्रारम्भ करने की अनेक सिफारिश की।²³ बालो ने अपनी सिफारिश में लिखा कि चेतसिंह के समय में बैल पर लदे बोझों पर १७७३ की व्यवस्था के अनुसार टैक्स लगता था। दर निश्चित करने में वस्तुओं के मूल्य से अधिक वजन पर ध्यान दिया जाता था। इस लिए अधिक कीमती सामानों से घटिया माल पर टैक्स के अनुसार ही अधिक टैक्स ले लिया जाता था।²⁴ १७८१ के अध्यादेश से बगाल की कीमती वस्तु पर बनारस के टैक्स रजिस्टर में दर्ज टैक्स की दरों से ५ प्रतिशत अधिक लिया जाता था। इस प्रकार सौदागरों के प्रति बैल भार सौ के बजाय २०/-रु० या २५/-रु० जो वे पहले देते थे, लिया जाता था। कच्चा रेशम और रेशम के सामान निर्यात करने वालों को अधिक नुकसान था। उन लोगों ने इन चीजों को बाहर

²² वही—

²³ वही—२४ अगस्त, १७८७ पृष्ठ ३५ (जी०एच० बालो रिपोर्ट)

²⁴ वही—पृष्ठ

भेजना बन्द कर दिया था। अधिक खर्च करके और खतरा मोल लेकर वे बिहार के दक्षिणी पहाड़ियों में ले जाते थे जिससे निर्यात अत्यधिक कम हो गया और टैक्स का नुकसान हो गया।

सौदागरों के आवेदन पर बनारस के रेजीडेन्ट मारखम को कच्चे रेशम पर लगे टैक्स को ५ प्रतिशत के स्थान पर ढाई प्रतिशत करने पर बाध्य होना पड़ा। इस परिवर्तन को २० मार्च, १७८२ में सरकार की स्वीकृति प्राप्त हो गई। परिषद् ने वारेन हैस्टिंग्स की सिफारिश पर यह सुविधा अक्टूबर १७८४ को बंगाल की रेशम की वस्तुओं के संदर्भ में भी दिया।²⁵ ऐसा लगता है कि जिन सिद्धान्तों के ऊपर यह छूट स्वीकृत की गई थी वह सबसे अच्छी व्यापारिक नीति थी। इस नीति से प्रान्त को अपने कच्चे माल तथा स्वनिर्मित माल के निर्यात हेतु प्रोत्साहन मिलता था।²⁶ किन्तु चुंगी घरों की रसीदों को देखने से ज्ञात होता है कि टैक्स सम्बन्धी आदेशों की अवहेलना करते हुए ५ प्रतिशत टैक्स रेशम माल पर पूर्ववत् लिया जाता था।

प्रधान सौदागर जो बंगाल से दक्षिण तक व्यापार करते थे सन्यासी कहलाते थे। यह लोग बनारस तथा कम्पनी राज्य में रहते थे। सन्यासी सौदागरों को बंगाल से सामान खरीदकर मिर्जापुर भेजते थे जहाँ से उस माल को या तो अपनी जाति के सौदागरों को, जो दक्षिण से आते थे दे देते थे या फिर बँच देते थे।²⁷ १७८१ में चुंगी घरों के स्थापित हो जाने से

25. वही पृष्ठ ३६.

26. साइनासिस, ऐ रिलिजस सेक्ट फेमस फार देयर वेल्थ एन्ड इन्टिग्रिटी इन कामर्शियल ट्रान्जिक्सन,

27. बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपान्डेन्स,—२४ अगस्त १७८६. पृष्ठ—३६.

सन्यासी सौदागरो ने यह कहकर बनारस में व्यापार करना छोड़ दिया कि ५ प्रतिशत टैक्स पुस्तक में दर्ज दर से अधिक है जिससे उन्हें नुकसान होता है। अधिक नुकसान और असुविधा के कारण वे अपने माल को पहाड़ियों के रास्ते भेजने लगे। राजा के नायक जगत देव सिंह को प्रार्थना पत्र देकर उन्होंने टैक्स में कमी करने के लिए आवेदन किया। इस पर विचारोपरान्त कच्चे रेशम पर ढाई प्रतिशत टैक्स का निश्चय किया गया। टैक्स की इस कमी का प्रभाव सन्यासी सौदागरो के लिए लाभप्रद सिद्ध हुआ। अन्ततोगत्वा उनके व्यापार में वृद्धि होनी प्रारम्भ हो गई।²⁸

इन करों के अतिरिक्त अन्य अनियमितताओं एवं अनुचित माँगों के कारण व्यापारी असन्तुष्ट थे। टैक्स मिर्जापुर में दिये जाने के कारण दक्षिण और बगाल के सौदागर प्रायः मिर्जापुर में ही अपने माल को बेच कर अपने प्रान्त लौट जाते थे। १७८८ के अध्यादेश की धारा-४ के अनुसार जो खन्ना एक बार बनारस, गाजीपुर, या मिर्जापुर के चुगीघरों में मजूर हो जाता था वह प्रान्त के एक छोर से दूसरे छोर तक स्थल या जल मार्ग से माल ले जाने के काम आता था। टैक्स अधिकारी उस पर केवल अपना हस्ताक्षर कर देते थे और किसी प्रकार का टैक्स नहीं लेते थे।²⁹ किन्तु इसके विपरीत मिर्जापुर में प्रत्येक बैल पर जो व्यापारी दक्षिण से आते थे और जो बगाल और बनारस आकर माल खरीदते थे उनसे ५ प्रतिशत टैक्स लिया जाता था।³⁰ उसी प्रकार बगाल से बाहर जाने वाले कच्चे माल और रेशम तथा उससे निर्मित कपड़े पर जो बनारस, गाजीपुर और अब

28 वही— पृष्ठ ३६ (ए) एवं जे० एम० घोष, 'सन्यासी एण्ड फकीर रेडर्स इन बगाल' पृष्ठ १६

29 वही—पृष्ठ ३७

30 वही—पृष्ठ ३८

दक्षिण में बिकता था उस पर पुन मिर्जापुर में प्रत्येक लदे बैल पर टैक्स देना पड़ता था।

ऐसा प्रतीत होता था कि २१ अक्टूबर १७८४ का पत्र जो वारेन हैस्टिंग्स ने लिखा था वह पुराना हो गया और ग्यारहवीं धारा के अनुसार टैक्स मात्र खाली नावों पर बन्द था किन्तु फिर भी अन्य प्रकार के शुल्क चलते रहे। ऐसी अनियमितताओं से सभी सौदागरों पर बुरा प्रभाव पड़ा। इस सम्बन्ध में कोई उचित कदम नहीं उठाया गया। माल के माप हेतु कोई वैज्ञानिक स्तर न होने के कारण कर लगाना चुगी अधिकारियों पर निर्भर था। टैक्स वसूलने के अनेक तरीके थे। कुछ मामलों में व्यापारियों के सामान के मूल्य के लिए सौगन्ध लेना पड़ता था और अन्य मामलों में प्रचलित मूल्य के ऊपर टैक्स लिया जाता था। कुछ पर तौल के अनुसार भी टैक्स लगता था। सबसे साधारण तरीका दर वाली पुस्तक से ही निर्धारित किया जाता था।³¹ टैक्स का पहला नियम आपत्तिजनक था क्योंकि सौगन्ध लेने मात्र से सामान का उपयुक्त मूल्य नहीं जाना जा सकता था। दूसरा टैक्स अधिकारियों के ऊपर निर्भर था जो बेईमानी और अन्याय भी कर सकते थे। तीसरे तरीके से सौदागरों को आपत्ति होती थी। कीमती वस्तुओं पर बढ़ा हुआ टैक्स अधिकारियों के मन में लालच पैदा कर सकता था। तौलने की फीस, दूकान टैक्स तथा चौकियों द्वारा छोटी छोटी क्रय-विक्रय की वस्तुओं पर लगने वाले टैक्स से व्यापारी असन्तुष्ट एवं परेशान थे।³² यद्यपि देश के भीतरी भागों में टैक्स कम था

³¹ वही—

³² वही—

किन्तु वास्तविकता यह थी कि व्यापारियों को अपना सामान इच्छित स्थान पर पहुँचाने के लिए काफी भार सहना पड़ता था।³³

सरकार द्वारा प्रतिबन्धित होने के बाद भी जमींदारी टैक्स, प्रत्येक जिले में बराबर वसूल होता रहा। यदि सौदागर टैक्स देने से मना कर देता था तो जमींदार उसके माल को जबरदस्ती ले लेता था। उदाहरणार्थ सैदपुर के एक व्यापारी द्वारा जमींदारी टैक्स न दिये जाने पर वहाँ के जमींदार ने उसके पीतल के बर्तन छीन लिये।³⁴

सन्यासी सौदागरों के सामान के एक बड़े भाग पर जो, दक्षिण और दूसरे देशों से लौटते थे, टैक्स लगता था। यह बनारस से मुर्शिदाबाद तक चुकाया जाता था। कोशल चन्द्र नाम के एक दलाल को ६००/-रु० तक के बिल पर राजा की ओर से बातचीत करने का अधिकार प्राप्त था।

सोना महल के नाम पर सोना टैक्स वसूल होता था। इस टैक्स की वसूली के लिए प्रभावी दलाल कार्य करते थे। किन्तु कुछ समय बाद ये दलाल किसान बना दिये गये। नेपाल निवासियों ने काठमान्डू के राजा को गद्दी से उतारने के लिए गोरखा के राजा पृथ्वीनारायण को बुलवाया। कुछ मुख्य सन्यासी सौदागरों के माल को राज में लौटा लिया। फलतः उन्होंने इस देश में व्यापार करना छोड़ दिया। यद्यपि सोने का निर्यात बन्द हो गया किन्तु फिर भी बनारस के बैंक में सन्यासियों से सभी माल पर टैक्स लिया जाता था। टैक्स लगाने की यह प्रणाली बड़ी कष्टकर थी। बैंक के लोगों को व्यापारियों का बिल स्वीकार करने की मनाही थी।

³³ शेक्सपीयर्स— पूर्व उद्धृत जिल्द (दो) पृष्ठ— ४६

³⁴ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपान्डेन्स—२४ अगस्त १७८७—पृष्ठ २५

ऐसा सोना महल के माध्यम से न आने पर होता था। यदि सन्यासी सौदागर को बिल मुर्शिदाबाद ले जाना होता था तो वह पहले किसान को प्रार्थना पत्र देता था जो उसे बदलने के लिए निश्चय करता था और फिर स्वयं टैक्स लेता था। सौदागरो ने इस टैक्स का विरोध करते हुए बन्द करने का आग्रह किया। उन्होंने प्रार्थना किया।³⁵

(१) सोना महल द्वारा टैक्स की वसूली बन्द कर दी जाय तथा अन्य सौदागरो की भौति उन्हे भी अपने बिल के लिए आज्ञा दी जाय।

(२) परिषद् की आज्ञा से रेशम पर ढाई प्रतिशत टैक्स घटा दिया जाय।

(३) सामान जो बगाल से बेचने के लिए लाया जाय और एक बार उस पर टैक्स दे दिया जाय तो फिर जब दक्षिण में वह सामान बेचा जाय तो मिर्जापुर में उस पर पुन टैक्स न देना पड़े और टैक्स अधिकारी खन्ना पर लिख दे तथा दूसरे किसी प्रकार के शुल्क की माँग न करे।

(४) १७८४ के धारा ४ के अनुसार प्रत्येक नाव पर जो उनके सामान को मिर्जापुर से बगाल ले जाने के लिए भाड़े पर ली जाती थी सवा छ प्रतिशत का अनिवार्य टैक्स बन्द कर दिया जाय।

(५) बरार और नागपुर के द्वारा माल भेजने पर मिर्जापुर में प्रत्येक बैल पर छ आने का जो टैक्स लगता था उसे बन्द कर दिया जाय।

35 वही पृष्ठ-४०-४१, एव जे० एम० घोष, -सन्यासी एण्ड फकीर रेडर्स' इन बगाल (कलकत्ता १६३०) पृष्ठ-१६

“कोशल एक मध्यस्थ (दलाल) था जो राजा की ओर से अधिकृत किया गया था पूर्ण वार्ता के उपरान्त उचित निर्णय लेने के लिए।” (देखिये- वी० आर० सी० पृष्ठ-४०-४१)

(६) रेशमी माल की तौल करने में प्रत्येक बैल पर टैक्स अधिकारी को जो शुल्क देना पड़ता था उसे बन्द किया जाय।

(७) नाव की तलाशी लेने वालों को जो सवा रूपया अतिरिक्त शुल्क दिया जाता है उसे बन्द किया जाय।

(८) डाकुओं से माल की रक्षा के लिए मिर्जापुर के कोतवाल को आदेश दिया जाय।

(९) कश्मीर से खरीदे गये रेशमी शाल के माल पर जिस पर दलाल की मुहर लगी होती थी, टैक्स न लगाया जाय।

उक्त आवेदन के प्रथम आठ माग को सरकार ने पहले ही मान लिया था। अन्तिम नवे माँग के सम्बन्ध में डकन ने सिफारिश किया कि यह घटा कर ढाई प्रतिशत कर दिया जाय। किन्तु उस सामान का मूल्य विदेशी सामान की ही भाँति आँका जाय। कश्मीर के व्यापार को प्रोत्साहन देने के लिए ऐसा किया गया था। पिछले कई वर्षों से अधिक टैक्स और अन्याय के कारण कश्मीर का व्यापार गिरता जा रहा था।

टैक्स में कठोरता बरतने के कारण बंगाल के व्यापार पर बुरा प्रभाव पड़ा। बंगाल के बने जो सामान योरप जाते थे उसकी माँग कम होने लगी। देश के भीतरी भागों में सामान पहुँचते-पहुँचते उस पर इतना अधिक टैक्स लग जाता था कि जनता उसे खरीद नहीं पाती थी। फलस्वरूप व्यापारियों ने सामान बेचना बन्द कर दिया। व्यापार में आई गिरावट का प्रभाव कृषि और सामान उत्पादकों पर पड़ा और लोग बेकार

हो गये। अदालत के प्रभाव में व्यापारियों और अधिकारियों के बीच उत्पन्न झगड़े का निपटारा करना कठिन हो गया।³⁶

उक्त बुराइयों को दूर करने की दृष्टि से बालों ने ऐसे परामर्श दिये जो टैक्स निर्धारित करने और सरकारी आदेश के पालन करने में सहायक थे। उन्होंने सिफारिश किया कि बनारस में उपयोग के लिए बिहार और बंगाल से जो माल आता है उस पर ढाई प्रतिशत टैक्स कर दिया जाय और देश के भीतर व्यापार पर ५ प्रतिशत ही जारी रखा जाय। इस सिफारिश का मुख्य ध्येय कम्पनी के निर्यात को पूर्णतः सुरक्षित रखना था। इसी प्रकार की सुविधा बनारस में रवन्ना में भी की गई। इसका उद्देश्य पहले के व्यापार को प्रोत्साहित करना भी था।

अवध के नवाब वजीर को भी इस प्रबन्ध को मान लेने की सिफारिश की गई थी जिससे तीन देशों को एक ही प्रकार का व्यापारिक लाभ प्राप्त हो सके।³⁷

बालों ने यह भी सिफारिश किया कि अपने देश में निर्यात का मूल्य निर्धारित करने के लिए राजा द्वारा प्रत्येक व्यक्ति को यह अनिवार्य रूप से आदेश दिया जाय कि वे रवन्ना के लिए प्रार्थनापत्र देने के लिए सामान का बीजक प्रस्तुत करें जिसके आधार पर उनके माल पर टैक्स निर्धारित किया जा सके। बीजक (चालान) राजा की मुहर लग जाने पर वापस हो जाता था। सिफारिश में यह भी कहा गया कि दकन से आयात होने वाले सामान पर बनारस के निर्यात की ही भाँति मूल्य आका जाय। मिर्जापुर

³⁶ वही—

³⁷ वही—२६ मार्च १७८८—पृष्ठ ८६

पहुँचने पर व्यापारी अपने सामान के मूल्य का विवरण दे और उसी आधार पर टैक्स निर्धारित किया जाय।³⁸

उपरोक्त नियमों की पुष्टि के लिए तथा व्यापारियों के जान-माल की रक्षा के लिए मिर्जापुर में रेजीडेन्ट के सहायक की नियुक्ति हेतु बालों ने सिफारिश किया। जमींदारी के अन्दर व्यापार सम्बन्धी सम्पूर्ण सूचना प्राप्त करने के लिए बनारस में नियमित न्यायालय की स्थापना हेतु भी निवेदन किया गया।³⁹

२६ जून १७८७ को बालों की सिफारिशें परिषद् द्वारा स्वीकार कर ली गईं और उन्हें लागू करने के लिए डकन को आदेश दिया गया। किन्तु डकन ने इससे पूर्व ही सन्यासी सौदागरों के हित एवं अहित सम्बन्धी निर्णय ले लिया था। उन्होंने पहले ही कच्चे रेशम तथा बिहार और बंगाल के सूती माल पर टैक्स घटाने की आज्ञा दे दी थी।⁴⁰

डकन ने मिर्जापुर के खेतों की जुताई पर लिये जाने वाले दुगने टैक्स, नावों के किराये पर लेने पर लगने वाले टैक्स को समाप्त करने का प्रयत्न किया। इसके अतिरिक्त सौदागरों के सम्पत्ति की डाकुओं द्वारा रक्षा के लिए आवश्यक कदम उठाये गये।⁴¹ डकन ने हाउस टैक्स और देश के भीतर व्यापार पर लगने वाले टैक्स को सीमित करने का प्रयत्न किया। उन वस्तुओं पर जो बनारस जिले से होकर आयात निर्यात होता था, मिर्जापुर में व्यापार पर लगने वाले दुगने टैक्स को बन्द करने का भी

38 वही पृष्ठ-८८

39 वही- पृष्ठ-८८

40 वही-पृष्ठ-८८

41 वही पृष्ठ-६०

प्रयास हुआ। दकन के सौदागरो की प्रर्थना पर तौल की फीस 'खजाना रसूल' भी बन्द करने की सिफारिश की गई।⁴²

माराठा तीर्थयात्रियो की बराबरी पर लाने के उद्देश्य से बगाल के तीर्थयात्रियो पर लगाये जाने वाले टैक्स को समाप्त कर दिया गया। उल्लेखनीय है कि माराठा तीर्थ यात्रियो को वारेन हैस्टिंग्स के समय मे ही टैक्स से मुक्त कर दिया गया था।⁴³ १८ मार्च १७८८ को रेजीडेन्ट ने सरकार के आदेश को कार्यरूप प्रदान करने की सूचना दिया। इस आशय के आदेश भी जारी किये गये कि रवन्ना अन्य प्रान्तो के सरकारी टैक्स कलेक्टरो की ही भाँति दिया जाय। इस कार्य के लिए उन्हे रवन्ना के प्रपत्र तथा मुहरो के नये सेट दिये गये। मुख्य अध्यक्ष होने के नाते राजा की मुहर भी बगाल एव बिहार मे कम्पनी दीवानी की भाति लगानी पडती थी। दूसरे प्रान्तो के सरकारी टैक्स कलेक्टरो की तरह राजा के अधिकारियो को भी रजिस्टर रखना पडता था।

कम्पनी सीमा के निर्यात पर जो माल बनारस से गुजरता था और दकन या पश्चिम जाता था या उपभोग के लिए इस जिले मे निर्यात होता था उस पर ढाई प्रतिशत टैक्स कम लगता था। बगाल, बिहार और उडीसा को छोड कर पश्चिम, दकन तथा अन्य बाजारो से होकर यहाँ उपयोग के लिए होने वाले निर्यात पर जो टैक्स यहाँ के लिए निर्धारित था वही देना पडता था।⁴⁴

⁴² वही—पृष्ठ—६१

⁴³ वही—पृष्ठ ६३, ६५, ६७

⁴⁴ बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स, २७ सितम्बर १७८७ पृष्ठ—२६६

रेजीडेंट ने सरकार को विश्वास दिलाया कि वह देश के आन्तरिक टैक्स को समाप्त करने का प्रयत्न करेगा। इससे होने वाली क्षति की पूर्ति राजा को सालाना लगान से काट कर करने का आदेश दिया गया।

५ प्रतिशत भारी टैक्स आन्तरिक व्यापार पर बड़ा भार था जिससे कम्पनी तथा राजा बनारस को भारी हानि थी। अतः डकन ने निर्यात के ऊपर ५ प्रतिशत से ढाई प्रतिशत टैक्स बनारस में बने माल पर कर दिये जाने की सरकार को परामर्श दिया जिससे बनारस के उद्योग को प्रोत्साहन मिले।⁴⁵

उक्त सभी प्रस्ताव सरकार ने स्वीकार कर लिया। सरकार के इस आदेश के अनुसार १ अप्रैल १७८८ को जो धारा सम्पूर्ण प्रान्त में लागू होने वाली थी उसको समाप्त कर दिया गया। फलतः बनारस के टैक्सघरों का टैक्स जो ₹० ३२, ६०३-४-६ था वह समाप्त हो गया। इसमें ४ या ५ हजार रुपये जोड़ दिये गये जिसे राजा राहदारी और गनी के रूप में⁴⁶ एकत्रित करते थे। आन्तरिक टैक्स की समाप्ति के कारण राजा के धन से जो कटौती प्रारम्भ हुई उसके सम्बन्ध में विवाद उत्पन्न हो गया। राजा ने अपने अधिकार के लिए दावा करते हुए रेजीडेंट से प्रार्थना किया कि उसे कुछ धन भत्ता के रूप में देकर उसके साथ न्याय किया जाय। २२ नवम्बर १७८१ की धारा के अनुसार वास्तव में राजा को अपने अधिकार से वंचित होना पड़ा था। उक्त धारा के अनुसार वह गाजीपुर, मिर्जापुर, और बनारस में टैक्स वसूली हेतु चौकियाँ बना सकता था जबकि उसने देश में

⁴⁵ वही—

⁴⁶ वही पृष्ठ—५६

अनेक छोटी-छोटी टैक्स चौकिया बना ली थी। किन्तु फिर भी राजा को आन्तरिक अनाज के ले जाने पर दो वर्ष तक के लिए १२, ७०७ रू० की छूट दी गई।⁴⁷ राजा और सरकार की क्षति में कमी लाने के उद्देश्य से डकन ने चुगी घरों के कार्यालय के खर्च पर व्यक्तिगत नियंत्रण स्थापित किया। कर्मचारियों की संख्या १२१२ से घटाकर ३६५ कर दी गई। फलतः खर्च रू० ५७, २२०-११-६ से घट कर रू० ३१४८६-०० मात्र रह गया। सन्यासी, इराकी और पजाबी सौदागरों के लिए अलग-अलग स्थापित चुगीघर समाप्त कर दिये गये।⁴⁸

डकन ने व्यापारिक न्याय के लिए सरकार से अदालत की स्थापना हेतु प्रार्थना किया। आन्तरिक टैक्स की वसूली के सन्दर्भ में धारा का जो उल्लंघन होता था - उसके लिए विशेष रूप से डकन सरकार से यह जानकारी प्राप्त करना चाहता था कि बनारस सहित चारों अदालतों के न्यायधीशों को कौन-कौन से अधिकार प्राप्त हैं। डकन ने यह भी संकेत किया कि व्यापारिक न्याय के लिए दूर के अदालत में जाने की अपेक्षा पड़ोस के अदालत में जाना व्यापारी के लिए अधिक सुविधाजनक होगा। अदालतों की अपील व्यापारिक न्यायालय के अध्यक्ष रेजीडेन्ट के यहाँ होती थी।⁴⁹

धारा के सन्दर्भ में ११ जून १७८८ को परिषद् ने डकन के प्रस्ताव पर अपनी सहमति दे दिया। परिषद् इस बात पर सहमत हो गया कि कम्पनी प्रान्त से जो माल बनारस होता हुआ वजीर के प्रमुख राज्य डकन

47 वही- पृष्ठ ५६

48 वही-पृष्ठ-५६-५७

49 वही पृष्ठ- २०६

या दूसरे देशों को भेजा जाये उस पर तुरन्त कम्पनी के रवन्ना मूल्य ढाई प्रतिशत की कमी कर दी जाय। अन्य योजना तथा व्यापार न्यायालय और उसकी धारा को भी सरकार ने स्वीकृत कर लिया। कामो में लापरवाही, चुगीघर के अधिकारियों के दुर्यवहार, राहदरी, गनी तथा चुगी विभाग से सम्बन्धित अन्य धारा के विरुद्ध की गई शिकायतों को अदालत सुनती थी।⁵⁰

गाजीपुर के चुगीघर के मालिक की प्रार्थना पर जो माल बनारस में कम्पनी की रवन्ना पर आयात होता था वह प्रायः तौल और सख्या में अधिक होता था जो उस पर दर्ज होता था। रेजीडेन्ट ने १७ जून १७८८ को सरकार को इस सन्दर्भ में रिपोर्ट किया कि ६ जून १७८८ का अधिनियम स्पष्ट नहीं है। अतः सरकार का अगला आदेश आने तक उन्होंने बचे हुए सभी आयात माल पर दोगुना टैक्स वसूली का आदेश दे दिया जो बंगाल एवं बिहार से आये थे और सब पर रवन्ना देने का भी आदेश दिया। यह देखा गया कि बहुत से मालों पर रवन्ना नहीं लगा था। चुगीघर के अधिकारियों को ये जानने में कठिनाई हुई कि बंगाल और बिहार से आयात किये गये माल पर चुगी लेना है अथवा नहीं। चुगी में व्याप्त अनियमितताओं और अन्तर को रोकने के लिए चुगीदर की सूची में उन्होंने परिषद् को सम्पूर्ण क्षेत्र के लिए जिसमें बंगाल, बिहार, और बनारस आता था, एक पृथक् चुगीघर बनाने की सम्मति दी। उन्होंने यह भी सम्मति दी कि जब रवन्ना में दर्ज से अधिक माल आयात हो तो पूरा भेजा हुआ माल ले लिया जाय। इसके विपरीत बनारस तथा बिहार क्षेत्र से

⁵⁰ वही— ११ जून १७८८, पृष्ठ—६२—६३

आयात किये हुए माल में जो अधिक होता था ले लिया जाता था। किन्तु उनकी अलग चुगीघर बनाने पर परिषद् ने सहमति नहीं दिया।⁵¹

बनारस और बगाल के तौल के मन में अन्तर पाया गया। अतः यह आवश्यक समझा गया कि बगाल और बिहार से आदर्श मन के अनुसार जहाँ से नाव का रक्कन लिया गया था टैक्स वसूल किया जाय। यह नियम उस माल के लिए जो बनारस से रक्कन सहित बगाल और बिहारके लिए जाता था आपसी सम्बन्ध के रूप में हो गया।

डकन ने घरदेवारी तथा खानाशुमारी को समाप्त करने की सिफारिश किया किन्तु कृषको द्वारा भूमि के लगान में छूट न देने की भी बात किया। उन्होंने इस आदेश के लिए एक प्रस्ताव भेजा कि चालू वर्ष में यह वसूली जारी रहे तथा अगले वर्ष में इसकी समाप्ति के लिए किसानों को बाध्य किया जाय।⁵²

घरदेवारी से सम्बन्धित भूमि के लगान को डकन ने समाप्त कर दिया। १३ जून १७८८ की अपनी रिपोर्ट में उन्होंने लिखा कि वास्तव में देश में जो भूमि घर के लिए दिये गये उन पर बनारस शहर को छोड़ कर कहीं लगान में छूट नहीं थी। कुछ भागों में उन पर उतना ही लगान लिया जाता था जितना राज्य में राजा के अधिकारियों को खेती वाली भूमि के लिए दिया जाता था। किन्तु बनारस शहर में अधिकांश घर खरीद वाली

⁵¹ वही—

⁵² वही— १३ जून १७८८, पृष्ठ—७४

जमीन पर बनाये जाते थे जिन पर किसी प्रकार का कोई टैक्स नहीं देना पड़ता था।⁵³

१२ अगस्त १७६० में अमानत महल के मूल्य में वृद्धि हुई।

अनुमान से ऐसा जान पड़ता था कि जमीन पर बने मकानों के लगान की वसूली बनारस शहर तथा उसके आस-पास के क्षेत्र में बाद में खानाशुमारी के नाम से जाना जाने लगा। डकन ने सोचा कि घरदेवारी उर्फ खानाशुमारी की वस्तुओं का टैक्स जो अनाज व्यापारी, तेली, भंडभूजो मनिहारी एवं पटवा से लिया जाता था एक सिद्धान्त है। टैक्स की दर २/- से बढ़ाकर कर ८/- प्रतिमाह कर दिया गया। खानाशुमारी शब्द के दोहरे प्रयोग से एक गलत विश्वास उठ खड़ा हुआ कि घरदेवारी टैक्स १८३५ ए० डी० में सरकार द्वारा समाप्त कर दिया गया था। उत्तर पश्चिम प्रान्त के वार्षिक लगान आय के सदस्य वी०ए० रीडे ने १८ नवम्बर १८५३ में विस्तृत अधिकृत पत्र लिख कर यह स्पष्ट किया कि गाँव के जमींदार के सम्पूर्ण प्रान्त में जमीन वाले मकान जो स्थायी बन्दोबस्त के समय बने थे, पर टैक्स लगाने के अधिकार सीमा में है। सम्भवतः उनका अनुमान ठीक था किन्तु तर्कसंगत न होकर कल्पना पर आधारित था।⁵⁴

कृषि में अच्छे तथा स्वस्थ जानवरों के प्रयोग को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से १८ फरवरी, १७८६ में घोड़ा तथा अन्य प्रकार के जानवर पर डकन ने बिक्री, खरीद, आयात, निर्यात पर से चुगी हटा दिया। इस आदेश

⁵³ वही— १३ जून १७८८, पृष्ठ—७४

⁵⁴ वही— २४ अगस्त १७८७ (एपेन्डिक्स १०)

को १६ मार्च १७८६ को सरकार की स्वीकृति मिल गई। इस समाप्ति के कारण चुगी में ६०००/- की वार्षिक क्षति हुई।

डकन ने महल चुगी को भी समाप्त कर दिया। बनारस प्रान्त में चूना, सब्जी, पत्थर, लकड़ी, शीशा एवं सोना जिनके क्रय विक्रय पर स्वतंत्र अधिकार था समाप्त कर दिया गया।⁵⁵

शहर चुँगी

सरकार को आन्तरिक चुगी और टैक्स को समाप्त करने के लिए बाध्य किया गया। यह आन्तरिक टैक्स सेवर के नाम से जाना जाता था जिसे जनता की उन्नति के लिए अन्तिम साधन के रूप में विचाराधीन रखा गया था। १० मार्च १८०१ में इसी अभिप्राय से गवर्नर जनरल ने उन सामानों पर जो बनारस के कुछ गजों में आते थे चुगी लगा दिया। बनारस में चुगीघरों की स्थापना की गई जो बनारस में आये हुए सामानों पर टैक्स वसूल करते थे। यह कार्य टैक्स कलेक्टर करता था जिसे ५ प्रतिशत दस्तूरी प्राप्त होती थी। तम्बाकू, सुपारी, लाख, मिर्च, घी, लौंग, रस्सी, सरसो तेल, मसाला, नारियलतेल, सोना, चाँदी, कच्चे रेशम, शाल, हाथीदाँत, तूतिया, सिदूर, चमड़ा, गाय तथा भैस पर ४ प्रतिशत चुगी लगायी गई।

जो सूत नवाब वजीर और राजा नेपाल के राज्य से नहीं आता था उससे बने सूती कपड़े पर २ प्रतिशत टैक्स लगाया गया। व्यापार को

⁵⁵ बनारस रेजीडेन्सी रिकार्ड—१६ मार्च १७८६, पृष्ठ—१२६

तेत्साहित और जनता के लगान में वृद्धि के लिए शहर चुगी की दर में परिवर्तन किया गया। कच्चे रेशम और सूती कपड़ों को छोड़ कर सम्पूर्ण वस्तुओं पर ढाई प्रतिशत चुगी निर्धारित की गई। बिहार प्रान्त से जो माल आता था उस पर रवन्ना में दर्ज पूरे मूल्य पर ढाई प्रतिशत टैक्स लगता था। यह आयात टैक्स पटना के चुगी घर में चुकाना पड़ता था।⁵⁶

१८०२ के अधिनियम ३ के अन्तर्गत जो माल बनारस प्रान्त में बनाये जाते थे और बिहार प्रान्त से आते थे चुगी मुक्त नहीं थे। उन्हें बनारस के चुगी घर में ढाई प्रतिशत अदा करना पड़ता था। बिहार प्रान्त से आने वाले माल पर बनारस में रवन्ना मिलता था, जिन्हें बगाल, बिहार और उड़ीसा में ले जाने पर टैक्स नहीं देना पड़ता था। वे १८०२ के अतिरिक्त अधिनियम १४ के अन्तर्गत नील बीज पर मौला, पौना, डुरमा, नामक स्थान के अतिरिक्त बिहार, बगाल, उड़ीसा प्रान्त में भी चुगी नहीं लगती थी। शहर चुगी वसूल करने के लिए गाजीपुर में चुगी घर की स्थापना अनिवार्य हो गई।

इससे असुविधा भी उत्पन्न हुई। सौदागरों को साढ़े नौ प्रतिशत अतिरिक्त चुगी देना पड़ता था। १/- प्रति रवन्ना की दर से चुगी में गलती थी।⁵⁷

कम्पनी ने बनारस में उद्योग बढ़ाने के लिए अनेक प्रयत्न किये। आयात, निर्यात पर चुगी कम कर दी गई। गैर कानूनी कार्य रोक दिये गये।

⁵⁶ बगाल रेग्युलेशन— ऐपेन्डिक्स (१) पृष्ठ—५००

⁵⁷ वही—पृष्ठ ५००—५०१

सोना महल, पत्थर महल, लकड़ी महल के कार्य रोक दिये गये। मिर्जापुर में ली जाने वाली दोगुनी चुगी, शहदरी तथा किराये के नाव पर लगाये जाने वाले टैक्स को खत्म कर दिया गया।⁵⁸ व्यापारियों के माल की सुरक्षा के लिए प्रयास किये गये। दक्षिण के व्यापारियों के माल की वर्षा से रक्षा के लिए झोपड़ियों का निर्माण कराया गया। चुगी तथा उद्योग सम्बन्धी शिकायतों की सुनवाई के लिए व्यापारिक अदालतें स्थापित की गईं। सरकार की इन नीतियों और प्रयासों के फलस्वरूप बनारस के व्यापार को अन्य प्रान्तों के समकक्ष लाने में सहायता मिली और इसका परिणाम लाभप्रद रहा।⁵⁹

नवाब अवध के साथ सुलह

नवाब अवध तथा नेपाल के राजा के साथ हुई व्यापारिक सन्धियों का व्यापार के विस्तार में मुख्य योगदान रहा है। १५ जुलाई १७८८ में नवाब वजीर के साथ हुई सन्धि की अवधि समाप्त हो गयी।⁶⁰ इस सन्धि के अनुसार जो माल कम्पनी क्षेत्र बनारस या अवध से आता था उसके साथ उन स्थानों के प्रतिनिधि अधिकारी का रवन्ना होता था। रवन्ना के ऊपर लिखे मूल्य पर टैक्स लगाया जाता था। स्पष्ट रूप से यह ध्यान रखा जाता था कि जिन वस्तुओं पर टैक्स लिया जाता था उनके मूल्य पर किसी प्रकार का विवाद न उत्पन्न हो।⁶¹ टैक्स की ठीक दर के सम्बन्ध में

58 वही— पृष्ठ— ५२७, ५२८, ५२९, ५३३

59 वही— जिल्द (१) पृष्ठ— ७४०— ७४१

60 ऐचकिसन— ट्रीटीज एण्ड सनद इन्जोमेन्ट, जिल्द (२) पृष्ठ— ६०— ६१

61 वही—

जो निश्चय किया गया उसके अनुसार कपास जो वजीर के राज्य से गुजरता था उसे बनारस में आयात टैक्स ६/- प्रति मन मूल्य पर देना पड़ता था। रेशम तथा सूती माल जो अवध में बनता था उस पर बनारस में आयात टैक्स ५ प्रतिशत के स्थान पर ढाई प्रतिशत चुकाना पड़ता था। इससे सस्ते कपास की आपूर्ति हुई तथा बगाल में सामान उत्पादकों को अच्छा बाजार मिल गया। अवध से गुजरने वाले पत्थर पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। दूसरे आयात एवं निर्यात होने वाले सामानों पर टैक्स यथावत बना रहा।⁶²

सन्धि समाप्त हो जाने पर इलाहाबाद में चुगी घरों की स्थापना हुई। लछागीर से डेढ़ कोस दूर हाल में ही बसे भदोही के पटवारीपुर में एक मुतसदी और दो चपरासी नियुक्त किये गये। यह स्थान तीन सीमाओं—कम्पनी, वजीर का राज्य और टौटेह से जुड़ा हुआ था। सीमा के अन्दर नावों को विभिन्न कठिनाइयों में बचाने के लिए ही इस कार्यालय की स्थापना की गई थी। सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत नाव के मालिकों से यदि किसी प्रकारके अवैध टैक्स लिए जाने की सूचना प्राप्त होती थी तो ऐसा करने वालों के नाम तथा नाव मालिकों के नाम आवश्यक कार्यावाही हेतु मिर्जापुर भेज दिये जाते थे।⁶³

२१ मई १७८६ को सरकार के पास एक सूचना भेजी गई जिससे ज्ञात हुआ कि वजीर नेपाल के राज्य में टैक्स घरों की गड़बड़ी एवं अनियमितताओं के कारण सौदागरों को अनेक असुविधाओं का सामना करना

62 वही — २१ नवम्बर १७८८ — पृष्ठ १६५

63 वही — २१ मई (१७८६) — पृष्ठ — ५७६-५८०

पड रहा है और सरकार को टैक्स में हॉनि हो रही है। रवन्ना की प्राप्ति में भी कठिनाई और विलम्ब होता था। लखनऊ में रह रहे रेजीडेन्ट के परामर्श से डकन बनारस के टैक्स मास्टर से मिला और व्यापारिया की शिकायतों को सुनने के बाद उसने टैक्स में व्याप्त गड़बड़ी को दूर करने के लिए टैक्स की पूर्व निर्धारित दर को ही मान्यता दिया। व्यापारिक सन्धि के अनुसार जो माल सम्बन्धित देश के रवन्ना के बिना था उन पर रवन्ना के साथ आने वाले मालो से दो गुना टैक्स लगता था।

इस सुझाव को २६ मई १७८६ को सरकार ने स्वीकार कर लिया। वजीर के रवन्ना मूल्य पर बनारस में सामान पर ८ प्रतिशत टैक्स लगता था।⁶⁴

नेपाल के साथ सुलह

ब्रिटिश के नेपाल के साथ प्रारम्भ में मात्र व्यापारिक सन्धि की ही बातचीत हुई।⁶⁵ बनारस से मसलिन, गुलदान, किमखाब, इमराल्ड, सफेद कपडा, छीट, खारा कपडा, मिर्च, चीनी, गुलाब और शाल नेपाल को निर्यात होता था। इन वस्तुओं पर निम्नवत् टैक्स लगता था।

(१) बनारस से निकलने पर ५ प्रतिशत

(२) बिहार टैक्स २ प्रतिशत

(३) सडक टैक्स २ प्रतिशत

⁶⁴ ऐंशेक्सपीयर्स-सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्ड जिल्द (दो) पृष्ठ-६३

⁶⁵ सेलेक्शन फ्राम इंग्लिश रेकार्ड- बनारस सिरीज जिल्द (दो) पृष्ठ- १६६-१७०

इस प्रकार कुल मिलाकर प्रत्येक माल पर बनारस में ६ प्रतिशत टैक्स लगता था। चवर नाफेट, मस्क, कोकीन, कपडा, मेज, सीग, शथीदात, सोने का बुरादा, कम्बल, छड और सोहागा का आयात नेपाल से होता था।⁶⁶

१ किनलाक के यात्रा की असफलता के पश्चात् लार्ड लडहौजी के समय तक नेपाल से किसी प्रकार का सम्बन्ध नहीं रहा। व्यापारिक सम्बन्ध समाप्त हो गया। हैस्टिंग्स ने नेपाल और तिब्बत से स्वतंत्र व्यापारिक बातचीत करने का प्रयत्न किया। किन्तु चीन और उसकी अदालत की कूटनीति से यह प्रयास असफल रहा।⁶⁷

सन् १७८६ में नेपाल के राजा के एजेन्ट ने कम माल पर खन्ना के लिए आवेदन किया जिसे रेजीडेन्ट ने तुरन्त स्वीकार कर लिया। ऐसा नेपाल से सम्बन्ध अच्छा बनाने के लिए किया गया।

१७६० में पुर्निया के कलेक्टर के परामर्श पर कार्नवालिस ने राजा नेपाल को एक पत्र लिख कर मिलने की इच्छा जाहिर की। पारस्परिक बातचीत के दौरान दोनों देशों में व्यापारिक उन्नति को प्रोत्साहन देने तथा बाधाओं को दूर करने का निश्चय किया गया। नेपाल की सीमा पर स्थापित चौकियों को हटा लिया गया तथा नेपाल से निर्यात होने वाले माल पर टैक्स समाप्त कर दिया गया। यद्यपि इससे कम्पनी की आय को

⁶⁶ वही—

⁶⁷ ऐचकिशन—पूर्व उद्धृत पृष्ठ—१८७

ति होना निश्चित था किन्तु इससे दोनो देशो को लाभ भी हो गया। क्षति को अन्य स्रोतो से होने वाली आमदनी से पूरा किया गया।⁶⁸

सरकार ने दोनो देशो के मध्य होने वाली व्यापारिक सन्धि पर बातचीत करने का डकन को अधिकार प्रदान किया। अधिकार और बातचीत की अवधि २१ मार्च, १७६२ को समाप्त हो गई।

इस सन्धि के अनुसार दोनो देशो के आयात माल पर ढाई प्रतिशत टैक्स निर्धारित हुआ। यह टैक्स सौदागर के पास उपलब्ध माल की रसीद की राशि पर लगता था। रसीद न उपलब्ध होने की स्थिति में चुगी अधिकारी बाजार दर के अनुसार टैक्स लगा देते थे। यदि किसी सौदागर को अपना सामान नहीं बेचना था, तो उसे यह स्वतंत्रता थी कि वह अपना माल दोनो सीमा के बाहर ले जा सकता है, तो उस माल पर कोई अतिरिक्त टैक्स नहीं लिया जाता था।⁶⁹

गोरखो की चाल से चीनीयो के साथ युद्ध में अंग्रेजो द्वारा सहायता न दिये जाने के कारण इस सन्धि का कोई महत्वपूर्ण परिणाम नहीं हुआ।⁷⁰

१७६४ में सरजान शोर ने व्यापारिक सम्बन्ध स्थापित करने के उद्देश्य से अब्दुल कादिर नामक एक व्यापारी को एक सिफारिशी पत्र

68 क्रिक पैट्रिक-एकाउन्ट आफ नेपाल-पृष्ठ २०५-२०७

‘किनलाक एक ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी यात्रा का लक्ष्य नेपाल से सम्बन्ध सुधारने का था किन्तु इनकी यात्रा की असफलता से लक्ष्य पूर्ण नहीं हो सका डलहौजी के कार्यकाल में।’
देखिये-बनारस सीरीज जिल्द (दो) पृष्ठ १६६-१७०

69 बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स- ३१ दिसम्बर (१७८६) पृष्ठ-४२३-४२४ एव पोलेटिकल लेटर्स आफ डाइरेक्टर्स ३० दिसम्बर (१७६४)

70 वही पैरा- (१३४)

लेकर नेपाल भेजा। इस विषय पर उसने डकन के ७ फरवरी १७६५ को लिखा कि व्यापार पूरी तरह नष्ट भी हो जाय तो क्षति बहुत मामूली होगी। कादिर की यात्रा में इतना अधिक विलम्ब हो गया कि राजा नेपाल अपना विरोध प्रदर्शित करने लगे। गरजार मिसिर के प्रयास करने पर कादिर को नेपाल आने का अवसर प्राप्त हो सका। किन्तु इन प्रयत्नों का विशेष परिणाम नहीं निकला।⁷¹

बाट और तौल

बनारस सूबे में प्रचलित बाट और तौल का डकन ने सुधार किया। बलवन्त सिंह के समय बनारस शहर का कोतवाल बाट और तौल का कार्य देखता था। वह पत्थर तौलता था और उसकी फीस लेता था। किन्तु जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर में कोर्ट स्थापित हो जाने के बाद तौल का कार्य कोतवाल से ले लिया गया। इस कार्य की देख रेख के लिए मोहतसीब नियुक्त हुआ जो पत्थरों के सेर और पसेरी के ऊपर अपनी मोहर लगाता था। तौल में गड़बड़ी न आने पाये उसकी वह देख रेख रखता था। बाट और तौल में गड़बड़ी साबित होजाने पर सम्बन्धित व्यक्ति को जुर्माना और दंड भुगतना पड़ता था।

बाट सम्बन्धी धोखा-धड़ी रोकने के लिए लोहे के बाट चलाये गये जिनका अदालत द्वारा प्रतिवर्ष निरीक्षण किया जाता था। यदि किसी के

⁷¹ वही— २१ जून (१७६२) पृष्ठ — (१८७-१६०) एव एच० फर्बर — प्राइवेट रेकार्ड आफ इन्डियन गर्वनर जनरलशिप — पृष्ठ ६५

पास लोहे का बाट नहीं होता था तो वह पत्थर का बाट रख सकता था किन्तु मोहर लगा हुआ ही।⁷²

‘कर आरोपित करने की प्रक्रिया एव उसके सचय के कार्य से राजकीय राजस्व में वृद्धि होती है जो राजकीय योजनाओं की पूर्ति में सहायक होते हैं। किन्तु इसी सदर्थ में यह भी कहा जा सकता है कि “अर्जित राजस्व की योजना एव कर व्यवस्था का सृजन मानव के स्तर एव उत्पादन के स्तर को ध्यान में रख कर होना चाहिए।”⁷³ भारत एक पिछड़ा हुआ देश है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष कर का जो निर्धारण अब तक हुआ है वह अत्यन्त सीमित मात्रा में एकत्र हुआ है। वास्तविकता यह है कि कर के माध्यम से राजस्व में वृद्धि की बात एक आम आदमी को जान कर एव मानकर तब सोचनी चाहिए।⁷⁴ कर देश के आर्थिक सुधार एव सामाजिक उत्थान में महत्वपूर्ण कदम होता है, साथ ही विशिष्ट प्रभाव भी डालता है। एक सुन्दर सृजित कर-व्यवस्था देश के आर्थिक सुधार में महत्वपूर्ण कदम होता है। किन्तु यदि कर व्यवस्था त्रुटिपूर्ण है तो उसका कुप्रभाव भी निश्चित होता है।⁷⁵

निसन्देह कोष राष्ट्र की परम आवश्यकता है। नीति ग्रन्थों के अनुसार कोष राष्ट्र का प्राण है। इसके बिना राष्ट्र का शरीर एक क्षण भी

72 ओल्डम-हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मोम्यार आफ बनारस डिस्ट्रिक्ट-पृष्ठ-२५-२६

73 एस० फिन्डले- साइस आफ पब्लिक फाइनेन्स पृष्ठ-४११ (मैकमिलन एण्ड कम्पनी-१९२४)

74 यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर्स बजट स्पीच फार (१९५१-५२) पैरा-५२ एव गवर्नमेन्ट आफ इण्डिया टैक्शेशन इन्क्वायरी-कमेटी रिपोर्ट (१९५४) जिल्द (१) पृष्ठ-६

75 वही- पैरा ५२

जीवित नहीं रह सकता। किन्तु जन सामान्य को उपेक्षित करके राष्ट्र का कोष भरना उचित नहीं होता।⁷⁶

बैंकिंग प्रणाली

पूर्वी उत्तर प्रदेश का तथाकथित बनारस सूबा एक क्षेत्रीय प्रशासनिक मुख्यालय था जहाँ से इस क्षेत्र के बैंक, व्यापार वाणिज्य, मुद्रा, नियंत्रित किये जाते थे। बनारस के क्षेत्रीय कुछ बैंकरो का एक विश्लेषण इस क्षेत्र के बैंकिंग प्रथा पर प्रकाश डालते है। जब हम पर्सियन पत्राचार के कैलेण्डर और पूरक पत्रो पर दृष्टि डालते है जो अनेक बैंकरो और महाजनो द्वारा हस्ताक्षरित रूप मे हैस्टिंग्स और कार्नवालिस के पास से प्रेषित किये गये थे तो हम पाते है ,वैश्य, अग्रवाल खत्री, गोसाई, और ब्राह्मण पारम्परिक रीति से इस क्षेत्र के बैंकिंग सघो को नियंत्रित कर रहे थे।

बैंकर सूची मे मुसलमानो का नाम नहीं है। इसका प्रमुख कारण यह था कि इस्लाम धर्म मे ब्याज या मूल पर होने वाले लाभ को हेय दृष्टि से देखा जाता है तथा निषेध है। इसी बाध्यता और निषेध के कारण बैंकर सूची मे मुसलमानो का नाम नहीं था। गुजरात, राजस्थान और आधुनिक उत्तर प्रदेश से सम्बन्धित अनेक बैंकर और महाजन थे। उदाहरण के रूप मे अमरोहा के साहू गोपाल दास सर्व प्रथम बैंकर थे जो बनारस मे ही निवास करते थे। वे बहुत प्रभावशाली एव उच्च सामाजिक स्तर वाले थे। कुछ बैंकर और महाजन को मुगल सम्राट द्वारा 'राजा' की भी उपधि प्राप्त

⁷⁶ माधुरी-लेख 'प्राचीन कर संग्रह' जिल्द (२) द्वारा श्रीयुत इन्द्र विद्यालकार, पृष्ठ-४३७

थी। लाला बछराज एव कश्मीरी लाल के नाम उल्लेखनीय हैं। इन दोनों के ही बनारस के नबाब और राजा के साथ वित्तीय सम्बन्ध थे। उसके पश्चात् उन्होंने कम्पनी के साथ भी अपने मधुर सम्बन्ध बनाये। उन्होंने आगे चलकर उत्तरी भारत में अपनी शाखाएँ चलाई। उनके अनेक प्रतिनिधि थे तथा फर्म की अनेक शाखाएँ थी। ये शाखाएँ कलकत्ता, लखनऊ, दिल्ली, जयपुर, बम्बई, सूरत में स्थापित थी।⁷⁷

अन्य बैंकिंग फर्मों में भैया राम गोपाल दास थे जिनके पास १७७० तक ५२ शाखाएँ थी जो भारत के विभिन्न भागों में स्थित थी। उनके मुख्य प्रतिनिधि दिल्ली, आगरा, बम्बई, कलकत्ता, पटना, लखनऊ, इलाहाबाद, नागपुर, सूरत, पूना, मद्रास, बड़ौदा, अहमदाबाद, गाजीपुर, मिर्जापुर, में थे। इनके अतिरिक्त मनोहरदास, चतुर्भुज दास ब्रजराम दास, चमनदास, त्रैलोक जी इत्यादि बैंकर थे। वे सब समाज में सम्मानित व्यक्ति थे और पूरे देश में अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अच्छा व्यवहार करते थे।⁷⁸

१८वीं शताब्दी में उपलब्ध स्रोतों और आकणों को देखने से ऐसा प्रतीत होता है कि हुण्डी एव बिल आफ एक्सचेंज की प्रथा पूर्ण विकसित

सुनियोजित कर की परिधि के अन्तर्गत वह कर आता है जो व्यक्ति की महत्वाकांक्षा से परे, भारतीय अर्थ व्यवस्था के अनुरूप—कल्याण को ध्यान में रखते हुये—स्थिर आर्थिक प्रणाली के अनुसार हो। ब्रिटिश शासन काल में मालगुजारी कम वसूल हुई। इसकी क्षतिपूर्ति के लिए अन्य स्रोतों से कर लगा कर आय में वृद्धि ही एक विकल्प है किन्तु जन सामान्य को उपेक्षित कर ऐसा सम्भव नहीं है एव अनुचित भी है। विशेष विवरण के लिए देखिये—(१) गान्धीयन ऐकानामिक थाट—पृष्ठ ५, (२) आर्थिक विचारों का इतिहास पृष्ठ ५२८, (३) ऐन इन्ट्रोडक्सन टू दी स्टडी आफ इंडियन ऐकोनामी पृष्ठ ३, (४) ऐकोनामिक स्ट्रक्चर इन फ्री इंडिया पृष्ठ ८८, (५) फाउन्डेशन आफ इंडियन ऐकोनामिक पृष्ठ ११२, (६) माधुरी—पृष्ठ ४३७

⁷⁷ मोती चन्द्र 'काशी का इतिहास'—पृष्ठ—३३६

⁷⁸ कैलेन्डर आफ पर्शियन करसपाण्डेन्स, जिल्द (७) लेटर न० ११८२

थी और इसका पालन भी नियमित ढंग से होता था। सर्राफ सिक्के बदलने एवं मुद्रा परिवर्तन करने का काम करते थे।⁷⁹

वाणिज्यिक और प्रशासकीय मुद्रा विनिमय रुपये में किये जाते थे। यह चाँदी निर्मित मुगलकालीन रुपया था। नये ढाले गये रुपये सिक्के कहलाते थे और एक साल तक मूल कीमत पर स्वीकार किये जाते थे।⁸⁰ उसके बाद पुराने सिक्के बट्टे पर लिए जाते थे। इसका मूल्य दो से ढाई के बीच था। बनारस की प्रशासकीय, सांस्कृतिक, और वाणिज्यिक प्रगति ने १७३३ में एक टकसाल की स्थापना में योगदान दिया। सोने और चाँदी के सिक्के दृढ़ता पूर्वक ढाले जाते थे। सोने के ईंट इत्यादि भी ढाले जाते थे। इस प्रकार इस क्षेत्र में एकाधिकार व्यापारिक जातियों एवं वशानुगत रूप में ही था।⁸¹

79 मिश्रा, के०पी०—‘बनारस इन ट्रान्जिक्शन’ पृष्ठ—१७१

80 इरफान हबीब — बैकिंग इन मुगल इंडिया’ (एक लेख)

81 इरफान हबीब—‘करेसी सिस्टम इन मुगल इंडिया’ जिल्द (२) पृष्ठ—२ एवं के० पी०

मिश्रा—पृष्ठ—१७६

मुख्य व्यापारिक क्षेत्र से सम्बद्ध लोगो में थे, मारवाडी, गोसाई, खत्री अग्रवाल जिन्होंने इस क्षेत्र की नागरिकता ली और शहर में रहने लगे। दृष्टव्य थामस ए० दिम्बर्ग—‘मारवारीज (दिल्ली—१६७८) पृष्ठ ४१—४३, डकन रेकार्ड्स—बस्ता—(१) रजिस्टर (१) बार्लो द्वारा गवर्नर जनरल को लिखे गये पत्र दिनांक २४ अगस्त, १६८७, के०पी० मिश्रा—पृष्ठ १७०

**भू-राजस्व व्यवस्था
भाग (१)**

भू-राजस्व व्यवस्था (भाग - १)

टोडरमल के रैयतवारी व्यवस्था के अनुसार किसानों को भूमि के क्षेत्रफल या पैदवार का आधा, जो उनकी इच्छा पर होता था, लगान देना पड़ता था। लगान वसूलने के लिए किसी मध्यस्थ की व्यवस्था नहीं थी। लगान वसूलने का कार्य प्रायः कलेक्टर करते थे जिन्हें हिसाब किताब में विशेष योग्यता प्राप्त होती थी।¹

मुगल सम्राट औरंगजेब के शासनकाल के अन्तिम चरण में यह व्यवस्था बिगड़ने लगी। उसके नये अधिकारियों में अनुभव, धैर्य और ज्ञान का अभाव था। लगान, वसूली की व्यवस्था बन्द हो गई और लगान वसूली के लिए ठेकेदारों की नियुक्ति आवश्यक समझी गई। यही ठेकेदार ही जमींदार कहे जाते थे।²

१८वीं शताब्दी में जब दीवानी का अधिकार ब्रिटिश को प्राप्त हुआ, सम्पूर्ण देश बड़े-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया और उनपर शक्तिशाली जमींदारों का आधिपत्य स्थापित हुआ। ये जमींदार लगान के ठेकेदार होते थे। इस सन्दर्भ में यह स्पष्ट करना युक्तिसंगत होगा कि राजा बनारस और कई गाँव के मालिक कहे जाने वाले लोग भी इसी प्रकार की श्रेणी में आते थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस जौनपुर, चुनार में जमींदारी प्रथा ३१

1 सी रइस्क-नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इण्डिया पृष्ठ-५३

2 वही-पृष्ठ ५३

मई १७३८ में शक्तिशाली शासकों के हाथ में आ गई। अब मुगलों के अधीनस्थ आमिल, राजा, कानूनगो, ताल्लुकदार जमींदार और रैयत द्वारा लगान वसूली का कार्य होने लगा था।^१ सभी राज्य अनेक जिलों में विभक्त थे जिनमें एक-एक मालगुजार होता था जिसे सम्पूर्ण वसूल की गई लगान का कुछ प्रतिशत 'दस्तूरी' प्राप्त होती थी। इसके बाद जमीन की नाप जोख करने के लिए अमीन होता था जो लगान भी निर्धारित करता था। इनके अतिरिक्त एक स्थाई कर्मचारी कानूनगो होता था जो आमिल और जमींदारों का हिसाब किताब रखता था।^२

सामान्यतः जमींदार का अर्थ "भू-स्वामी" अथवा 'भूधारक' से है किन्तु १८ वीं शताब्दी में 'जमींदार का अर्थ' 'मध्यस्थ' से होता था। वे लोग भी जो अन्य मध्यस्थों से लगान वसूल कर एक निश्चित राशि सरकार को भेजते थे 'जमींदार' कहलाते थे।^३ जमींदार शब्द का एक व्यापक अर्थ था। राजस्व हेतु वचनबद्ध होने वाले व्यक्ति अथवा राजस्वदाता के लिए, चाहे वह वास्तविक 'भूस्वामी' हो या मात्र एक 'मध्यस्थ' हो जिसके द्वारा राजकीय कोष में राजस्व जमा किया जाता था उसके लिए जमींदार शब्द का प्रयोग किया जाता था।^४ भूमि की देखभाल करने वाले को भी जमींदार

१ वही—पृष्ठ—५४

२ डब्लू० एच० मोरलैण्ड—दि एग्रीग्रेरियन सिस्टम इन मुस्लिम इण्डिया पृष्ठ—२६ एव इरफान हबीब—दि एग्रीग्रेरियन सिस्टम इन मुगल इण्डिया—पृष्ठ—२७८ एव २८६

३ बर्नार्ड एस० कोन—'पॉलिटिकल सिस्टम इन एटीन्थ सेन्चुरी इण्डिया जर्नल ऑफ दि अमेरिकन ओरियन्टल सोसाइटी' जिल्द—८२, अक—३ जुलाई—सितम्बर— १९६२, पृष्ठ ३१५ (उद्धृत शोध ग्रन्थ 'जामिंदार इन एट्डीन सेचुरी—')

४ जे० आर० रीड— एक रिपोर्ट एपेन्डिक्स न० १, पृष्ठ ६ ए

कहा जाता था।⁷ भूमि को खण्डों में विभाजित किया जाता था और प्रत्येक जमींदार को एक 'सनद' और 'नानाकार' दे दिया जाता था। जमींदार को अपनी जमींदारी बेचने का अधिकार प्राप्त था किन्तु दोषी पाये जाने पर किसी भी जमींदार की जमींदारी राजा द्वारा छीनी भी जा सकती थी। राजा जब्त की हुई जमींदारी किसी दूसरे को दे सकता था। किन्तु सामन्त और सूबेदार इस अधिकार का उपयोग नहीं कर सकते थे।⁸ १८वीं शताब्दी में जमींदार शब्द का प्रयोग शक्तिशाली स्वतन्त्र और स्वायत्त सरदारों से लेकर ग्राम स्तर के छोटे-मोटे मध्यस्थों तक के लिए प्रयुक्त होता था। किन्तु १८वीं शताब्दी के अन्तिम दशक में इसके व्यापक अर्थ में कमी आई और बनारस सूबे में अंग्रेजी कम्पनी के शासन के अन्तर्गत हुए स्थायी बन्दोबस्त के परिणामस्वरूप (जागीर महालों के अतिरिक्त शेष भाग) ग्राम स्तर के जमींदारों को 'भूस्वामी' मान लिया गया और जमींदार शब्द का प्रयोग 'भूस्वामी' के लिए होने लगा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमींदारों की स्तर के अनुसार अनेक श्रेणी थी किन्तु मुख्यतः इन्हें तीन श्रेणियों में रखा जा सकता है—

(१) स्वायत्त सरदार (२) मध्यस्थ जमींदार (३) प्राथमिक जमींदार।

यद्यपि जमींदारों का अस्तित्व और अधिकार अनुवाशिक और स्थायी होता था किन्तु फिर भी उसमें विविधता होती थी। 'नानाकार' और 'मालिकाना'

7 ब्रिटिश म्यूजियम, ऐड ६६०३, प० ६५, उद्धृत नोमान अहमद सिद्दीकी, मुगलकालीन भूराजस्व प्रशासन-१७००-१७५०-पृष्ठ-४५

8 नो० आ० सिद्दीकी, मुगलकालीन भू राजस्व पृष्ठ-४५ एव, डब्लू के फ्रिमिनगर- दि फिफ्थ रिपोर्ट फ्रॉम दी सेलेक्टेड कमीटी आन दि अफेयर्स ऑफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी जिल्द-द्वितीय पृष्ठ-४ एव सेलेक्शन फ्रॉम रेवेन्यू रेकार्ड ऑफ दि एन० डब्लू० पी०-१८१८-१८२० पृष्ठ-८६

जमीदारी के महत्वपूर्ण अधिकार थे और मुगलकाल में इसकी सामान्य दर १० प्रतिशत थी। किन्तु १८वीं शताब्दी में मुगलों के पतन के कारण इस दर में अन्तर आ गया। अब 'नानाकार' और 'मालिकाना' जमींदार के अधिकार क्षेत्रीय सत्ता से उनके सम्बन्धों पर आधारित हो गये। 'नानाकार' और 'मालिकाना' के अतिरिक्त कुछ अन्य कर भी एकत्रित करने का अधिकार जमींदार के पास था किन्तु इसमें समानता नहीं थी। जमींदार स्वतत्त्वों का क्रय-विक्रय, स्थानान्तरण और गिरवी रखने जैसे कार्य भी किया करता था। वह किसानों और असामी वर्ग से बेगार भी लेता था। मात्र 'वित्तिया' जमींदार ऐसे अधिकारों का उपभोग बिना 'वित्ति दाता' की अनुमति के नहीं कर सकते थे। १८वीं शताब्दी में कुछ राजनीतिक अस्थिरता के कारण जमींदारों के अधिकारों में परिवर्तन परिलक्षित हुआ। कृषि की उन्नति, आबादी का विस्तार, सरकारी राजस्व एकत्रित करके राजकोष में जमा करना, शान्ति व्यवस्था को बनाये रखने में सहायता करना तथा शासन के प्रति निष्ठा बनाये रखना, जमींदारों का मुख्य कर्तव्य था।

स्वायत्त-सरदार

स्वायत्त के अन्तर्गत आने वाले जमींदारों को सर्वोच्च स्थान प्राप्त था। इनके भी अनेक वर्ग थे। पहले वर्ग में वे राजा या जमींदार थे जो मुगलों की अधीनता तो स्वीकार करते थे किन्तु उन पर कोई वित्तीय या सैनिक जिम्मेदारी नहीं होती थी। दूसरे वर्ग में मुगल सम्राट का अधिराजत्व मानने वाले वे जमींदार थे जो या तो प्रान्त के नाजिम की सैनिक सेवा करने की शर्त स्वीकार करते थे या फिर निश्चित सालाना

उपहार देना स्वीकार करते थे।^{१०} (१) पूर्वी उत्तर प्रदेश में मात्र वही जमींदार थे जो सैनिक सहायता और वार्षिक उपहार देते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद भी सम्राट के नाम मात्र के प्रतिनिधि अवध के नवाब को आवश्यकता पड़ने पर सैनिक सहायता देते थे। मुगल साम्राज्य की केन्द्रीय सत्ता के विघटन से उत्पन्न अव्यवस्था से लाभ उठाने के प्रयास में अनेक बार जमींदारों ने अपने अधिकार और भूमि की सीमा को बढ़ाने का प्रयत्न किया। इस विवाद को लेकर अवध के नवाबी शासन और स्थान-स्थान के जमींदारों के मध्य संघर्ष की स्थितियाँ भी आयीं। अनेक जमींदार दंडित भी किये गये किन्तु बनारस के जमींदार काफी समय तक कुछ कारणवश दण्ड से बचते रहे। किन्तु अन्ततः जब नवाब आसफ़ उद्दौला ने बनारस की जमींदारी की प्रभुसत्ता ईस्ट इण्डिया कम्पनी को सौंप दी तो बनारस के राजाओं की स्थिति में स्वाभाविक परिवर्तन आया। राजा चेतसिंह पर तरह-तरह के आरोप लगाकर कम्पनी-शासन ने जमींदारी का सम्पूर्ण प्रशासन अक्टूबर १७६४ में अपने अधिकार में कर लिया। बनारस का राजा थोड़े से भू-भाग का जमींदार मात्र रह गया। फिर भी यह सत्य है कि बनारस स्वायत्त की जमींदारी श्रेणी में आती थी।

मध्यस्थ जमींदार

प्राथमिक जमींदारों से लगान वसूल करके सरकारी खजाने में या जागीरदार अथवा सरदार के पास जमा करने वाले मध्यस्थ जमींदार कहे

जाते थे। विशिष्ट परिस्थितियों में ये लगान की रकम अपने पास भी रख सकते थे। इनका कार्य अपने क्षेत्र में कानून व्यवस्था बनाये रखना था। सेवा के बदले इन्हें कुछ कमीशन, कर मुक्त भूमि और कुछ अन्य रियायतों का लाभ मिल जाता था। प्रायः ऐसे जमींदार पैतृक उत्तराधिकारी होते थे किन्तु कभी-कभी एक निश्चित अवधि के लिए भी कार्य करने वाले जमींदार होते थे। वास्तविकता यह थी कि सम्पूर्ण देश की जमींदारी व्यवस्था किसी न किसी प्रकार से मध्यस्थ जमींदार के अधिकार क्षेत्र में होती थी।¹⁰ १८वीं शताब्दी में मुगल साम्राज्य के विघटन का लाभ उठाकर इन्होंने अपनी स्थिति और स्तर स्वायत्त जमींदार जैसा बना लिया था।¹¹ पूर्वी उत्तर प्रदेश में तो उन्हें अर्धस्वतन्त्र सरदार के रूप में स्वीकार भी किया गया।¹² ये इतने शक्तिशाली थे कि सुनियोजित सैनिक अभियान के बावजूद भी जौनपुर में स्थित राजा-बाजार सिगरामऊ, बदलापुर की स्थिति में बनारस के राजा कोई परिवर्तन नहीं कर सके।¹³ बनारस मण्डल में इनकी सख्खा और शक्ति पर्याप्त थी।

10 एव० नूरुल हसन, "जमींदारि अन्डर दि मुगल्स"—सम्पादित राबर्ट एरिक फ्रीकेनबर्ग, लैण्ड कन्ट्रोल एण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री, १९७६ पृष्ठ २४-२५

11 सी० ओ० जी० जिल्द-१५ पृष्ठ ६३-६४

12 डकन रिकार्ड्स बस्ता न० २, रिकार्ड न० १०, पृष्ठ-१८१ विल्डम ओल्डम-हिस्टोरिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल मेमोरियल पार्ट ११, पृष्ठ १८०-१८१

13 बर्नार्ड एस० कोन, स्ट्रक्चरल चेन्ज इन इण्डियन रूरल सोसायटी- '१५६६-१८८५'-सम्पादित-राबर्ट एरिक फ्रीकेनबर्ग लैण्ड कन्ट्रोल एण्ड सोशल स्ट्रक्चर इन इण्डियन हिस्ट्री १९७६ पृष्ठ ५६-६०

प्राथमिक जमींदार

कृषि योग्य और आवास योग्य भूमि पर स्वामित्व का अधिकार रखने वाले प्राथमिक जमींदार थे। इस तीसरे वर्ग में अपने हाथ से या भाड़े के मजदूरों की सहायता से खेती करने वाले कृषक स्वामी ही नहीं वरन् एक अथवा अधिक गावों के स्वामी भी आते थे। इनके भी कई वर्ग जैसे ग्राम स्तर के जमींदार, भैया जमींदार, पट्टीदार या थोकदार तथा विर्तिया जमींदार थे।

जमींदार और कृषकों के मध्य सम्बन्ध

जहाँ तक तत्कालीन कृषक और जमींदारों के आपसी सम्बन्ध की बात है वे घनिष्ठ और महत्वपूर्ण थे। इन्हीं कृषक वर्ग पर ही उच्चवर्ग का भूमि सम्बन्धी हित आश्रित था। ये परस्पर सीधा सम्बन्ध रखते थे। यद्यपि कृषक समाज का निचला वर्ग था किन्तु फिर भी इनकी अनेक श्रेणियाँ थी। इस सन्दर्भ में डा० सतीश चन्द्र की कृति¹⁴ के परिपेक्ष में इनकी श्रेणियों का विभाजन इस प्रकार है—

(१) खुदकाश्त -

वह कृषक जो अपनी भूमि (स्वयं जोतता हो) का स्वामी हो और जिनके पास निजी हल बैल और परिवारिक श्रम हो। वह निश्चित किन्तु अपेक्षाकृत प्रचलित दर से कम लगान देता हो। यह कृषकों का ऐसा समूह

¹⁴ सतीश चन्द्र—मेडिवल इन्डिया, सोसायटी, दि जागीरदारी—क्राइसिस ऐण्ड दि विलेज—पृष्ठ १६६

था जो कृषि में विशिष्ट धन लगाने वाले विशिष्ट वर्ग की रचना करता था।¹⁵ उन्हें अपने खेत का चयन करने, सम्पत्ति का उत्तरादान करने, गिरवी रखने, स्थानान्तरित करने का अधिकार था। ये प्रायः जमींदारी के उपकरणों से मुक्त थे।

(२) पाही काश्त -

जमींदारी की सीमा के बाहर के गांव से आने वाले अस्थाई निवासी इस श्रेणी के कृषक थे। इनमें कुछ निजी हल-बैल रखते थे और कुछ साधन विहीन अश्वपृष्ठ होते थे।¹⁶

(३) मुजारा -

इस श्रेणी में ऐसे किसान आते थे जो गांव के बड़े लोगों से हल बैल लेकर कार्य करते थे। वे बटाई तौर पर कृषि कार्य करते थे।¹⁷

किन्तु मोरलैण्ड के अनुसार "कृषक वर्ग के अन्तर्गत ग्राम के जमींदारों का समुदाय, उस गांव के निवासी-कृषक सम्मिलित थे।"¹⁸

जमींदारी प्रबन्ध -

पूर्वी उत्तर प्रदेश में नितान्त छोटी जमींदारियों को छोड़कर प्रायः सभी में व्यवस्था हेतु दो केन्द्र—(१) सदर कचहरी (२) मुफस्सिल कचहरी होते थे। सदर कचहरी अर्थात् केन्द्रीय कार्यालय जमींदार का पारिवारिक

15 वही—पृष्ठ ३२-३६, १६६-१७०

16 वही—

17 वही—पृष्ठ १७१

18 डब्ल्यू० एच० मोरलैण्ड—दि एग्नीग्रेरियन सिस्टम ऑफ मुस्लिम इण्डिया—पृष्ठ-१६१

निवास स्थान होता था। इसका प्रमुख 'दीवान' होता था। प्रायः सभी बड़े जमींदार जमींदारी की व्यवस्था हेतु 'दीवान' की नियुक्ति करते थे। बनारस के राजा बलवन्त सिंह ने मेहरचन्द खत्री को अपना दीवान नियुक्त किया था।¹⁹ मेहरचन्द की मृत्यु के बाद उसका छोटा भाई नन्द भगत दीवान बनाया गया।²⁰ राजा चेतसिंह के समय में औसान सिंह दीवान के पद पर था।²¹ यह एक जमींदारी प्रबन्ध को सर्वत्र प्रचलित परम्परा थी। जौनपुर के बदलापुर ताल्लुका में भी दीवान नियुक्त था।²² यद्यपि इन 'दीवान' के कार्य और अधिकार का निर्धारण नहीं स्पष्ट है। किन्तु यह उनकी योग्यता और जमींदार के सम्बन्धों पर निर्भर करता था। धीरे-धीरे अधिकांश दीवान विशिष्ट अधिकार सम्पन्न सर्वेसर्वा भी बन गये थे।

जमींदारों द्वारा वकील रखने की भी परम्परा थी। वर्तमान में उक्त वकील का अर्थ राजदूत, प्रतिनिधि²³ अथवा मुख्तार के रूप में समझा जा सकता है।

जमींदारों के पास सैनिक शक्ति भी थी। विभिन्न जातियों के लोगों से तैयार एक सेना जमींदारी की रक्षा हेतु केन्द्रीय कार्यालय में रहती थी। बनारस के राजा बलवन्त सिंह के केन्द्रीय कार्यालय में एक विशाल सेना थी।²⁴ प्रबन्ध व्यवस्था की दृष्टि से सभी बड़ी जमींदारी विभिन्न प्रादेशिक

19 बलवन्तनामा— पृष्ठ १४, २१

20 वही—पृष्ठ—१४

21 वही—पृष्ठ—१२, १३, ६४

22 रेजीडेन्ट प्रोसीडिंग्स ऐट बनारस, बस्ता न० २१, रजिस्टर न० ८ जून १७८८ ई०—पृष्ठ ५३५

23 बी०एस० कोन, 'फ्राम इण्डियन स्टेट्स टू ब्रिटिश कान्ट्रेक्ट'— दि जर्नल ऑफ़ एकनामिक हिस्ट्री—जिल्द २१, न०४, १९६१ पृष्ठ ६२६

24 गुलाम हुसैन खॉं— तारीख—ए—बनारस, पृ० १६ बी— १७ ए०

ईकाइयो में विभक्त थी। बनारस के राजा की जमींदारी में ६६ परगने थे किन्तु १७८७-८८ ई० के मध्य बनारस मण्डल ५४ परगनों में विभाजित था।²⁵

सभी श्रेणी के जमींदारियों की प्रबन्ध व्यवस्था में जमींदार स्वयं सर्वोच्च था।

जमींदार देश का एक ऐसा महत्वपूर्ण वर्ग था जिसको आय का स्तम्भ कहा जा सकता है। किन्तु १८वीं शताब्दी में कृषि उत्पादन, हस्तशिल्प तथा व्यापार सम्बन्धी आर्थिक जीवन के क्षेत्र में यह वर्ग आर्थिक शोषण की प्रक्रिया में विदेशी सत्ता के साथ सझींदारी कर रहा था। यह वह समय था जब मुगल सत्ता अपने विघटन को रोकने में असमर्थ हो रही थी और देश के विकास के लिए कुछ करने में असमर्थ थी। ऐसी स्थिति में विकास का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्थानीय अधिकारी वर्ग पर तथा जमींदार वर्ग पर था। पूर्वी उत्तर प्रदेश की कृषि उद्योग एवं व्यापार की उन्नति में जमींदारों की भूमिका महत्वपूर्ण थी। कृषि की उन्नति के लिए सभी श्रेणी के जमींदार प्रयासरत रहते थे। कृषि के विस्तार से जहाँ सरकार के राजस्व में वृद्धि होती थी वही जमींदारों को भी लाभ पहुँचता था। सरकार सदैव कृषि कार्य बढ़ाने और रैयत के प्रति विशेष ध्यान देने पर बल देती थी।²⁶

²⁵ बनारस इन ट्रान्जिक्शन पृष्ठ-१६-के० पी० मिश्र।

²⁶ के० पी० मिश्र ट्रान्जिक्शन इन बनारस-पृष्ठ ६६ एवं ओल्डम- हिस्टारिकल एण्ड स्टैटिस्टिकल मेमायर-भाग-११ पृष्ठ-६२

बलवन्त सिंह के शासन का उद्देश्य भूमि मालिकों के अधिकार को समाप्त करना था। परगना जमींदार अथवा स्वायत्त जमींदार को समाप्त करने का भी उद्देश्य था। वह अपने निजी व्यक्तियों की उनके स्थान पर नियुक्ति करता था। इसी बीच देश की आर्थिक व्यवस्था के लिए एक नई योजना बनाई गई। गाँव के जमींदारों को उनकी 'सीर' पर कायम रहने का आदेश हुआ। सीर अथवा निजजोत की भूमि ग्राम स्तर के खेतिहर जमींदारों की आय का मुख्य स्रोत था।²⁷ इस श्रेणी के समस्त छोटे जमींदार अपने 'सीर' को बढ़ाने और उस पर उच्च कोटि की प्रणाली से खेती करने का प्रयत्न करते थे। वे कृषि कार्य में विशेष रुचि लेते थे। गाजीपुर जनपद में अंग्रेजी बन्दोबस्त के समय जमींदारों की 'सीर' की भूमि समस्त कृषि योग्य भूमि की एक तिहाई थी। कृषि की उन्नति हेतु १८वीं शताब्दी के जमींदारों का प्रयास उल्लेखनीय है। इसी सन्दर्भ में वे कृषकों और रैयतों के प्रति विशेष कृपा रखते थे। गाजीपुर परगना के सैदपुर को मिर्जा मोहम्मद ने पाँच वर्ष के अनुबन्ध पर प्राप्त किया था। इस अवधि में उसने न केवल रैयत के साथ सद्व्यवहार किया बल्कि अकाल और सूखा पड़ने पर उन्हें अपनी तरफ से लगान मुक्त कर दिया। इसी प्रकार जौनपुर के परगना केराकत में स्थित मौजा मोरे एवं डेहरी, १८वीं शताब्दी के प्रारम्भ में जंगल था। इसे लालशाह ने बनारस के राजा मसारांम से १५/- वार्षिक राजस्व के बदले प्राप्त किया और उसे कृषि योग्य बनाया। उसने खेती का सर्वाधिक विस्तार किया और १७८६ में इन

27 वी० ए० नरायण— जोनार्थन डकन एण्ड वाराणसी—पृष्ठ—५६

मौजों की सरकारी राजस्व १४०० रु० वार्षिक कर दिया।²⁸ कृषि के विकास में जमींदारों ने अपना धन भी लगाया। राजा बलवन्त सिंह के समय में परगना सैदपुर में भगवन्त राव नामक व्यक्ति ने 'ताहुद' अर्थात् अनुबन्ध के द्वारा पाँच मौजों की जमींदारी प्राप्त, की जिस पर कृषि कार्य नहीं होता था। उसने इन्हें आबाद करने और कृषि योग्य बनाने में काफी धन खर्च किया। गाजीपुर के बहरिबाद क्षेत्र के सहाय परिवार के जमींदार का भी योगदान विशिष्ट था। इन्हीं के वंशज जमींदार हरी राम सहाय थे जिनके परिवार ने बाद में स्वतन्त्रता संग्राम में अंग्रेजी सत्ता का विरोध किया था। पूर्वी उत्तर प्रदेश में लगभग सभी राजाओं ने अपनी जमींदारी का विस्तार करने के प्रयास में तथा कृषि के विकास में विशेष रुचि लिया था। रैयत के प्रति राजा की विशेष कृपा होती थी। चराई, मछली मारना एवं जंगल की उत्पत्ति 'सीर' धारकों के अधिकार में थी। उन्हें अपने गांव के पास से गुजरने वाले अनाज एवं व्यापारिक वस्तुओं पर राहदारी मिलती थी।²⁹

राजा की सेवा करने वालों को विशेष छूट दी जाती थी। बलवन्त सिंह ने आदेश दिया था कि रैयत से समस्त राजस्व वर्षा प्रारम्भ होने के पूर्व ही ले ली जाये जिससे खेती प्रारम्भ करने के पश्चात् वे लगान वसूल करने वालों द्वारा परेशान न किये जायें।

राजा चेतसिंह के समय में यह नियम ढीला कर दिया गया था। पूर्व वर्ष का अवशेष, दूसरे वर्ष में वसूलने का आदेश हुआ।³⁰ रैयत जब कृषि

28. ओल्डम पूर्व उद्धृत-पृष्ठ-६४.

29. वही-

30. ओल्डम-वही-

कार्य में व्यस्त होते थे उस समय उन्हें लगान के लिए तग किया जाता था।³¹ चेतसिंह और अग्रेजों के सम्बन्ध बिगड़ रहे थे और जब चेतसिंह भाग गये तो राज्य की दशा बिगड़ गई।³² इससे सनसनी फैल गई। बनारस में रेजीडेन्ट लगान वसूली में हस्तक्षेप नहीं करता था। अगले वर्षों में आमिलों को आदेश दिया गया कि लगान में साढ़े नौ प्रतिशत से सोलह प्रतिशत की वृद्धि कर दें। इसके कारण जमीन बजर होने लगी। कुँआ की दशा खराब हो गई और कृषि कार्य ढीला पड़ गया।

इस अव्यवस्था और ढिलाई के परिणामस्वरूप जहूराबाद, पचोतर तथा सिकन्दरपुर के परगनों में कृषि कार्य शिथिल पड़ गया और गबन होने लगा। जुलाई १७८७ में जॉनथन डकन को ५०००/- प्रतिमाह पर बनारस में रेजीडेन्ट नियुक्त किया गया। कार्यभार ग्रहण करने के बाद उसे इस गड़बड़ी का पता लगाकर उसमें सुधार करने के उपायों की रिपोर्ट करने का आदेश हुआ। इस समय आधी से अधिक भूमि बजर पड़ी थी।³³ डकन को पूर्व रेजीडेन्ट से अधिक अधिकार दिया गया। राजा से सहयोग करने को कहा गया। शासन की इच्छाओं को कार्यान्वित करने के लिए उसे अधिकार के साथ सम्पूर्ण उत्तरदायित्व भी दे दिया गया।³⁴

इस निर्णय से अधिक आशा न होने पर भी राजा सरकार का कृपा पात्र बनना चाहता था और सम्पूर्ण लगान वसूल करना चाहता था।

31 वही—

32 बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू करसर्पॉन्डेन्स— टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड आक्सन सेल इन गाजीपुर एण्ड दि बनारस प्राविन्स जिल्द ५७ पृष्ठ—१०

33 बोर्ड ऑफ़ रेवेन्यू करसर्पॉन्डेन्स— अप्रैल २६, १७८१ पृष्ठ—१८८—१८९

34 वही— जुलाई १२, १७८८ पृष्ठ—२३३

आमिलो को टेन्डर देने का आदेश दिया गया तथा बोली बोलने को प्रोत्साहित किया गया। इनके आचरण एवं योग्यता पर विशेष ध्यान दिया गया। विगत पाँच वर्षों की एकत्रित राशि ४० करोड़, ७१ हजार, ६३३ रु० २ आना ६ पाई थी और इस नई व्यवस्था में औसत राशि से २ लाख अधिक थी।³⁵ केवल एक साहसी कार्यकर्ता मेहदी अली खॉ, जो एक पारसी था, ने डकन से कुछ शिकायत किया। किन्तु अन्य कोई शिकायत नहीं आई। उसकी शिकायत यह थी कि सादियाबाद और गाजीपुर के लिए राजा ने लगान से बहुत अधिक की शर्त रखी है।³⁶ डकन की सिफारिश पर राजा ने 'आकिलनामा' और कबूलियत के तरीके में परिवर्तन किया। इस नई व्यवस्था के अनुसार आमिलो को अपने क्षेत्र में होने वाली चोरी डकैती आदि के लिए जवाबदेह होना पड़ता था।³⁷

गाजीपुर और सादियाबाद के आमिल मेहदी अली खॉ से लगान की शेष किश्त जमा कराने को कहा गया। इसके लिए राजा के चपरासियो ने उसे तरह-तरह से परेशान किया और उसे राजा की कचहरी में ले जाने का प्रयास किया। इन्हीं प्रयासों के बीच एक दिन मेहदी अली खॉ ने सखिया खाकर आत्महत्या करने की चेष्टा किया। किन्तु रेजीडेन्ट डकन के डाक्टर ने उसे बचा लिया।

डकन प्रान्त में एक नया व्यक्ति था और स्थानीय मामलो का उसे बिल्कुल ज्ञान नहीं था। किन्तु मेहदी अली खॉ द्वारा आत्महत्या के प्रयास

35 वही— सितम्बर १२, १७८८, पृष्ठ—१३६

36 वही—

37 वही—

से वह चिन्तित हुआ। उसने उस क्षेत्र की सम्पूर्ण, जानकारी प्राप्त करने के लिए मामलो की छानबीन कराया और सम्पूर्ण जानकारी प्राप्त किया। तत्पश्चात उसने सादियाबाद जहाँ औसत से अधिक लगान ले लिया गया था, में २५०००/- की छूट दिलवाया। गाजीपुर से लिए गये अधिक लगान को भी राजा को छोड़ना पड़ा।³⁸

इसी बीच एक अन्य घटना भी सामने आई। कुल्ब अली खॉ को अपने जिले से अधिक लगान लेने पर बाध्य किया गया। उसने डकन से इसके विरोध में प्रार्थना किया। राजा ने इसका विरोध किया क्योंकि इसका प्रभाव अन्य आमिल पर भी पड़ता। इसी समय राजा दो माह तक बीमार रहा। डकन ने कुल्ब अली खॉ के विषय में जो ज्ञात किया उसके अनुसार वह दिवालिया था और उस पर महाजनो का कर्ज था जो वह ऋण अदायगी के लिए लेता था।³⁹ डकन ने मुख्य अधिकारियों से परामर्श लिया। यह पता चला की १७८६-८७ के लिए कुल्ब अली खॉ पर ३३००/- से अधिक लगान निर्धारित की गई थी। उसने इब्राहिम अली को इस बात के लिए अधिकृत किया कि वह इस रकम को २५००/- निश्चित कर के मामला निपटाये। वह मान गया।⁴⁰ राजा ने तीन माह का लगान पूरे प्रान्त में छोड़ दिया। कुल्ब अली खॉ ने जौनपुर के निकट अपने एक परगने के लगान में छूट के लिए पुन प्रार्थना किया। राजा उसकी बात

38 वही—

39 वही— एव डा० ए० एन० सिंह गाजीपुर जनपद इतिहास की दृष्टि पृष्ठ—४३

40 वही—पृष्ठ—१३८

सुनने को तैयार नहीं था। डकन राजा के अधिकार क्षेत्र में बाधा नहीं डालना चाहता था।⁴¹

देश के आन्तरिक हिस्सों के दौरे के उपरान्त जब राजा लौटा तो उसने जमींदारों और अपने मध्य अनेक कठिनाइयाँ महसूस किया। उसने लगान वसूली और सख्त कर दिया। अप्रैल १७८८ में कुल्ब अली खाँ ने लगान देना बन्द कर दिया। राजा की प्रार्थना पर रेजीडेन्ट ने अपने सहायकों के साथ कुछ सैनिक भेज कर वसूली और शान्ति व्यवस्था स्थापित करने का आदेश दिया। बनारस और बलिया परगनों का हिसाब पूछा गया। सहायक रेजीडेन्ट जे० नीवा अप्रैल १७८८ तक जौनपुर रहा और उसने लगभग २ लाख रुपया लगान वसूल किया। अभी तक लगान न जमा करने का यह कारण पता चला कि महाजनो ने कुल्ब अली खाँ को जो ऋण दिया था उसी हेतु १७०८४ रु० ४ आना ले लिया।⁴²

डकन ने उक्त राशि महाजनो से लौटाने के लिए कहा। महाजन और सर्राफ नाराज हो गये। इन्हीं के द्वारा प्रान्त का सम्पूर्ण लगान राजा के खजाने में जमा होता था। उन्होंने यह निर्णय किया कि जब तक रेजीडेन्ट उनका पूर्व धन लौटायेगे नहीं तब तक वे अपना दाखिला अगली किश्त में नहीं जमा करेंगे। रेजीडेन्ट एक कठिन परिस्थिति में पड़ गया क्योंकि महाजन लगान वसूली के प्रधान व्यक्ति होते थे। किश्त धन के रूप में न होकर दाखिला के रूप में बदल दिया जाता था। प्रान्त के सभी

41 वही—

42 वही—

भागो में लगान का परिणाम जौनपुर की ही भांति रहा। राजा और उनके नौकर अधिकांश लगान की वसूली कर लेते थे।⁴³

सम्पूर्ण लगान एवं दूसरे टैक्स ३८ करोड़ १५ हजार ३७६ रु० १२ आना ३ पाई थी। यह राशि निर्धारित से ४ लाख ७० हजार कम थी। सरकार की मांग उस वर्ष के लिए ३६ करोड़ १ हजार ७३२ रु० ७ आना ८ पाई थी। इसमें ५०,०००/- गत वर्ष का बकाया भी सम्मिलित था। डकन को २ लाख ५ हजार, ६६२ रु० २ आना का घाटा पूरा करना पड़ा।⁴⁴ यह घाटा अन्य साधनों से पूरा किया गया। यह सब कमियाँ पिछले वर्ष की वसूली से एवं ८५०००/- की राशि राजा ने शिवराज दूबे से लेकर पूरा किया।⁴⁵ यद्यपि राजा का सग्रह चेतसिंह के भागने के बाद से निरन्तर गिरता गया किन्तु फिर भी मुफस्सिल तथा रैयत से वसूला गया कर चेतसिंह के शासन काल से एक लाख अधिक हुआ।⁴⁶ इस प्रकार का घाटा और विभिन्न साधनों से उसकी भरपाई शासन के लिए एक चेतावनी थी।⁴⁷

डकन का विचार था कि जब तक मुफस्सिल की गडबडिया सुधारी न जायेगी और उसकी जगह कोई निश्चित नियम नहीं बनाया जायेगा तब

43 वही— सितम्बर २७, १७८८, पृष्ठ—१४३

44 वही अप्रैल—२८, १७८६, पृष्ठ—१७२—१७३

45 वही— पृष्ठ १७४— शिवलाल दूबे एक समृद्ध महाजन आमिल था। बाद में वह जौनपुर का राजा बनाया गया। इससे पूर्व वह कुल्ब अली के फार्म के साथ सम्बद्ध था। उसने जौनपुर के आन्तरिक भागों से राजस्व वसूल करके बनारस खजाने में जमा किया। परिश्रमिक स्वरूप उसे प्रति सौ रुपये पर बारह आना प्राप्त होता था।

46 वही—सितम्बर १२ १७८८ —पृष्ठ १४६—१४७

47 वही—पृष्ठ—१४७

तक सरकारी आय व्यवस्था असफल रहेगी। इसी सन्दर्भ में डकन ने २५ जून १७८८ को राजस्व व्यवस्था में सुधार व वसूली हेतु निम्नलिखित सुझाव दिया —

(१) राजा एक ही प्रकार का पट्टा सभी के लिए स्वीकृत करे। आमिल कृषको को जो उनका उचित हिस्सा नहीं देते थे यह व्यवस्था स्वाभाविक रूप से सुरक्षा प्रदान करेगी।

(२) रुपये के अतिरिक्त अन्य सामग्री आदि के रूप में प्राप्त होने वाले अनुमानित भाग अथवा हिस्सा के सन्दर्भ में जो विवाद उत्पन्न हो रहा है उसे रोकना आवश्यक है। प्रत्येक परगना के हर एक प्रकार के अन्न का मूल्य निर्धारण दोनों फसलों के लिए वर्ष में एकबार होना चाहिए। यह कार्यवाही रेजीडेन्ट के अनुमोदन पर राजा द्वारा लिखित घोषणा द्वारा पूर्ण होना चाहिए।

(३) भविष्य में अनाज की दर उत्पादित अन्न की गुणवत्ता के मूल्यांकन के उपरान्त निर्धारित होनी चाहिए। फसल के उपज की कोई वास्तविक श्रेणी निर्धारित नहीं होनी चाहिए।

(४) भूमि का पट्टा करते समय विशिष्ट रूप से इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि राजा और रैयत को उत्पादन का प्राप्त हिस्सा समानुपात में हो।

(५) आमिल और कानूनगो द्वारा रजिस्टर्ड पट्टा होना चाहिए।

(६) भूमि का पट्टा रेडी मनी सेटलमेंट के आधार पर होना चाहिए। रैयत से गैरकानूनी ढग से दिन प्रति दिन वृद्धि करके लगान की जबरदस्ती वसूली पर प्रतिबन्ध लगाना चाहिए। १७७६-१७८० की दर को लागू किया जाना चाहिए।

(७) देश के प्रत्येक भाग में राजा द्वारा नियुक्त अमीन सम्बन्धित परगना के कानूनगो और आमिल से परामर्श करके ही किसान को पट्टा वितरित करेंगे।

(८) कानूनगो के सहायतार्थ लगाये गये अतिरिक्त कर समाप्त होने चाहिए और उनकी सहायतार्थ मात्र भूमि आवंटित करना चाहिए।

(९) अमीन किसानों को कुछ बेकार पड़ी भूमि, किसी भी शर्त पर जैसा कि वे पसन्द करें, पुरानी खेती से जोड़ने के लिए प्रेरित करें। यह अतिरिक्त फसल राज की आमदनी का एक नया और अच्छा माध्यम होगा।

इस प्रस्ताव का सर्वाधिक महत्वपूर्ण परिच्छेद नये अतिरिक्त करों को रोकना तथा १७७६-१७८० के लगान दर को पुनः लागू करना था। इस नियम के अन्तर्गत वसूली १७७६-८० की दर के अनुसार होना था। विभिन्न कानूनगो को डकन ने इस आशय का निर्देश प्रेषित किया कि वे परगना को सुनिश्चित लठ्ठे उपलब्ध कराये जो रेजीडेन्ट के कार्यालय में जमा थे। उसने रैयतों के बीच वितरित कराने के लिए लिखित परिपत्र अग्रसारित किया।⁴⁸

⁴⁸ वही-पृष्ठ-१४७-१५०

इस प्रकार एक निश्चित दर प्रति बीघा के लिए लागू करने का आदेश हुआ। आमिलो को आदेश हुआ कि वे सभी पट्टो को रजिस्टर्ड दे। देश के सभी भागो मे राजा द्वारा नियुक्त अमीन, आमिल और कानूनगो किसानो को पट्टा वितरित करते थे। कानूनगो लोगो के भरण—पोषण के लिए जो धन टैक्स लगा कर लिया जाता था उसे समाप्त करके जमीन दिये जाने की व्यवस्था की गई। इस व्यवस्था के विपरीत डकन ने पहले ही कानूनगो को खजाने से नकद भुगतान हेतु परामर्श दिया था किन्तु उस परामर्श को न मानते हुये आमिलो द्वारा 'अबवाब' रैयतो से लेना जारी रहा। इस व्यवस्था ने कानूनगो को आमिल पर आश्रित कर दिया जो कि असंवैधानिक था। उसने यह भी परामर्श दिया कि 'कानूनगो' पद पर पैतृक अथवा अनुवाशिक नियुक्ति न करके योग्यता के अनुसार नियुक्ति की जाये। उनका कार्यकाल और उसकी निरन्तरता उनके कुशल कार्य, व्यवहार और निर्धारित उत्तरदायित्व निर्वाह के अनुरूप होने पर निर्भर होनी चाहिए। यह प्रस्ताव २५ जून १७८८ को पारित किया गया जिसे गवर्नर जनरल की परिषद् ने उसी वर्ष ३ अक्टूबर को अनुमोदित कर दिया। इस प्रस्ताव को लागू करने का उद्देश्य नये टैक्सो को समाप्त करना भी था।⁴⁹

राजा और डकन की एक सामूहिक बैठक हुई जिसमे डकन द्वारा प्रस्तावित 'पट्टा' व्यवस्था को राजा ने मानने से इनकार किया। राजा की यह दलील थी कि इस प्रकार के पट्टे से चालू वर्ष की लगान वसूली मे बाधा उत्पन्न होगी और व्यय भी अधिक होगा। डकन को राजा की यह

⁴⁹ वही—पृष्ठ—१४७—१५०

आलोचना और प्रस्तावित पट्टे के स्वरूप पर अरुचि दर्शाना उचित नहीं लगा। उसने यह निश्चय किया कि यदि राजा असमर्थ है तो वह स्वयं लगान वसूली और पट्टा वितरण का कार्य कर लेगा।⁵⁰

डकन ने यह वादा किया कि १०,०००/— अतिरिक्त खर्च करके अमीनो से कार्य करायेगा और इसकी स्वीकृति सरकार देगी।⁵¹

डकन ने लगान सम्बन्धी विवादों के निपटारों हेतु एक अदालत स्थापित करने का सुझाव दिया। यद्यपि राजा की 'मुल्की' अदालत पहले से थी किन्तु यह व्यक्तिगत सम्पत्ति सम्बन्धी और लगान सम्बन्धी मामलों को देखने के लिए अपर्याप्त थी। अधिकांश न्यायाधीश मुस्लिम थे जिन्हें कानून का पूरा ज्ञान नहीं था। इसी कारण आमिल के विरुद्ध रैयत को बहुत कम न्याय मिल पाता था। १९६६ फरस्ती (१७८८-८९) में जो अदालत थी वह रैयत, आमिल और जमींदार के मध्य उत्पन्न विवाद को ही सुनती थी और अपनी निर्णय देती थी। उनके निर्णय पर अन्तिम अपील रेजीडेन्ट की अदालत में होती थी।

जेम्स ग्रान्ट के अर्थ सम्बन्धी रिपोर्ट की एक प्रति डकन को प्राप्त हो गई थी जो एक प्रस्तावित बयान के रूप में थी। इसमें उसने १९८४ फरस्ती के लगान का आकड़ा लिखा था जो ७ लाख ३७ हजार ८३९/—रु० था। डकन ने गहराई से सावधानीपूर्वक इसका निरीक्षण किया और यह पाया कि कुछ जिलों में लगान अधिक लगाई गई है। इसकी पुष्टि अवसान

⁵⁰ वही पृष्ठ-१५५

⁵¹ वही पृष्ठ-१५६

सिंह, सदानन्द तथा बनारस के दूसरे लगान अधिकारियों के द्वारा हुई।⁵² मुफस्सिल के आय से पूरे वर्ष का सग्रह ४० लाख, ७१ हजार ६३३ रु० २ आना ६ पाई थी। डकन ने एक विस्तृत रिपोर्ट देश के लगान व्यवस्था के सम्बन्ध में प्रस्तुत करके शासन से सुधार हेतु आग्रह किया। देश की व्यवस्था और उसे नियमबद्ध करने के प्रयास हेतु बोर्ड ने डकन की प्रशंसा किया।⁵³

डकन की सभी प्रस्तावित सिफारिशें स्वीकार कर ली गईं। उसे सम्पूर्ण लगान व्यवस्था को अपने हाथ में ले लेने का अधिकार दिया गया।⁵⁴

डकन ने राजा को लिखा कि प्रत्येक परगने का लगान पट्टे पर लिखा जाय और उन्हीं के आधार पर जमींदारी के सभी वाशिन्दों के लिए समान और सुविधाजनक लगान निश्चित की जाय। उसने राजा को यह भी आगाह किया कि वह कोई ऐसा असामी न नियुक्त करे जो उसका विरोध करें। इसी आशय का ज्ञापन प्रत्येक परगना के कानूनगो और प्रत्येक जिले के आमिल को अलग-अलग प्रेषित किया गया। इस प्रकार लगान व्यवस्था को अपने हाथ में लेकर डकन ने व्याप्त कमियों और असमानताओं को दूर करने का प्रयास किया।⁵⁵

52 वही—पृष्ठ १२५—१२६ एवं पृष्ठ १३२—१३३

53 वही—अक्टूबर—३—१७८८ पृष्ठ—२३

54 वही—अक्टूबर—७, १७८८, पृष्ठ—११३—११४

55 वही पृष्ठ—१०७—११४

समझौता के पहले वाली भूमि के नाप जोख में डकन ने कानूनगो की रिपोर्ट के आधार पर ठीक-ठाक पैदावार पर समझौता करने का वादा किया। समझौता से पूर्व डकन ने 'जामा' और 'अबवाब' को भी अपने समक्ष रखा और इनमें से १० प्रतिशत आमिल के लाभ और मुफरिसल की व्यवस्था में खर्च हेतु कम कर दिया। इन सब खर्चों से बची हुई रकम सरकार को अदा कर देते थे। तब से यह एक सामान्य नियम बन गया।⁵⁶

११८७ फस्ली के बाद लगाये गये सभी टैक्स को डकन ने बन्द कर दिया। टैक्स की इस समाप्ति के बाद बनारस में मात्र एक ही प्रकार की राजस्व व्यवस्था—भूमि लगान व माल सम्बन्धी रह गया। डकन ने किसी अन्य प्रकार का टैक्स लगाना न तो उचित समझा और न ही आवश्यक।⁵⁷ फलतः सारे भ्रष्टाचार और अनियमितताओं के मार्ग बन्द हो गये।

अब डकन का ध्यान, आमिलों के किश्तवारी की ओर आकृष्ट हुआ। बलवन्त सिंह के शासन काल में लगान वसूली अश्विन मास से जेठ मास तक होता था। अगले तीन महीनों में किसान कृषि कार्य के लिए अपने खेतों की जुताई करते थे। सदर किश्त बन्दी दस माह बढ़ाकर अषाढ तक कर दी गई। चेतसिंह के समय में यह कार्य पूरे वर्ष चलता था। डकन ने यह अनुभव किया कि बलवन्त सिंह के शासन काल में लागू नियम अपेक्षाकृत अधिक लाभप्रद थे। अतः उसने वही पहली किश्त खरीफ फसल की और दूसरी किश्त रबी फसल की पुनः लागू कर दिया।⁵⁸

⁵⁶ वही—अप्रैल—२८, १७८६, पृष्ठ—१८१

⁵⁷ वही—पृष्ठ—१८३

⁵⁸ वही पृष्ठ—१८३—१८४

इन नियमों का परिणाम यह निकला कि सभी परगनों को एक साल का पट्टा देने से ३ करोड़ ५२ लाख, ८ हजार, ६३३ रु०, १३ आना का और खराब भूमि को पाँच वर्ष का पट्टा देने पर ३ करोड़, ६० लाख, १ हजार, ८६३ रु० १४ आना ६ पाई की रकम प्राप्त होगी।

बहुत गम्भीरतापूर्वक विचार करने पर डकन को यह विश्वास हो गया कि परगना को इस प्रकार निर्धन बना देने से और बराबर परिवर्तन करते रहने से इसमें कभी सुधार नहीं हो सकता।⁵⁹

राजा की सहमति से डकन ने कुछ पिछड़े और निर्धन जिलों को ५ वर्ष का पट्टा और जो पिछड़े नहीं थे उन्हें एक वर्ष का पट्टा दिया।⁶⁰ यह समझौता १३ दिसम्बर १७८८ से आरम्भ किया गया। आमिलों के लिए लगान वसूली का नया फार्म बनाया गया जिनमें ये शर्तें लगा दी गई कि—

(१) वे २५ जून, १७८८ के नियमानुसार पट्टे के आधार पर ही कार्य करें और कानूनगो द्वारा गाँव के लिए निर्धारित किराया के अनुसार ही एकत्रित करें।

(२) वे भूमि के नाप जोख के लिए एक प्रमाणित लट्ठे का ही प्रयोग करें जो रेजीडेन्ट द्वारा सम्पूर्ण प्रान्त के लिए निर्धारित है। इस लट्ठे की लम्बाई ५६ गज होनी चाहिए। बनारस का प्रमाणित एक बीघा अंग्रेजी के एक एकड़ भूमि के ६४६ के बराबर होता था।

⁵⁹ वही—पृष्ठ—१८४—१६१

⁶⁰ वही—

(३) यह आदेश दिया गया कि जो टैक्स समाप्त कर दिये गये हैं उनकी पुनः माग न की जाये।

(४) परगना के कानूनगो और काजी की रिपोर्ट के साथ चोरी, डकैती, हत्या, राहजनी आदि के अपराधियों को अदालत में पेश करने का भी आदेश हुआ।

(५) यदि किसी प्रकार की जायदाद सम्बन्धी चोरी आदि का मामला पता करने में और उसकी भरपाई कराने में वे असमर्थ रहे तो इसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व उन पर होगा।⁶¹

१३ दिसम्बर १७८८ से माह के अन्त तक अपने अनुमानित राजस्व का ब्यौरा लेकर बनारस के रेजीडेन्ट के समक्ष उपस्थित होने का निर्देश प्रान्त के प्रत्येक कानूनगो को दिया गया। प्रायः कानूनगो द्वारा प्रस्तुत किये गये विवरण का आवश्यक निरीक्षण और विचार करने के बाद स्वीकार करके किश्त निर्धारित कर दी जाती थी। किन्तु कोल्सला और डारुमाही परगना के राजस्व वसूली पर रेजीडेन्ट ने आवश्यक हस्तक्षेप किया। ऐसा इसलिए करना पड़ा कि कानूनगो और आमिल पूर्व रेजीडेन्ट फ्रांसिस फोक द्वारा हस्ताक्षरित और निर्धारित लगान से कम लगान निरन्तर देते आ रहे थे। इस तरह के सभी प्रकरण से होने वाली हानि की धनराशि का रेजीडेन्ट ने विवरण तैयार करके सरकार को प्रेषित किया। शासन की स्वीकृति से डकन ने इस तरह के सभी देनदारों से सम्पूर्ण 'जामा' की आदायगी हेतु समझौता किया।

⁶¹ वही पृष्ठ-१८५-१८६

डकन ने सभी पक्षों को समझा और उसने पूरी तरह यह अनुभव किया कि प्रान्तों के पास आमदनी के जो स्रोत हैं वे राजस्व और अन्य खर्चों की तुलना में कम हैं। अतः उसने राजा से खर्चा सीमित करने का निवेदन किया। इसके लिए सदर कचहरी और उसकी व्यवस्था पर होने वाले खर्च को कम किया गया। ४७ घुडसवार २८७ चपरासी, ७५ हरकारों के स्थान पर १० घुडसवार ६० चपरासी और ४० हरकारों को ही रखा गया। यद्यपि डकन की इस कार्यवाही से राजा को भावनात्मक दुःख पहुँचा किन्तु डकन ने १३, ५३२/— की बचत सुरक्षित कर लिया।⁶²

ईमानदारी, निष्ठा, आर्थिक स्थिरता आमिल के साथ किसी भी समझौते का मुख्य आधार था। ऐसे ही दो आमिल शिवलाल दूबे और शकर पंडित थे। शिवलाल दूबे के साथ भूइली परगना के लिए एक वर्ष तथा जौनपुर और उसके आश्रित परगना के लिए पाँच वर्ष का समझौता हुआ। सिकन्दरपुर परगना शकर पंडित को दिया गया। यह एक विस्तृत किन्तु क्षतिग्रस्त भू-भाग था।⁶³

१७८८-८९ के मध्य डकन ने ३८ आमिलों से पाँच वर्ष का तथा २८ आमिलों से एक वर्ष का समझौता किया। समझौते की राशि पूरी तरह उनपर छोड़ दी गई और वास्तविक संचित धनराशि ८२३६/— प्राप्त हुई जो पूर्व आशा से अधिक थी। प्रान्त की चुगी जो लगभग चार लाख रुपये थी उसे सम्मिलित नहीं किया गया। इसे जोड़ने के बाद भी कुल धनराशि

62 वही पृष्ठ-१८८-१८९

63 वही पृष्ठ-१९२-१९४

वारेन हैस्टिंग्स द्वारा निश्चित धन से १ लाख कम थी।⁶⁴ इन वर्षों में राजा राज्य के प्रशासन के लिए जिम्मेदार नहीं था अतः विगत वर्षों उसकी जागीर की भूमि से हुई कमी के लिए उससे नहीं पूछा जा सकता था। डकन ने जमींदारों, मुस्लिम पेशनर्स को दिये जा रहे भत्ते में कटौती करके आमदनी बढ़ाने का सुझाव दिया किन्तु इस तरह के कार्य से सरकार अपने प्रति जनता की आस्था को कम नहीं करना चाहती थी।⁶⁵ डकन का सुझाव अस्वीकार कर दिया गया। डकन को उन्होंने बार-बार बनारस मण्डल में ऐसे कार्य के लिए मना किया। यह तर्क भी रखा गया कि समझौता स्थाई है जबकि हॉनि अस्थायी। रैयत की सुविधा पर ध्यान देने के लिए जामा को कम करने में ब्रिटिश शासन को विशेष रुचि थी।

बोर्ड ने देश की सुख और शान्ति के परिपेक्ष में समझौते का लाभप्रद प्रभाव देखा। उसे ज्ञात हुआ कि २५ जून १७८८ के नियम की गणना इसी आशय से की गई थी। आमिलों के लिए ११८६ फरस्ती से एक पथ प्रदर्शक का कार्य प्रारम्भ हुआ। १४ जून १७८६ के आदेशानुसार आन्तरिक व्यवस्था दूसरे वर्ष के पट्टे की शर्त पर पाँच वर्ष के लिए किया गया।

आमिल जमींदारों या पैतृक भूमि मालिकों को गाँव एवं जमीन देते थे। जमींदार ने कानूनगो को 'डोल' देने से मना कर दिया।⁶⁶

64 वही पृष्ठ— २१०—२११

65 वही जून १७, १७८६— पृष्ठ—३६६

66 वही पृष्ठ ३६४—३६५

राजा महीप नारायण सिंह इस आदेश से सहमत थे क्योंकि उन्होंने सोचा कि जमींदारों को स्थायीरूप से नहीं बल्कि सालाना कृषकों के नाम से कई गाँवों को लगान पर देने से लाभ है। ये जमींदार परगना के आश्रित थे। वे खजाने में धन जमा करते थे। इसका परिणाम यह हुआ कि उनकी दशा दयनीय हो गयी किन्तु इतना निश्चित था कि कुछ समय के बाद वे गाँव के स्थायी लगान देने वाले बन जायेंगे।⁶⁷

डकन के बनारस प्रान्त में बिहार प्रान्त की तरह दस वर्ष में एक बार समझौता करने का आदेश हुआ। इससे लोगों को निरन्तर अपने श्रम में आनन्द और शान्ति का अनुभव होगा।⁶⁸ लगान रबी की फसल के आने के पहले ही निश्चित की जाती थी। जमींदारों और किसानों के बीच एक वर्ष की कबूलियत होने लगी। जब आमिलों को यह ज्ञात होता था कि छोटे किसान लगान नहीं दे सकते तो वे भूमि निश्चित लगान प्राप्त करने के हेतु दूसरे किसानों को उनसे वापस लेकर दे देते थे। इससे छोटे किसानों में निराशा व्याप्त हुई।⁶⁹ बोर्ड ने इस आदेश की एक प्रति डकन के पास भेज दिया। उससे अपने विचार व्यक्त करते हुए सरकार से बिहार प्रान्त की भाँति बनारस में भी स्थाई समझौते के लिए आग्रह करने को कहा गया। डकन से इस योजना हेतु राजा को बाध्य करने के लिए कहा गया। डकन ने राजा को भली-भाँति समझाया कि यह स्थाई समझौता देश और राजा दोनों के लिए लाभप्रद है।⁷⁰

⁶⁷ वही पृष्ठ-३२०-३२७ (जून १४, १७८७)

⁶⁸ वही जून-१७, १७८६, पृष्ठ-४०७

⁶⁹ वही पृष्ठ-४०८

⁷⁰ वही अक्टूबर-२१, १७८६ पृष्ठ-४२३ (६ जुलाई १७८६ के पत्र के एक सलग्नक से उद्धृत)।

राजा की सहमति से डकन ने दसवर्षीय नियम उन जिलो मे लागू करने का निश्चय किया जो पॉच वर्षीय पट्टे के अन्तर्गत नही थे। इस कार्य के लिए अति विश्वसनीय आमील नियुक्त किये गये।⁷¹

एक स्थाई अमीन भी रखा गया जिसे यह आदेश दिया गया कि—

(१) यदि गाँव के तीन चौथाई भाग मे कृषि होती है तो उसमे दस वर्ष तक लगान एक समान रहेगा और कोई परिवर्तन नही किया जायेगा।

(२) यदि भूमि इसी क्षेत्रफल मे बजर पडी है तो समझौता पॉच या छ वर्ष के लिए किया जायेगा।

(३) स्ट्रिट की दूकान तथा जूलाहो आदि जिनके कार्य अभी शुरू हुये है उन्हें जमीदारो द्वारा स्वीकृत पट्टे से अलग ही रखा जाय।

(४) जो जमीदार उचित लगान जमा करने को राजी न हो उनसे गाँव लेकर दूसरे जमीदार को दे दिया जाय और ऐसे जमीदारो की जीविका के लिए कोई अन्य साधन उपलब्ध कराया जाय।

(५) स्त्रियो और नाबालिगो के गाँवो को लेकर उनके परिवार के किसी सदस्य या किसी मित्र को दे दिया जाय और उनके लिए १० प्रतिशत भत्ता मजूर कर दिया जाय।

कानूनगो के पास एक विज्ञापन इस आशय का भेजा गया कि वे नगदी भूमि का लगान चौधरी काजी और परगना के किसी मुखिया के

71 वही पृष्ठ—४९६ एव वही— पृष्ठ ४९०—४९१ (२७ जुलाई १७८६ के एक सलग्नक से उद्धृत)।

समक्ष १९६६ फरस्ली के समझौते के आधार पर निश्चित करे। नकदी और 'मुशखासी' भूमि का लगान रैयत पूरे वर्ष भर बिना किसी अबवाब के जमा करे। बटाई भूमि के लिए लट्ठे की लम्बाई निश्चित कर दी गई।⁷² देश के विभिन्न भागों में लट्ठे की लम्बाई बराबर न होने से नाप में कठिनाई उत्पन्न हुई। आमिलों के सहायक बीघा का नाप करते समय रस्सी के दोनों छोरों पर गांठ लगा देते थे जिसके कारण बीघे की लम्बाई कम होती जाती थी।⁷³ पूरे प्रान्त में बीघा तीन श्रेणियों में बटा था—

(१) डकन द्वारा निश्चित ५६ वर्गगज का

(२) मूलस्थानीय परगना बीघा

(३) स्थानीय बीघा जो गाँठ लगा कर छोटा कर दिया गया था।⁷⁴

डकन ने विभिन्न कठिनाईयों और धूर्तता आदि से बचने के लिए १०८७ फरस्ली में प्रचलित प्रमाणिक बीघा प्रणाली लागू किया और इसे कार्यान्वित करने का आदेश दिया। कानूनगो के प्रस्ताव को स्वीकार करते हुए डकन ने धूस परगना में ८००० बीघा और जौनपुर की सीमा पर ५००० बीघा बेकार पड़ी भूमि को कृषि कार्य में उपयोग करने का आदेश दिया।⁷⁵ २५ जून १७८८ के आदेश के आधार पर डकन ने १९८६ फरस्ली पट्टों में कुछ नयी धाराएँ जोड़ दीं। अब डकन का ध्यान चार वर्षीय पट्टों को दस

⁷² वही—जुलाई १७८६ पृष्ठ ८-६

⁷³ वही पृष्ठ-६

⁷⁴ ओल्डम्—पूर्व उद्धृत पृष्ठ-१३१-१३२

⁷⁵ बोर्ड आफ रेवन्यू करसपान्डेन्स अक्टूबर २१, १७८६ पृष्ठ ३३६-३४१

वर्षीय पट्टो मे बदलने से पूर्व भूमि पर कर लगाने की ओर आकर्षित हुआ।

प्रत्येक परगना के मुफस्सिल कानूनगो को वर्तमान भूमालिको के लिए दस या चार वर्ष के औसत पर कर निर्धारित करने तथा दस वर्ष का हिसाब चुकाने का आदेश हुआ। उनसे घोषणा पत्र पर शपथपूर्वक हस्ताक्षर कराया जाता था। जिसमे यह लिखा होता था कि उन्होंने पट्टे मे कोई तथ्य छुपाया नहीं है और न ही कोई गलत बयान दिया है। उन्हें २५ जून १७८८ के नियमों के अनुसार लगान वसूलने का आदेश दिया गया।⁷⁶

आमिलों को भी अपनी ईमानदारी पूर्ण कार्य के लिए शपथ घोषणा पत्र प्रस्तुत करना पड़ता था। उन्हें भी २५ जून १७८८ के नियमानुसार लगान वसूलने का आदेश दिया गया। बटाई लगान वाली भूमि भी उसी लट्ठे से नापी जाती थी और उनकी पैदावार का निर्णय पचो या कानूनगो के द्वारा 'कुनकूट' के आधार होता था जिसका विभाजन बडे ही न्यायिक ढंग से होता था।

जनवरी फरवरी माह मे खरीफ के अन्न का मूल्य निर्धारित होता था और रबी के फसल का मई जून मे। कानूनगो को शपथ लेनी पड़ती थी कि वे अम्बवाब के साथ रैयत से सही-सही लगान वसूल करेंगे और नाप जोख मे किसी अन्य लट्ठे का प्रयोग नहीं करेंगे।⁷⁷

76 वही—अक्टूबर २ १७८६, पृष्ठ १५३—१५४

77 वही— नवम्बर २७, १७८६ पृष्ठ ३६६—३८४

२२ अक्टूबर १७८६ में डकन गवर्नर जनरल से मुफरिसल के एक मुख्य विषय पर परामर्श के लिए कलकत्ता गया हुआ था। वहाँ से लौटने के तुरन्त बाद ६ नवम्बर १७८६ को राजा से स्वीकृति प्राप्त करके उसने पूरे प्रान्त का दौरा किया। जादूपुर में आवश्यकता से बहुत कम जमींदार थे। बनारस में ५००० गाव थे जिनमें लगभग ३००० के पास लगल-अलग जिलो में जमीन थी। शेष जमींदारों को बलवन्त सिंह ने अपने शासनकाल में निकाल दिया था। यह कार्य २१ मई १७७५ में बनारस राज्य कम्पनी को सौंपने से पूर्व किया था।⁷⁸ डकन द्वारा दौरा करने का उद्देश्य मुफरिसल में दस वर्षीय समझौते का निरीक्षण करना, दरों में सशोधन करना और आमिल तथा कानूनगो के द्वारा प्रस्तावित समझौतों तथा अन्य त्रुटियों में सशोधन तथा सुधार करना था।

जिन गावों में कृषि कार्य के बिना अधिकांश भूमि बेकार पड़ी थी वहाँ पर धीरे-धीरे लगान में उचित बढ़ोत्तरी की गई जिससे लगान देने वाले इस भूमि पर कृषि कार्य प्रारम्भ कर दें और उन्हें कुछ लाभ प्राप्त हो।⁷⁹

आगे की धारा के अनुसार शराब आदि के दूकानदारों तथा जुलाहों के ऊपर आमिलों द्वारा कर वसूली में से जो आबकारी की सजा के अन्तर्गत आते थे उनमें से 'घुरदेवारी' तथा 'खरगुई' से पृथक् कर दिया जाता था जो रैयत से लिया जाता था।

⁷⁸ वही नवम्बर २५, १७८६ पृष्ठ ३६६-३८४

⁷⁹ वही पृष्ठ १४६-१५२

**भू-राजस्व व्यवस्था
भाग (२)**

भू-राजस्व व्यवस्था (भाग-२)

राजस्व वसूलने वालों को १७८७ की दर के अन्तर्गत अपने एकत्रित किये हुए राशि को सीमित करना था। उन्हें नये और पुराने लट्ठे के अन्तर को प्रत्येक पट्टे में दर्ज करना पड़ता था। वसीयतनामे में भी लगान वसूली के नियम दर्ज होते थे। लगान चुकाने वाले किसान या जमींदार ११६५ फसली तक परती पड़ी जमीन पर कृषि नहीं कर सकते थे। जमींदार अपने सीमाक्षेत्र में यात्रियों तथा व्यापारियों की चोरी डकैती आदि के लिए उत्तरदायी होते थे। यदि वे चोरी या डकैती में लूटी गई सम्पत्ति का पता नहीं लगा पाते थे तो उन्हीं को उनका मूल्य अदा करना पड़ता था।¹

सभी गाव और परगना में सही लगान निर्धारण की ओर डकन ने अपना ध्यान केन्द्रित किया। प्रत्येक जिले का नाम, जमींदारों और नदियों की संख्या, व्यापार और कारखानों में उत्पादित वस्तुओं की मात्रा की जानकारी प्राप्त किया। प्रत्येक परगना में समझौते का हिसाब-किताब ठीक हो जाने के बाद उनमें अगले छ वर्षों के लिए चार वर्षीय पट्टा स्थायी कर दिये जाने का आदेश हुआ।²

जब तक पट्टा मालिक पट्टे में दर्ज निर्धारित लगान चुकाते रहते थे तब तक उनसे कोई अन्य राशि वसूल नहीं की जाती थी। इस प्रकार

1 बोर्ड ऑफ रेवन्यू करसापान्डेन्स, नवम्बर २५, १७८७, पृष्ठ १५२-१५४

2 वही-पृष्ठ १५५-१५८

समझौता पूरे बनारस प्रान्त में कर लिया गया^१ जिसके कारण १७८६-६० की सम्पूर्ण राशि जो ८५ हजार रु० से अधिक थी वसूल हो गयी। १७७२ में लार्ड कार्नवालिस ने डकन को मालाबार (जिसे टीपू सुल्तान ने छोड़ दिया था) कमिश्नर बना कर भेजा। डकन के चले जाने से बनारस प्रान्त में स्थायी समझौता करने में विलम्ब हो रहा था क्योंकि कार्नवालिस इसे डकन की अनुपस्थिति में नहीं करना चाहता था। पीट्रियेस ने लगभग डेढ़ वर्ष तक डकन के पद पर कार्य किया। लार्ड कार्नवालिस के बाद सर जॉनशोर आये और उन्होंने बनारस में अधूरे कार्य को पूर्ण करने का प्रयास किया। इस हेतु राजा बनारस की स्वीकृति बड़ी मुश्किल से प्राप्त हुई।^४

डकन प्राचीन समझौते में व्याप्त कुछ त्रुटि को समाप्त करना चाहता था। ४७०० पट्टों में से ७०० पट्टों का समय समाप्त हो चुका था। उनके प्रभावहीन हो जाने से उन्होंने उसे छोड़ दिया।^५ वह न्यायविरुद्ध तलबाना की माग को सीमित करने की व्यवस्था का प्रयत्न कर रहा था। अपने आमिलों के लिए एक दण्ड विधान इस आशय से बनाना चाहता था कि कानूनगो से बिना प्रमाणित कराये तलबाचिट्ठी किसी को न दी जाय। इसके लिए उन्हें एक रजिस्टर रखना पड़ता था जिसमें तलबाना की राशि एवं दर दर्ज करना पड़ता था और उसे वर्ष के अन्त में मुल्की खजाना में जमा करना पड़ता था।^६

१ वही फरवरी ११, १७६१ पृष्ठ ३२१

४ ओल्डम-पूर्व उद्धृत पृष्ठ-१६८

५ बोर्ड ऑफ रेवन्यू कररायान्डेन्स जुलाई २२ १७६४ पृष्ठ ३७८

६ वही पृष्ठ-३८१

डकन ने यह बात राजा की जानकारी में रखी कि सग्रह की अतिरिक्त राशि लगातार उसी को मिले जिसका एक अश हिन्दू कालेज की रक्षा के लिए सड़क, पुल बनवाने एवं जमींदारी की प्रजा की उन्नति के लिए, न्यायालय संस्थापन के लिए निकाल कर शेष राशि राजा को दे दी जाये।⁷

अब डकन मुफरिसल के सुधार में व्यस्त हो गया। बोर्ड ने कुछ पत्र डकन के विचार के लिए भेजे। वह राजा को इस बात से अवगत कराना चाहता था कि वह उसके अधिकारियों के हिसाब के नकल की एक प्रति अपने पास रखे। पट्टों पर राजा का हस्ताक्षर पूर्ववत् होता रहे।⁸

चूँकि इस प्रणाली का यह अभी प्रारम्भ ही था अतः बोर्ड ने सोचा कि सभी व्यवहारिक मामलों में भूमि मालिक और किसानों का भूमि लगान सदैव के लिए निश्चित कर दिया जाय। इसका उद्देश्य व्यक्तिगत अधिकारों की रक्षा करना था। कृषिकार्य से लगे लोगों पर इसे अनिवार्य रूप से लागू करने के वह पक्ष में था। बोर्ड की सिफारिश यह थी कि समझौता उन्हीं के साथ हो जो अधिकार सम्पन्न और कबूलियत हो। अयोग्य और दुराचारी जमींदारों के समझौतों को रेजीडेन्ट समाप्त करके भूमि किसी दूसरे को देने के पक्ष में था। पट्टेदारों को व्यवसाय में आने वाली कठिनाई से बचाने के लिए उन्हें एक मैनेजर रखने को कहा गया किन्तु डकन के विचार से यह उचित नहीं था। वह प्रत्येक व्यक्ति को पट्टा देना चाहता था। जिन जिलों में स्थायी जमींदार नहीं थे वहाँ गाव

7 वही—सितम्बर १६, १७६४ पृष्ठ ११०—१११

8 वही—

के प्रधान व्यक्ति के साथ स्थायी सकझौता करने का सुझाव बोर्ड ने दिया और उसका लगान भी निर्धारित कर दिया।⁹

इस सिद्धान्त के आधार पर लगान सीधे बनारस के सरकारी खजाने में जमा होता था। बोर्ड ने सोचा कि कलेक्टरों को निर्धारित लगान वसूलने का समय भी निर्धारित हो।¹⁰ उन्हें न्यायिक अधिकार से वंचित रखा गया। बोर्ड का विचार था कि जो कलेक्टर नियत लगान की राशि से अधिक की माग करते थे उन्हें दण्डित किया जाय। आमिलों को तहसीलदार या स्थानीय कलेक्टर की सजा दी गयी। उन्हें दीवानी के सभी मामलों जो व्यक्तिगत सम्पत्ति के लिए या १००/- से अधिक के होते थे निपटारा करने का अधिकार दिया गया।¹¹ बोर्ड ने कानूनगो के पद को उसी भत्ते पर स्थानीय रजिस्ट्रार के पद में बदल देने का विचार किया तथा उन्हें कलेक्टर के सस्थापन के अग के रूप में माना। चूँकि पैदावार में लगातार हेर फेर होता रहता था अतः यह उचित समझा गया कि कुछ ऐसे अधिकारी नियुक्त किये जायें जो लगान वसूलने वाले अधिकारी को समय-समय पर पैदावार सम्बन्धी सूचना देते रहे। भूमि और जामा का हिसाब रखने वाले को पटवारी कहा गया।¹²

डकन ने बोर्ड को अपनी टिप्पणी के साथ इन आदेशों के आधार पर कुछ नियम बना कर भेज दिये। उसने १३ अक्टूबर १७८४ को प्रान्त का अतिरिक्त लगान जो लगभग १,४०,०००/- था सडको की मरम्मत पुलों के

9 वही—पृष्ठ ११५—११६

10 वही पृष्ठ—११७—११६

11 वही पृष्ठ १२०—१२७

12 वही पृष्ठ—१३४

निर्माण तथा जनता पर व्यय के लिए राजा को देने का सुझाव दिया।¹³ इस सुझाव का आशय राजा द्वारा किये जाने वाले अतिरिक्त माग को कम करना था। राजा की आय में बढोत्तरी देश के लिए क्षति बताया गया क्योंकि जनता को लाभ पहुँचाना अधिक आवश्यक था।¹⁴ डकन ने यह भी सुझाव दिया कि भूमि का हस्तान्तरण आवश्यक नहीं है। जो लोग मौसम की खराबी या अन्य किसी कारण से लगान नहीं देते उन्हें कलेक्टर दण्डित कर सकता है।¹⁵ बोर्ड ने डकन के सुझाव को स्वीकार कर लिया। यह नियम धारा २, १७६५ के अन्तर्गत स्थायी कर दिया गया।¹⁶

उसने भूमि की नाप करवायी और ११८७ फसली की दर के अनुसार लगान निर्धारित कर दिया गया। रैयत की शिकायत का आमिलो द्वारा समाधान करवाया। जब स्थायी समझौते की अधिक शिकायतें आने लगी तो डकन ने यह अनुभव किया कि उसके जाने के बाद उसके स्थान पर आने वाले अधिकारी को किसानों को दिये गये सुरक्षा पर कम प्रभाव पड़ेगा। पट्टों में लगान की दर बदल देने से अनेक झगड़े खड़े हो गये। किन्तु जहाँ भूमि मालिक और किसान सन्तुष्ट और सहमत थे वहाँ १७६४ की धारा ४ नियम पारित किया गया।¹⁷

जहाँ कोई विवाद या शिकायत नहीं थी वहाँ पट्टा देना उतना आवश्यक नहीं था। यदि कहीं अमीन लोग लगान की दर निर्धारित करने

13 वही पृष्ठ- १३५

14 वही अक्टूबर-१३ १७६४ पृष्ठ-२२६

15 वही अक्टूबर- २०, १७६४, पृष्ठ-२२७

16 बंगाल रेग्यूलेशन , प्रथम, पृष्ठ २०६

17 वही मार्च १८, १७६५ पृष्ठ १०५-१०६

मे पक्षपात करते थे सरकार उन्हें वहाँ से हटा देती थी।¹⁸ जमींदार और ताल्लुकेदार की स्थिति इससे भिन्न थी। जमींदारों को अपनी सम्पत्ति बेचने का अधिकार था बशर्ते वे ताल्लुकेदार को निरन्तर जामा की राशि अदा करते रहे।

उन स्थानों में जहाँ पैतृक जमींदार या ताल्लुकेदार नहीं थे उस स्थान को लगान वसूलने के लिए आमिलों को पट्टे पर दे दिया जाता था।¹⁹ ऐसे आमिलों की स्थिति प्रत्येक वर्ष राजा की कृपा पर निर्भर होती थी। १७६५ की धारा २, अनुभाग १५ के समझौते से उनकी स्थिति में कुछ स्थायित्व आया।²⁰ बनारस में किया गया समझौता बंगाल के समझौते से भिन्न था। बनारस में भूमि की पैमाइश हुई किन्तु बंगाल में नहीं हुई। इससे कुछ मतभेद उत्पन्न हुआ। सर जॉन शोर और लार्ड कार्नवालिस जमींदारों को भूमि का मालिक समझते थे। किन्तु हेस्टिंग्स और ग्रान्ट उन्हें लगान वसूलने वाला ही समझते थे। यह पिछली धारणा भारतीय परम्परा से मिलती जुलती थी। इस प्रकार भूमि पर जमींदारों का पैतृक अधिकार नहीं था। बनारस का समझौता एक प्रकार का सुधार था जिसमें सही भूमि मालिक को स्थायी अधिकार प्रदान किया गया।

18 वही जून २६, १७६५ पृष्ठ-२२६-२६७

19 बंगाल रेग्यूलेशन-भाग-प्रथम, पृष्ठ २१३-२१४

20. वही पृष्ठ - २२५

समझौते के दोष

बनारस का समझौता जिसे डकन ने बड़ी ही बुद्धिमानी, योग्यता और उदारता के साथ किया था उसमें कुछ बड़े दोष भी थे।²¹ जैसे —

(१) जमींदारों में आन्तरिक कलह होने लगा जिससे बकाया लगान की वसूली में बाधा पड़ी।

(२) राज्य का समझौता नाप जोख पर आधारित नहीं था।

(३) राज्य के बीच में सीमाएँ नहीं बनायीं गयीं।

(४) भिन्न-भिन्न सम्मिलित भूमि मालिकों के हिस्से की रकम निश्चित करने एवं दर्ज करने की नीति नहीं अपनायी गयी।

(५) नियुक्त किये गये नम्बरदार जमींदारों के सही व्यक्ति नहीं थे।

(६) महाल बड़े-बड़े बनाये गये थे।

डकन की इच्छा थी कि प्रान्त में पैमाइश करवायी जाय किन्तु पुन विचार करने पर यह ज्ञात हुआ कि पहले करायी गयी नाप-जोख अधिक समय बीत जाने पर अव्यवहारिक हो जायेगी। उसने उसके स्थान पर 'डोल' का प्रयोग किया।²² जमींदार पुन पैमाइश के लिए प्रार्थनापत्र देते थे किन्तु उनकी माग स्वीकार नहीं की जाती थी। मार्च १७६१ के डकन के रेकार्ड से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि बिना नाप जोख के समझौतों को

²¹ टेनैन्ट्स राइट्स एण्ड ऑक्शन रोल्स इन गाजीपुर एण्ड राइट्स बनारस प्राविन्स (वी० आर० सी, जिल्द ६५ पृष्ठ २१)।

²² बोर्ड ऑफ रेवन्यू करसर्पॉन्डेन्स अप्रैल २६, १७८६ पृष्ठ १८१

स्थायी बनाने में अधिक बाधा उत्पन्न होती है।²³ कुछ राज्यों को छोड़कर (जहाँ कुछ विशेष कार्य हुआ) न तो सीमा निर्धारित हुयी और न ही कोई निशान बनाया गया था। व्यर्थ भूमि के किनारे-किनारे जंगल थे। सीमा के लिए निरन्तर लड़ाई झगड़े होते रहते थे जिसके कारण लगान की अदायगी में बाधा पड़ती थी। ऐसे व्यक्ति जिनके पास उनके हिस्से से अधिक भूमि थी वे उसकी रक्षा के लिए प्रार्थना करते थे।²⁴

डकन के इस कार्य से यह सही-सही ज्ञात नहीं हो पाता कि विवाद का निपटारा पैतृक अधिकार को ही मान कर किया गया अथवा नहीं। इनके लिए कोई निश्चित नियम नहीं था। सुधार का कोई विधान नहीं था। पारिवारिक या व्यक्तिगत हिस्से की राशि न कही दर्ज थी और न निश्चित। बराबरी के भागीदारों को अपने झगड़ों का स्वयं निपटारा करने का आदेश प्रदान किया गया। चूँकि नम्बरदार जमींदार के उचित प्रतिनिधि नहीं थे इसलिए उनकी जिम्मेदारी डकन पर ही थी। कुछ को छोड़कर शेष १७६० से १७६४ के मध्य के सभी पट्टों को स्वीकार कर लिया गया।²⁵ स्थायी समझौते को अधिकांश मामलों में सफल बनाने में सरकार असमर्थ थी। डकन बड़े महाल को उचित समझता था किन्तु जितने छोटे महाल होते थे प्रशासन कार्य उतना ही सरलता पूर्वक होता था।²⁶ बड़े-बड़े महाल की स्थिति इसी से समझी जा सकती है कि गाजीपुर में किसी किसी महाल में २०,००० एकड़ से अधिक की भूमि थी जिसका लगान

²³ टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड आक्शन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दी बनारस प्राविन्स (बी० आर० सी-जिल्द ४५, पृष्ठ-२२)।

²⁴ वही -

²⁵ वही पृष्ठ- २२ २३

²⁶ वही -

२५०००/- था और इनमे जमींदारो की सख्या कई हजार मे थी। उन्हे नीलाम किया जा सकता था। भाग्यवश अनेक मामलो मे बनारस की ग्रान्तीय अदालत मे इनके विक्रय को निरस्त कर दिया गया तथा कुछ मामलो मे सरकार ने नीलामी मे दिये गये राज्य को पुन वापस ले लिया। उनके लिए सही और नये भूमि मालिको से समझौता कर लिया गया।

अगर ऐसा न होता तो समझौता बिल्कुल असम्भव हो जाता। उक्त दोषो के होते हुये भी नि सन्देह यह एक उत्तम समझौता था। १८४० मे समझौता अधिकारियो द्वारा प्रान्त के प्रत्येक गाव का निरीक्षण, योग्य योरोपियनो द्वारा भूमि की पुन पैमाइश तथा प्रशिक्षित भारतीयो द्वारा गावो का आन्तरिक बटवारा वास्तव मे आश्चर्यजनक कार्य थे।²⁷

स्थायी समझौते का लाभ

विभिन्न पहलुओ को देखते हुए यह कहना अनुचित नही होगा कि डकन द्वारा किया गया समझौता विशेषरूप से श्रेष्ठ था। इससे कम्पनी को लगान स्वरूप प्राप्त होने वाली एक बडी राशि मे सुधार हुआ इससे शासनशक्ति दृढ हुई। इसके कार्यान्वित होने से भूमि मालिको को लाभ हुआ और वे अब राजा के कष्टप्रद शासन को भूल गये।

जमींदारो को सरकारी खजाने मे निर्धारित राशि जमा करनी पडती थी जिसे वे वैध अथवा अवैध रूप से जैसा चाहते थे कृषको से वसूल करते थे। रकम की निश्चित सीमा का प्राय उल्लघन करते थे। इसी सन्दर्भ मे

²⁷ ओल्डम - पूर्व उद्धृत-पृष्ठ १७५

प्रसिद्ध समाजशास्त्री राधाकमल मुखर्जी ने लिखा है कि १६वीं शताब्दी के अन्तिम चरण तक कृषक अपने उचित लगान का तीस गुना राशि देने लगे थे।²⁸

स्थायी समझौते से हॉनि

कम्पनी की माग लगान के लिए स्थायी रूप से निश्चित की गयी जिसे अन्य क्षेत्रों की भांति सरलता से परिवर्तित नहीं किया जा सकता था। बनारस में अनेक लोगों की साझीदारी में कई राज्य थे जिनमें से मात्र दो या तीन लोगों को ही स्वतन्त्रतापूर्वक लगान वसूल करने के लिए चुना जाता था। पट्टे भी उन्हीं को मिलते थे। उन्हीं का नाम भी मालिक के रूप में दर्ज किया जाता था। जहाँ उनका प्रबन्ध व्यवस्थित था वहाँ किसी प्रकार की हॉनि नहीं थी किन्तु जहाँ उनका प्रबन्ध ठीक नहीं था वहाँ दूसरे साझीदारों के गावों की सम्पत्ति बकाया लगान की सुरक्षा के लिए नीलाम कर दी जाती थी।

इस समझौते के अनुसार छोटे साझीदारों के मालिकाना की सुरक्षा नीलाम के पश्चात् पूर्णतः समाप्त हो जाती थी। स्थायी समझौता शासकों के लिए बड़ी हुई भूमि कर को संग्रह करने में बाधक हुयी। लार्ड कार्नवालिस जितना भी अर्जित हो सकता था उसके लिए प्रयासरत था।

लार्ड विलियम बेन्टिक भारत में एक उदार गवर्नर जनरल के रूप में जाना जाता था। उसने गवर्नर जनरल की हैसियत से ८ नवम्बर १८२६

28 आर० के० मुखर्जी लैण्ड प्राबलम्स इन इण्डिया—पृष्ठ ३०५

को यह लिखा था कि "यदि विद्रोह के हलचल का निरीक्षण किया जाय तो मैं यह कह सकता हूँ कि यद्यपि स्थायी समझौते की अनेक बातों में सरकार असफल रही किन्तु इसका सर्वाच्च लाभ यह रहा कि असंख्य धनी जमींदार ब्रिटिश राज्य को बनाये रखने में और जनता पर ब्रिटिश प्रभुत्व स्थापित करने में सहायक हुये।"²⁹

१४ जून १७८६ के अपने आदेश में डकन ने लगान चुकाने में असमर्थ होने पर नीलामी, बिक्री का कहीं सकेत नहीं किया था किन्तु कुछ समय पश्चात् सरकार ने बगाल तथा उड़ीसा प्रान्तों की भाँति बनारस प्रान्त में भी समझौते की योजना बनाने का डकन को आदेश दिया। गाजीपुर परगना में भी दसवर्षीय योजना बनाने का आदेश निर्गत हुआ और यही पूरे प्रान्त में प्रचलित हुआ³⁰

बगाल के नियम और बिक्रीकर व्यवस्था को बनारस तक में लागू करने का प्रस्ताव किया गया। किन्तु, डकन ने इसका विरोध किया। उसने सरकार को परामर्श दिया कि भूमि सम्पत्ति स्थानान्तरण अधिकार के लिए या बकाया लगान जो मौसम की खराबी के कारण रह गया हो, बिक्रीकर लेना आवश्यक नहीं है। बगाल में जमींदार को जब तक लगान अदा न कर दे दण्डित किया जाता रहता था।³¹ डकन की सलाह पर सरकार ने यह निश्चित किया कि जो भू-स्वामी लगान देने में असमर्थ थे उनके लिए बिक्रीकर के नियम सामान्य न बना दिये जाय। उसने यह भी सुझाव दिया कि दण्डित करने की अपेक्षा रेजीडेन्ट ऐसे लोगों की भूमि तब तक के

29 ए० बी० कीथ, स्पीचेज, एण्ड डाक्यूमेन्ट्स ऑन इण्डियन पॉलिसी—जिल्द-१— पृष्ठ २१५

30 बोर्ड आफ रेवेन्यू क्लर्कपोन्डेन्स अक्टूबर २१, १७८६ पृष्ठ-४१०

31 वही— अक्टूबर २०, १७६४— पृष्ठ २२७-२२८

लिए ले ले जब तक कि वे पूरी राशि न दे दे। इसके अतिरिक्त स्थायी समझौते में उल्लेखित कोई सन्तोषप्रद जमानत वे दे सकते थे।³²

इन्हीं सुझावों और परामर्श के आधार पर बनारस प्रान्त में १७६५ का नियम-६ लगान वसूली हेतु बनाया गया। इस नियम के अन्तर्गत वैध प्रणाली निम्नवत् थी।³³

(१) फसल के ऊपर चौकीदारों की नियुक्ति की जाय।

(२) अपराधी के खर्च पर पैदल चलने वाले या घुड़सवार के माग की रिपोर्ट जारी हुई।

(३) अपराधियों को गिरफ्तार करके जेल भेजना भी निश्चित किया गया।

(४) नम्बरदारों के पट्टे को हटाकर सीधे-सीधे असामियों से लगान वसूलने की व्यवस्था की गयी।

इन नियमों के लागू करने पर भी वर्ष के अन्त में कुछ लगान बाकी रह जाता था। १७६५ के नियम-६ अनुभाग १७ के अन्तर्गत कलेक्टरों को बकाया लगान के कारणों का एक विस्तृत विवरण प्रस्तुत करना पड़ता था। यदि अवशेष का कारण पैदावार की राशि का गबन सिद्ध होता था तो गवर्नर जनरल को भूस्वामियों के अधिकार रद्द कर देने का अधिकार प्राप्त था।³⁴

32 वही नवम्बर-७, १७६४, पृष्ठ ७०-७१

33 बंगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ २३६-२३६

34 वही- पृष्ठ २४०-२४१

भूमि की बिक्री का आदेश देना गवर्नर जनरल की इच्छा पर आधारित था। अनुभाग-१ में यह स्पष्ट लिखा हुआ है कि १७६६ का नियम-६ बनारस तक बढ़ा दिया गया है। यह नियम बनारस के वसूली नियम के अनुरूप था।³⁵ १७६५ का नियम-६, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के विशेष सिफारिश पर लागू हुआ था, को असाधारण एवं विशेष मामलों की निगरानी सीमित कर देने का तब तक आदेश नहीं था जब तक १८३० का नियम-७ इसके स्थान पर जारी नहीं हुआ।³⁶ सामान्यतः भूमि बिक्री का कार्य कलकत्ता में होता था। भूमि मालिकों को बिक्री के एक दिन पहले और जिले के कलेक्टर को दस दिन पहले बिक्री की तिथि आदि सूचित कर दिया जाता था।³⁷

किसी बिक्री के पूर्व उस नियम के अनुभाग-३२ के अन्तर्गत दूर-दूर तक 'मुनादी' करनी पड़ती थी जो फारसी, देवनागरी और हिन्दुस्तानी भाषा में होता था। बिक्री का स्थान समय और तिथि लोगों को बताया जाता था।³⁸ बिक्री के समय क्रय मूल्य का ५ प्रतिशत जमा करना पड़ता था। यदि खरीददार नियत समय पर क्रय मूल्य जमा नहीं कर पाता था तो उसकी जमा की हुई राशि सरकार को दे दी जाती थी और फिर उसी के खर्च से भूमि की बिक्री होती थी।³⁹ १७६५ में बनारस की कलेक्ट्री के स्थापित होने के पश्चात् डकन द्वारा बड़ी सावधानी पूर्वक लगान वसूलने

³⁵ वही— पृष्ठ ४२०-४२१

³⁶ वही पृष्ठ ४५२

³⁷ वही पृष्ठ-२२६

³⁸ वही — २२६

³⁹ वही — २२६

के बावजूद भी लगान बाकी रह जाता था। बकाया लगान वसूलने का नियम मात्र नीलामी ही था।

कलेक्टरों को इन नीलामियों में बहुत समय लग जाता था। बनारस के कलेक्टर मि० डब्लू० ओ० सॉलमन ने लिखा था कि उन्हें बिक्री के लिए लगातार कई दिन लगाना पड़ा। गाजीपुर में १८१७ में कलेक्ट्रेट की स्थापना के बाद एक ही माह में वहाँ के कलेक्टर ने हजार से ऊपर राज्यों की बिक्री का प्रस्ताव किया।⁴⁰ इससे यह स्पष्ट हो जाता है कि नीलामी/बिक्री की प्रणाली जिसे गबन के मामलों में लागू किया गया था अवैध थी। लम्बरदार अपने साझीदारों से जबरन लगान वसूलने के बाद भी सरकार को अदा नहीं करते थे। रेवेन्यू सम्बन्धी दस्तावेजों में ऐसे अनेक प्रकरण देखने को मिलते हैं।⁴¹

लार्ड मिंटो ने भी १८०७ के नियमानुसार उक्त प्रणाली को सीमित करने का प्रयास किया। वास्तविक स्थिति स्वाभाविक रूप से भिन्न थी और उसे किसी भी नियम द्वारा बदला नहीं जा सकता था। यद्यपि मिंटो के समय में कठिनाइयाँ कुछ कम हुई थीं किन्तु ऐसा जमींदारों के सहयोग और सहानुभूति के कारण था न कि नियम बदलने के कारण। १ फरवरी १८०६ में बनारस प्रान्त कलकत्ता के नियन्त्रण से अलग कर दिया गया था। १७६५ का कानून जो बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू था वह बनारस में लागू कानून से भिन्न था।⁴²

40 टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड ऑक्शन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दि प्राविन्स ऑफ बनारस (बी० आर० सी० जिल्द - ६५ पृष्ठ २१)

41 वही—

42 वही— पृष्ठ -३६

लगान के प्रशासन की फिर से व्यवस्था की गयी जिसके फलस्वरूप बनारस में मात्र १२ (बारह) तहसीलदार ही रह गये। अधिकांश परगनाओं का लगान सरकारी खजाने में जमा होता था जिसके लिए एक विशेष अधिकारी नियुक्त किया गया था। गाजीपुर का जिला बनारस से अलग कर देने के बाद वहाँ रावर्ट वालों कलेक्टर नियुक्त हुए जो वहाँ १८२७ तक रहे।⁴³

लगान की अदालत

उचित अदालत न होने के कारण लगान सम्बन्धी मामलों को निपटाने में अनेकानेक त्रुटियाँ व्याप्त हो गयी थीं। राजा की मुल्की अदालत पर्याप्त नहीं थी। न्यायाधीश और अधिकारी अधिकांश मुस्लिम थे जो लगान सम्बन्धी कार्य में दक्ष नहीं थे तथा पक्षपात की प्रवृत्ति की कारण उचित न्याय भी नहीं दे पाते थे।

१७६६ फसली के समझौते के अनुसार एक न्यायालय स्थापित हुआ। इसमें दो न्यायाधीश होते थे जिनमें एक रेजीडेन्ट द्वारा तथा दूसरा राजा द्वारा मनोनीत होता था।⁴⁴ यह अदालत रेजीडेन्ट के नियन्त्रण में उसी की अदालत में लगती थी। रेजीडेन्ट लगान सम्बन्धी मामलों के लिए फोर्ट विलियम के नियन्त्रण में था। लगान और कर सरकारी खजाने में जमा होने लगा। यह व्यवस्था तब तक बनी रही जब तक कि गाजीपुर का

⁴³ वही —

⁴⁴ बोर्ड ऑफ रेवन्यू कारसपाण्डेन्स, सितम्बर १२, १७८८ पृष्ठ—१६१

अधिकांश बलिया का कुछ भाग और शाहबाद अलग-अलग नहीं किया गया।

मिर्जापुर जिले का अधिकांश भाग १७७५ तक अवध के नवाबों के नियंत्रण में रहा। इसके पूर्व उत्तरकालीन मुगलों के समय में मिर्जापुर चौदह परगनों में विभाजित था। मुगलकाल में भू-राजस्व निर्धारित करते समय भूमि के उपजाऊपन, औसत मूल्य तथा पिछले वर्ष की उपज को ध्यान में रखा जाता था।⁴⁵ अवध के नवाबों के शासन में भूमि के अधिकारों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता था। उनका उद्देश्य केवल भूमिमालिकों से अधिकधिक राजस्व वसूल करना था। अधिकार और कार्य की दृष्टि से आमिल का पद ब्रिटिश कालीन कलेक्टर या मजिस्ट्रेट की तरह का था। भू-राजस्व की व्यवस्था नियमों पर आधारित थी।⁴⁶

मिर्जापुर १७७५ में ईस्ट इंडिया कम्पनी के नियंत्रण में आया किन्तु १७६४ तक यह भाग राजा बनारस की जमींदारी में बना रहा। २७ अक्टूबर १७६४ में राजा महीप नारायण सिंह व ईस्ट इंडिया कम्पनी के मध्य हुए समझौते के तहत बनारस पर पूरी तरह से कम्पनी का नियंत्रण हो गया।⁴⁷ बलवन्त सिंह के समय में अधिकांश आमिल उनके सगे सम्बन्धी ही थे।⁴⁸ १७८७ तक आमिलों ने कठोर नियंत्रण न होने के कारण भूराजस्व सग्रह में गड़बड़ी की और भू-राजस्व सोलह प्रतिशत तक बढ़ा दिया। राजस्व सग्रह में व्याप्त भ्रष्टाचार को समाप्त करने के लिए डकन ने पट्टाधारी व्यवस्था

45 पी० सरन 'प्राविसियल गर्वन्मेन्ट ऑफ द मुगल्स' पृष्ठ ३६१

46 मुफसिल, रेकार्ड्स, सिरीज-३, वाल्यूम-५

47 मिर्जापुर गजेटियर-पृष्ठ १५६

48 वही -

में भी सुधार किया। आमूल परिवर्तन के उद्देश्य से १९६६ फसली के तहत नया बंदोबस्त करने की स्वीकृति गवर्नर जनरल की परिषद् से प्राप्त हुआ।⁴⁹

एक वर्ष पश्चात जौनपुर भी एक स्वतन्त्र जिला बन गया किन्तु मिर्जापुर १८३२ तक बनारस के अन्तर्गत बना रहा।

समझौतों का प्रबन्ध

लगान वसूली एवं कलेक्टरों के ऊपर नियन्त्रण रखने का अधिकार बोर्ड को था। बोर्ड में एक प्रेसीडेन्सी और चार सदस्य होते थे। न्यायाधीश के फैसले पर पुनर्विचार हेतु अपील करने के लिए एक अदालत की भी व्यवस्था की गयी थी। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को कर्त्तव्य के प्रति निष्ठा न रखने वाले कलेक्टर को पद से हटा देने का पूरा अधिकार था।⁵⁰

बोर्ड ने एक कोर्ट आफ वार्ड्स की स्थापना किया जिनका कार्य अल्पसंख्यक राज्य पर नियन्त्रण रखना तथा उनके हिसाब किताब का निरीक्षण करना था। इसकी रिपोर्ट शासन को निर्धारित समय पर भेजनी पड़ती थी। शासन के माध्यम से कोर्ट आफ रेवेन्यू को लगान के माध्यम की दशा तथा की गयी कार्यवाही की सूचना भी देनी होती थी। किसानों और भूमिमालिकों को 'तकाबी' बांटने का भी इन्हें अधिकार था।⁵¹ कलेक्टर

49. टामस ए०— लैंड सिस्टम इन बनारस राज पृष्ठ १३६.

50. फिफ्थ रिपोर्ट, प्रथम, पृष्ठ—३१.

51. वही बंगाल रेग्यूलेशन— प्रथम, पृष्ठ—२२६.

को बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के उन सभी मामलो तथा निर्देशो पर ध्यान देना पडता था जिनका सम्बन्ध जनता से होता था।⁵²

बोर्ड आफ रेवेन्यू के पथप्रदर्शक नियम

बोर्ड को निर्धारित नियमानुसार कार्य करना होता था। बोर्ड का कार्य अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के कार्यों का निरीक्षण करने तथा दोषी पाये जाने पर दण्डित करने का अधिकार था। अपराधी को कार्यालय में अपराध का कारण आदि बताने के लिए बुलाया जाता था और अपराध सिद्ध होने पर अधिक से अधिक एक माह के वेतन के बराबर उनपर जुर्माना भी लगता था। कभी-कभी उन्हें निलम्बित भी कर दिया जाता था। भ्रष्टाचार लूट, उत्पीडन आदि गम्भीर मामलो की पूरी जाँच होती थी। यदि शिकायत झूठी सिद्ध होती थी तो शिकायत करने वाले को दण्डित किया जाता था और उसे जेल भी होती थी। लगान सम्बन्धी शिकायत कलेक्टर के पास भेजी जाती थी। सम्बन्धित व्यक्ति की जाच होती थी। उन्हें माह के अन्त तक कलेक्टरों को माग, आय और बकाया का हिसाब देना पडता था। प्रतिवर्ष १८ जुलाई तक जिले के समझौते की आय का बकाया का विवरण सुप्रीम काउन्सिल को भेजना पडता था।

उन्हे व्यय के हिसाब का अलग से रजिस्टर रखना पडता था। अपराधियों से बकाया राशि की वापसी और विद्रोही जमींदारों के दमन पर हुये खर्च का ब्योरा भी रखना पडता था। बोर्ड के चालू नियमों को उसे अतिरिक्त आदेश देकर कार्यान्वित भी करना होता था। बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के

⁵² वही पृष्ठ - २२७

सभी योरोपियन या भारतीय अधिकारियों के सभी मामलो मे प्रेसीडेन्ट की आज्ञा का पालन करना पडता था। प्रेसीडेन्ट के सभी अधिकार प्रभारी रेजीडेन्ट को भी प्राप्त थे। प्रेसीडेन्ट की अनुपस्थिति मे वरिष्ठ सदस्य उसका कार्य देखता था।⁵³ १७८८ मे बोर्ड ऑफ रेवन्यू मे दो अन्य सुधार हुये जिनका उद्देश्य भारतीय नियन्त्रण को खालिसा के शासन से हटाकर उसके स्थान पर कम्पनी के नौकरो को रखना था।⁵⁴

प्राप्त शिकायती प्रार्थनापत्रो पर आवश्यक विचार के बाद प्रेसीडेन्ट के निरीक्षणार्थ भेजना पडना था। वे जमीदार, ताल्लुकेदार और भूस्वामियो से किसी प्रकार का उपहार नही ले सकते थे। उन्हे अपनी रिपोर्ट के लिए अग्रेजी या फारसी भाषा मे नियमित डायरी तैयार करनी पडती थी। किसी प्रकार के दावा या झगडा सम्बन्धी मामले को उचित अधिकारी को इन्हे भेजना भी पडता था। किसी रेवन्यू विभाग के योरोपियन या स्थानीय कर्मचारी के विरुद्ध प्रार्थनापत्र को गवर्नर जनरल-इन काउन्सिल के पास आदेशार्थ भेजना पडता था। ऐसे मामलो मे वह मुकदमे से सम्बन्धित गवाह को अदालत मे बुला सकता था और सम्बन्धित पत्रजात भी माग सकता था। वह गवाह की जाच करके रिपोर्ट विचारार्थ प्रेषित कर देता था। उसे अदालत के न्यायाधीशो या कलेक्टर के पास लिखित पूछताछ के प्रश्नो को भेजना पडता था। मुद्रणालय के अतिरिक्त अन्य शिकायतीपत्रो को वह नही स्वीकार कर सकता था। मुद्दयी का जवाब वकालतनामा के विना स्वीकार नही करता था। सभी आदेश और सम्मन हस्ताक्षर और मुहर से

⁵³ बोर्ड ऑफ रेवन्यू करसपान्डेन्स, जून २७ १७८८ पृष्ठ-१६३-१७०

⁵⁴ वही- मई २३, १७८८ पृष्ठ २१६-२३३

ही भेजे जाते थे। किसी मुकदमे में गवाह की आवश्यकता होने पर वह कलेक्टर को आदेश देने हेतु पत्र लिखता था। गवाह को अदालत में हाजिर होने का खर्च भी देना पड़ता था।

उसे मुद्दयी को अदालत में हाजिर होने हेतु नोटिस निकालनी पड़ती थी और ऐसे नोटिसों को खालसा के मुख्य स्थानों पर भी लगा दिया जाता था। उसे सभी जमींदारी, तालुकेदारी चौधरी की सनद तैयार करके नजीर के रूप में रजिस्टर में दर्ज करना पड़ता था। उसे जमींदारी, चौधरी और अन्य लगान की भूमि की बिक्री भी करनी पड़ती थी। यदि उसे गवर्नर जनरल-इन-काउन्सिल या बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का आदेश बिक्री के लिए मिल जाता था तो उसे वह रोक नहीं सकता था। रिपोर्ट तैयार करने वालों का पद अपने अधीनस्थ कर्मचारियों के ऊपर प्रभावकारी था।

कलेक्टर के कार्य

कलेक्टर का कार्य निर्धारित लगान नियत समय पर वसूल करने तक सीमित था। लगान न निर्धारित किये हुये भूमि का समझौता करना तथा आर्थिक सम्बन्धी अन्य कार्य भी उसे सौंपा गया था।⁵⁵ १७६५ केनियम -५ अनुभाग-७ के अनुसार उनका कार्य नशीले पदार्थों एवं उत्तेजक सामान पर कर लगाना, सरकार को लगान देने वाली भूमि का बटवारा करना, अपाहिज, सैनिकों को भूमि देना, समय-समय पर अपना लेखा-जोखा महालेखाकर के आदेश से बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को निर्धारित प्रपत्र पर भेजना, सरकारी लेनदेन के लिए अंग्रेजी, फारसी या हिन्दुस्तानी भाषा में डायरी

⁵⁵ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स सिम्बर १६, १७६४ पृष्ठ-११६

रखना, सम्बन्धित अन्य कर्मचारियों से अपनी आज्ञा का पालन करवाना था।⁵⁶

पूर्व अनुमति के बिना वह कोई बड़ा कार्य नहीं कर सकता था। सम्पूर्ण लेनदेन कलेक्टर के एक लिखित हस्ताक्षरित वारंट के अन्तर्गत था। बिना किसी लिखित अधिकार पत्र के खजान्ची किसी को रुपया नहीं दे सकता था। खजाची और रेकार्डकीपर के अतिरिक्त अन्य सभी की नियुक्ति और बर्खास्तगी का अधिकार कलेक्टर को प्राप्त था। किन्तु इन सभी कार्यों की सूचना बोर्ड ऑफ रेवन्यू को भेजनी पड़ती थी। कलेक्टर की मृत्यु या अन्य किसी कारण से उनकी अनुपस्थिति में वरिष्ठ सहायक उसके कार्य को देखता था। किसी भी कलेक्टर, सहायक दीवान या भारतीय अधिकारी को भूमि रखने और भूमि लगान चुकाने की आज्ञा नहीं थी। वे नीलाम की भूमि को भी नहीं खरीद सकते थे।⁵⁷

कोई भी कलेक्टर या उसका दीवान प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से व्यापार सम्बन्धी लेनदेन नहीं कर सकता था। कलेक्टर के दीवान को किसी भी भूस्वामी, किसान या रैयत को ऋण देने की मनाही थी। इस नियम के विरुद्ध लिया गया ऋण किसी अदालत से नहीं वसूल किया जा सकता था। रिकार्ड और हिसाब किताब सम्बन्धी रखरखाव के लिए कलेक्टर उत्तरदायी होता था।⁵⁸ उसे लगान वसूली के लिए सिपाही तथा 'तकाबी' बाटने के लिए अग्रिम धनराशि बोर्ड ऑफ रेवन्यू की स्वीकृति पर प्राप्त होता था। खजाने में लगान जमा करने की रसीद पर अपना तथा राजा

⁵⁶ बंगाल रेग्यूलेशन, प्रथम पृष्ठ - २३१

⁵⁷ वही पृष्ठ - २२५

⁵⁸ वही पृष्ठ-२२६

का हस्ताक्षर काराना आवश्यक था। रेकार्ड रखने वालों को एक रजिस्टर में प्रत्येक रसीद की संख्या लिखकर रखना पड़ता था और उनपर हस्ताक्षर करके प्रमाणित भी करना पड़ता था। रजिस्टर की एक प्रति प्रत्येक माह में बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को प्रेषित करना पड़ता था। कलेक्टर द्वारा प्रदत्त वेतन और भत्ते का माहवार रसीद रेकार्ड रूप में जमा होता था जिसे रेकार्डकीपर प्रत्येक वर्ष बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को भेजता था।⁵⁹

तहसीलदार के कार्य

तहसीलदार को राजस्व वसूलने का अधिकार था। भूमि मालिकों से सरकार द्वारा निर्धारित लगान वसूल करना और कुछ सीमा तक कानून और व्यवस्था बनाये रखने के लिए उसे पुलिस का अधिकार प्राप्त था। अपने क्षेत्र में वह सम्पूर्ण लगान के लिए जिम्मेदार था। उनको संग्रह किये गये सम्पूर्ण लगान का साढ़े ग्यारह प्रतिशत वेतन के रूप में दिया जाता था।⁶⁰ इसमें पुलिस शासन का खर्च भी सम्मिलित था। तहसीलदार के अपने क्षेत्र हेतु पुलिस अधिकार को मजिस्ट्रेट बिना गवर्नर जनरल-इन-काउन्सिल की स्वीकृति के बदल नहीं सकता था।⁶¹ यदि मजिस्ट्रेट किसी तहसीलदार को दुराचारी, अयोग्य या किसी प्रकार से दोषी पाता था तो कारण और तथ्य सहित अपनी रिपोर्ट गवर्नर जनरल-इन-काउन्सिल को भेजता था और फिर उसके आदेश और निर्देश के अनुसार कार्य करता था। १७६५ के नियम १७ अनुभाग-७ के

⁵⁹ वही—

⁶⁰ बंगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ ६५६ एव दस्तूर-उल-आलमगीरी पृष्ठ-११२ ए

⁶¹ वही पृष्ठ-२३६

अन्तर्गत यदि कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति को हत्या, चोरी डकैती आदि के लिए दोषी पाता था किन्तु समय से मजिस्ट्रेट को सूचित नहीं कर पाता था तो सम्बन्धित क्षेत्र के तहसीलदार को इस सम्बन्ध में कार्यवाही करने का अधिकार था। दोषी व्यक्ति की गिरफ्तारी की सूचना चौबीस घण्टे के अन्दर मजिस्ट्रेट को देनी पड़ती थी। अभियुक्त के उपस्थित होने पर मजिस्ट्रेट उस पर कार्यवाही प्रारम्भ करता था। चोरी आदि का सामान जिस व्यक्ति के पास निकलता था उसे 'दस्तक' देने का अधिकार था। तहसीलदार को गवाह मुद्दयी आदि को निर्धारित समय पर उपस्थित होने की जमानत लेना पड़ता था। कुख्यात डाकू को गिरफ्तार करके मजिस्ट्रेट के समक्ष उपस्थित करने का उत्तरदायित्व तहसीलदार पर ही होता था। मजिस्ट्रेट उसकी जाच आदि का कार्य करता था।⁶²

१७६५ के नियम-१७ अनुभाग-१३ के अन्तर्गत गोडइत, चौकीदार एवं दसबन आदि कर्मचारी तहसीलदार के अधीन थे जिन्हें स्थानीय पुलिस का अधिकार प्राप्त था। तहसीलदार को प्रत्येक के नाम का एक रजिस्टर रखना पड़ता था।⁶³ मृत्यु या किसी अन्य कारण से इनका पद रिक्त होने पर किसी भूमि मालिक को रिक्त स्थान पर नियुक्त कर दिया जाता था। तहसीलदार को किसी डाकू या चोर को पकड़ने पर १०/- प्रति की दर से पुरस्कार प्राप्त होता था। चोरी का पता लगाने और चोर को पकड़वाने तथा जेल भेजने की प्रक्रिया पूर्ण होने पर चोरी में गये सामान के मूल्य का १० प्रतिशत तहसीलदार को प्राप्त होता था। १७६५ की धारा-१७

⁶² वही—

⁶³ वही पृष्ठ-२३६

अनुभाग-१८ के अन्तर्गत तहसीलदार बाजार, मेला तथा धार्मिक सभाओं के लिए आवश्यक, प्रबन्ध करता था। उसकी सुरक्षा की व्यवस्था करता था।⁶⁴

यदि तहसीलदार के अधीनस्थ कोई भी कर्मचारी भ्रष्टाचार, उत्पीड़न और लूट आदि के लिए दोषी पाया जाता था तो उसके विरुद्ध दीवानी अदालत में तहसीलदार मुकदमा चला सकता था। १८०७ के नियम १४ अनुभाग-२ के अनुसार तहसीलदार पुलिस द्वारा कार्य कराने में सक्षम था। वह पुलिस की आवश्यकतानुसार सहायता ले सकता था। स्थानीय अधिकारियों की मध्यस्थता से कार्य सरलता से सम्भव होता था।⁶⁵ तहसीलदार १००/- प्रतिमाह वेतन प्राप्त करता था जो जमींदार देता था। १८०२ में इनका वेतन १००/- बढ़ाकर १५०/- कर दिया गया।⁶⁶ प्रत्येक परगना में दो कानूनगो होते थे जो तहसीलदार के अधीन कर्मचारी थे कलेक्टर की संस्तुति पर बाद में उनकी संख्या बढ़ाई गई।⁶⁷

कानूनगो

तहसीलदार के अधीनस्थ कर्मचारी कानूनगो का पद लगान सम्बन्धी कार्य के लिए बहुत महत्वपूर्ण था। वह सरकार और किसान के मध्य एक कड़ी का कार्य करता था। २६ अक्टूबर १७८७ में यह पद सरकारी हो गया। उनकी सुरक्षा पर पर्याप्त राशि खर्च होती थी।⁶⁸ इससे पूर्व वे

⁶⁴ वही—

⁶⁵ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स (पत्र प्राप्त — १७६६-१८०८) पृष्ठ ५२-५३ एव बंगाल रेग्यूलेशन प्रथम पृष्ठ ६५२-६५३

⁶⁶ गाजीपुर करसपॉन्डेन्स, अक्टूबर २८, १८०२ जिल्द-१, पृष्ठ-५

⁶⁷ बनारस करसपॉन्डेन्स, मई ६, १८०८, पृष्ठ १२५-१२७,

⁶⁸ बोर्ड ऑफ रेवेन्यू करसपॉन्डेन्स अक्टूबर २६, १७८८ पृष्ठ-१६

आमिलो के आश्रित और सहायक होते थे। रैयत से लगान वसूलने वाला आमिल ही इन्हे पैसे देता था। किन्तु ३ अक्टूबर १७८८ को डकन को सरकार से यह आदेश प्राप्त हुआ कि कानूनगो को सरकारी खजाने से वेतन दिया जाय। इनका पद पैतृक न होकर व्यक्तिगत योग्यता पर आधारित था।⁶⁹ कानूनगो का सम्मान ही एक ऐसा आधार था जिसपर डकन का समझौता कार्य आधारित था।⁷⁰ कानूनगो खेतों और गावों के पट्टे देते थे और रेजीडेन्ट के पास प्रत्येक परगना के समझौते का हिसाब भेजते थे। मुफ़र्रिसल का लगान गाव के पट्टे पर निर्धारित होता था।⁷¹ जुलाई १७६४ में वे कलेक्टर के सस्थान के एक अंग बन गये।⁷² १८०८ के नियम-४ अनुभाग-५ के अनुसार उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित वेतन प्राप्त होता था।

कानूनगो की सहायता करने के लिए दो व्यक्ति दिये जाते थे जिन्हें कलेक्टर चुनकर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के पास नियुक्ति हेतु भेजता था। यह पद पैतृक नहीं होता था। ये सहायक प्रायः कानूनगो के परिवार के अपनी योग्यता, बौद्धिक कुशलता और अच्छे आचरण के कारण चुने जाते थे।⁷³

१८०८ में कानूनगो के कार्यों की व्याख्या इस प्रकार की गई— (१) उन्हें कोई जामा वासिल बाकी की प्रतिलिपिया रखनी पड़ती थी जिनका समझौता समाप्त हो चुका था। तहसीलदार द्वारा सग्रहित लगान की राशि

69 वही अक्टूबर ३, १७८८ पृष्ठ १४-१६

70 वही अप्रैल २६, १७८६ पृष्ठ -१८६-१८७

71 वही-जून १४, १७८६ पृष्ठ-३२४

72 वही - सितम्बर, १६, १७६४ पृष्ठ-१२७

73 बनारस करसर्पॉन्डेन्स मई ६, १८०८ पृष्ठ १२५-१२७

का हिसाब रखना पड़ता था। (२) लगान से पैतृक छूट वाली भूमि, बदली गई भूमि सम्पत्ति का हिसाब एक रजिस्टर में रखना पड़ता था। बिक्री द्वारा भरोहर पट्टा करके उस पर बिना शुल्क लिए अपना हस्ताक्षर करना पड़ता था।

(३) प्रत्येक गाव के पटवारी की एक सूची तथा भूमि मालिकों द्वारा किये गये पट्टों का हिसाब रखना पड़ता था। इसके लिए एक रजिस्टर तैयार करना पड़ता था।

(४) परगना एवं स्थानीय भूमि सम्पत्ति के स्थानीय सीमा की सूचना, प्रत्येक गाव का नाम, संख्या, पैदावार के अन्न, लगान की दर एवं समस्त स्थानीय सूचनाएँ कलेक्टर के न्यायालय को भेजना पड़ता था।

(५) नियमानुसार सूचनाएँ एवं हिसाब तैयार करना पड़ता था। यह नियम बोर्ड आफ रेवेन्यू और **बोर्ड ऑफ कमीशनर्स** द्वारा निर्धारित होते थे।

(६) मालगुजार की मृत्यु और उसके उत्तराधिकारी के बारे में वह सूचना देता था।⁷⁴

नियमानुसार कार्य न करने पर कानूनगो को दण्ड का भागी होना पड़ता था।

⁷⁴ बंगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ ६६२-६६३, बनारस करपॉन्डेन्स मई ६, १८०५, पृष्ठ १२५-१२७

पटवारी

१७६५ के नियम-२७ अनुभाग-६ के अन्तर्गत पटवारी की नियुक्ति होती थी।⁷⁵ वे जमींदार के नौकर समझे जाते थे। भूमि सम्बन्धी सूचना देने का कार्य पटवारी करता था। बिक्री का आदेश कलेक्टर द्वारा होने पर वह सम्बन्धित पत्रजात कानूनगो को भेजता था। विभिन्न पत्रजातो का मिलान करता था और यदि इस मिलान की कोई त्रुटि परगनाधिकारी को पता चलती थी तो पटवारी दण्डित भी किया जाता था।

सभी भूमि मालिक और किसान अपनी रैयत का हिसाब किताब रखने के लिए पटवारी रखते थे। पटवारियों की एक सूची होती थी जो कलेक्टर की माग पर प्रस्तुत करना पड़ता था। पटवारियों को भूमि पैदावार के समस्त पत्रजात रखने पड़ते थे जिनकी माग होने पर सम्बन्धित गाव के नाम आदि के विवरण के साथ न्यायालय में देना होता था। यदि विवरण में किसी प्रकार का परिवर्तन, त्रुटि या जालसाजी का संकेत मिलता था तो पटवारी पर मुकदमा भी चलता था। उन्हें अपना हिसाब निरीक्षणार्थ कलेक्टर के पास भेजना पड़ता था।⁷⁶

⁷⁵ वीर पृष्ठ-४१५

⁷⁶ बंगाल रेग्यूलेशन, प्रथम, पृष्ठ-२५६-२६१

उपसंहार

उपसंहार

भारत के पूर्वी उत्तर प्रदेश की वैभवशाली सस्कृति जग प्रसिद्ध है। पूर्वी उत्तर प्रदेश के जनपद अपने प्राचीन गौरव और गरिमा के लिए अपना विशिष्ट स्थान रखते हैं। इसी प्रदेश का अंग बनारस अस्सी और वरुणा नदियों के निकट गंगा के किनारे स्थित ऐतिहासिक वैभव से युक्त आज भी अपनी समृद्धशाली सस्कृति का प्रतीक है। बनारस नगर के निकट जौनपुर, मिर्जापुर और गाजीपुर जिले अठारहवीं शताब्दी में बनारस मण्डल के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं। इन सभी नगरों की अपनी विशिष्ट सभ्यता और सस्कृति रही है।

अनेक विदेशी आक्रमणकारियों ने बनारस मण्डल के वैभव को नष्ट करने का प्रयास किया। यही नहीं बादशाह औरंगजेब ने तो यहाँ के मदिरों, धार्मिक स्थलों को ध्वस्त करने के बाद इस पवित्र नगर का नाम ही बदल डाला। किन्तु ~~उसने~~ ^{उन्होंने} द्वारा दिया गया नाम 'मुसलमानों का शहर' मात्र उसके उत्तराधिकारियों द्वारा चलाये गये सिक्कों तक ही सिमित रह गया।

मुगल शासन के पतन के बाद १७१६ में फर्रुखसियर की हत्या कर दी गई जिससे बनारस का उत्तरदायित्व क्रमशः मुहम्मद शाह, मुर्तजा खॉं, सहादत खॉं, और रुस्तमअली के हाथों से गुजरता हुआ बनारस के भूमिहार ब्राह्मण मनसाराम तक पहुँचा। मनसाराम को बनारस के सत्तारूढ परिवार का संस्थापक कहा जा सकता है। उसकी मृत्यु के बाद

उसका पुत्र बलवत सिंह दिल्ली के सम्राट से राजा की उपाधि प्राप्त कर राजसिंहासन पर बैठा। बलवत सिंह के बाद उसकी पुत्री के पुत्र महीपनारायण और अवैध पुत्र चेतसिंह ने गद्दी को लेकर विवाद उठ खड़ा हुआ। महीपनारायण अवयस्क था। चेतसिंह ने रिश्वत आदि देकर साठे बाईस लाख वार्षिक राजस्व पर बनारस का राजसिंहासन प्राप्त कर लिया। यह सब वारेन हैस्टिंग्स और अवध के नवाब शुजाउद्दौला की आपसी बात चीत से निश्चित किया गया। किन्तु नवाब की मृत्यु के बाद उसके पुत्र आसफउद्दौला ने बनारस प्रान्त अंग्रेजों को दे दिया जिसे बड़ी ही कठिनाई से अंग्रेज रेजीडेंट के आधीन रह कर चेतसिंह ने पुन प्राप्त किया।

राजा चेतसिंह द्वारा गर्वनर जनरल के आन्तरिक झगड़े में फ्रांसिस का साथ देने के कारण हैस्टिंग्स उससे अत्यधिक क्रुद्ध हुआ। इस कारण चेतसिंह अपनी निष्ठा और सेवा भाव के होते हुए भी हैस्टिंग्स की सद्भावना नहीं प्राप्त कर सका। हैस्टिंग्स उसे परेशान और अपमानित करने के लिए दृढ़ प्रतिज्ञ था।

चेतसिंह सरल व्यक्तित्व का स्वतन्त्रताप्रिय व्यक्ति था। किन्तु उसने अपनी स्वामी भक्ति प्रदर्शित करने में कमी नहीं किया। वह राजस्व की रकम निरन्तर जमा करता रहा। हैस्टिंग्स द्वारा नित्य नई माग और राजस्व की दिन प्रतिदिन बढ़ती रकम चेतसिंह के लिए कठिनाई का कारण बनती गई। एक समय ऐसा भी आया जब उसने हैस्टिंग्स की माग पूरा करने में असमर्थता जतायी। वास्तव में हैस्टिंग्स चाहता भी यही था।

हैस्टिंग्स द्वारा २००० घुडसवारों की माग को चेतसिंह द्वारा न पूर्ण कर पाना बहुत बड़ा अपराध निर्धारित किया गया। इसके लिए दण्ड देने हैस्टिंग्स स्वयं बनारस पहुँचा। चेतसिंह बन्दी बना लिया गया किन्तु उसकी सेना ने बड़ी बहादुरी और उत्साह से अंग्रेजी सेना को पराजित किया। चेतसिंह भाग निकला किन्तु सेना के इस विद्रोह का अंग्रेजों ने शीघ्र ही दमन कर दिया। चेतसिंह को महादजी सिन्धिया की शरण लेनी पड़ी। हैस्टिंग्स का चेतसिंह के प्रति जो व्यवहार था उससे यह स्पष्ट होता है कि वह उसके स्वतंत्रता प्रिय होने का प्रबल विरोधी था। उसे अपमानित करने के लिए और उसकी शक्ति क्षीण करने के लिए सबसे अच्छा तरीका यही था कि उससे तब तक धन की माग की जाय जब तक कि वह उसका विरोध न करे। हैस्टिंग्स की योजना सफल हुई।

यद्यपि हैस्टिंग्स इस तथ्य से भी परिचित था कि बाह्य सुरक्षा और समय पर सहायत के लिए बनारस राज्य का विशेष महत्व है। इसी कारण वह बनारस के राजा और कम्पनी के बीच स्थिर मैत्री सम्बन्ध का पक्षपाती था। किन्तु वह इतना अधिक स्वार्थी और चंचल मनोवृत्ति का व्यक्ति था कि अपनी बात पर अधिक समय तक टिक नहीं पाता था। चेतसिंह के प्रति वह बदले के भाव से ग्रसित था।

बनारस में कानून व्यवस्था में कमी, मराठों से गुप्त वार्ता, बढ़ते अपराध, सैनिक विद्रोह आदि कुछ ऐसे कारण थे जिनके लिए हैस्टिंग्स का यह विचार था कि चेतसिंह की इच्छा से यह सब होता रहा है। उसकी निष्ठा सदिग्ध बतायी गयी जब कि समस्त तथ्यों का अवलोकन करने से यह प्रकट होता है कि प्रारम्भ में चेतसिंह हैस्टिंग्स के प्रति निष्ठावान और

सहृदय था किन्तु वारेन हैस्टिंग्स के कपटपूर्ण और द्वेषपूर्ण व्यवहार के कारण वह विद्रोही बन गया।

असीमित धनराशि की माग न पूर्ण करना चेतसिंह की स्वेच्छा से अधिक इस कारण भी हुआ क्योंकि राजकीय कोष धीरे-धीरे खाली होता जा रहा था। राजा आर्थिक सकट में था। हैस्टिंग्स सन्धि द्वारा निर्धारित रकम प्राप्त करने पर भी सन्तुष्ट नहीं था। यह उसकी कटुता और चेतसिंह को अपमानित करने की स्पष्ट साजिश थी। इन सबसे अलग जो सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारण था, वह था भारत में एक छत्र राज्य की स्थापना जिसके लिए अंग्रेज शासक कुछ भी कर सकने के लिए सदैव तत्पर रहते थे। इस सन्दर्भ की इस तथ्य से पुष्टि होती है कि चेतसिंह के बाद महीपनारायण को उत्तराधिकार तो सौंपा गया किन्तु न्याय प्रशासन और राजस्व का अधिकार १७६४ में अंग्रेजों ने अपने हाथ में ले लिया। १७६५ में बनारस का राज्य प्रशासन बंगाल की भांति हो गया। इस प्रकार क्रमशः ब्रिटिश शासन द्वारा बनारस के निकट के जनपद भी ले लेने का प्रयास होने लगा। १८०० में सर्वप्रथम जौनपुर, तत्पश्चात् गाजीपुर और फिर मिर्जापुर भी सम्मिलित हो गया। बनारस मंडल में और प्रत्येक जनपद में प्रशासनिक व्यवस्था कर ली गई।

मध्यकालीन समाज में व्याप्त जटिल परिस्थितियाँ, आर्थिक अस्थिरता तथा औरंगजेब की अनुदार नीतियाँ भारत में मुगलशासन के पतन का कारण थीं। जिन उद्योग धन्धों और व्यवसायों को मुगलकाल में उन्नति के शिखर पर पहुँचाया गया था उन्हें ही ईस्ट इंडिया कम्पनी ने अपने व्यापार का माध्यम बनाया। प्रचलित पूर्वी उत्तर प्रदेश में उद्योग धन्धे जैसे नील,

अफीम, शोरा, नमक, रेह का उत्पादन तथा धातु निर्मित वस्तुओं एवं सूती रेशमी वस्त्रों का निर्माण कार्य उन्नति की दशा में था।

नील की खेती भारत में प्रचीन काल से ही होती रही। पूर्वी उत्तर प्रदेश में गाजीपुर क्षेत्र में नील का वृहद पैमाने पर उत्पादन और व्यापार होता था। इससे होने वाले लाभ का आकर्षण इतना अधिक था कि कम्पनी के कर्मचारी जैसे गिल्डिस्ट और चार्टर्स ने स्वयं नील की खेती करना प्रारम्भ कर दिया। इस हस्तक्षेप से स्थानीय उत्पादकों और अंग्रेज कर्मचारियों के मध्य तनाव की स्थिति भी व्याप्त हुई जिसका निराकरण डकन द्वारा करने का प्रयास किया गया। सभी पहलुओं का अध्ययन करने से यह प्रकट होता है कि यद्यपि नील का उत्पादन साधारण जनता के हितार्थ नहीं था किन्तु इंग्लैण्ड के लिए निश्चित रूप से यह आर्थिक लाभ का एक स्रोत था।

अफीम उद्योग पर बनारस मण्डल का आधिपत्य था। १८वीं शताब्दी के मध्य अफीम उद्योग को लेकर भारतीय और योरोपीय कारखानों में प्रतिस्पर्धा की भावना व्याप्त हो गई जिससे इसका मूल्य १००/- रु० से १५०/-रु० प्रति पेट्टी हो गया। १७७३ में हैस्टिंग्स ने इस उद्योग पर पूर्णतः सरकारी आधिपत्य स्थापित कर दिया। अंग्रेजी सरकार अफीम का अधिक से अधिक लाभ स्वयं लेना चाहती थी। उसकी नीतियाँ में बराबर परिवर्तन होता रहा। कभी ठेके द्वारा तो कभी प्रतिनिधि द्वारा अफीम का उद्योग कराया जाता रहा। इसकी वृद्धि के लिए तथा तस्करी रोकने के लिए अनेक नियम बनाये गये किन्तु व्यापार में गिरावट आ गयी। बाद में एजेन्सी नीति लागू की गई। अफीम की गुणवत्ता में सुधार किया गया और

अनियमितता बरतने पर कठोर दण्ड का प्राविधान किया गया। अफीम के उत्पादन को सीमित करने के लिए प्रतिवर्ष १५०० मन की सीमा निर्धारित की गई।

१८वीं शताब्दी में पूर्वी उत्तर प्रदेश के मुगरा, गरवारा, रारी, सिगरामऊ जफराबाद और गोपालपुर में तथा जौनपुर और बनारस में नमक बनाने का कार्य होता था। सरकार की नीति के अनुसार जौनपुर में साल्ट महल बनाया गया और नमक जैसे छोटे उद्योग पर टैक्स लगाया गया। इससे व्यापार पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस मण्डल के चवसा केवली ग्राम तथा गाजीपुर जिले के खेतीपुर ग्राम में शोरा का उत्पादन होता था जिसका मुख्य प्रयोग बारूद बनाने में किया जाता था। १८वीं शताब्दी में योरोप के युद्धों में इसकी मांग बढ़ जाने से इसका आयात बनारस से भी होने लगा।

सम्पूर्ण बनारस नगर कारखानों से सुसज्जित रेशम वस्त्र उद्योग का समृद्ध केन्द्र था। मूल्यवान रेशमी वस्त्र, उच्च कोटि के सूती वस्त्र, सोने चाँदी के हौदे, पालकी, कुर्सी, आभूषण, सोना-चाँदी के तार आदि का निर्माण और व्यापार उन्नतिशील दशा में थे। आय के इस वृहद स्रोत का अधिक से अधिक लाभ उठाने के लिए ब्रिटिश सरकार स्थानीय राजस्व से प्राप्त धन से सम्पूर्ण माल क्रय कर लेती थी। और स्वयं उसका व्यापार करती थी। भारतीय उद्योग धन्धों के शोषण का यह एक अंग्रेजी नीति या तरीका बन गया था।

पीतल व धातु से निर्मित वस्तुएँ, केवडा जल, इत्र, गुलाब जल, सुगन्धित तेल का उत्पादन क्रमशः बनारस, गाजीपुर, और जौनपुर में होता था। खोजवा लकड़ी के बने खिलौनों का प्रमुख केन्द्र था। वहाँ खिलौने का निर्माण एवं व्यापार होता था। इसके अतिरिक्त ईंट उत्पादन तथा पान और तत्सम्बन्धी सामग्री का व्यापार भी उच्च कोटि के रूप में जाना जाता था।

१८वीं शताब्दी का पूर्वी उत्तर प्रदेश आर्थिक दृष्टि से समृद्ध और आत्मनिर्भर था किन्तु ब्रिटिश नीति के अन्तर्गत दिन प्रतिदिन स्थिति गिरती गई। व्यापार और उद्योग का भरपूर शोषण हुआ। इंग्लैण्ड की औद्योगिक क्रान्ति के कारण यहाँ का सम्पूर्ण कच्चा माल जबरन कम से कम मूल्य में क्रय करके इंग्लैण्ड भेज दिया जाता था। धीरे-धीरे उद्योगधन्धे बन्द होने लगे। मशीनरीकरण और औद्योगिक क्रान्ति के कारण भारतीय परिवेश के साथ ही साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश में भी परिवर्तन आया। जिनके पास पूँजी थी उन्होंने अपनी पूँजी उद्योग स्थापित करने में लगायी। कारखानों में मजदूरों के श्रम की आवश्यकता बढ़ी। समाज में एक धनी वर्ग जिसमें बड़े व्यापारी उद्योग पति थे तथा दूसरा श्रमिक वर्ग जिसमें गरीब मजदूर था स्थापित हुआ। इसके अतिरिक्त एक तीसरे वर्ग जिन्हें मध्यम वर्ग कहा जाता था का जन्म हुआ। गरीब और अमीर के बीच का अन्तर बढ़ता गया। मध्यम वर्ग मात्र शोषण का शिकार था। किन्तु धनी जमींदार, उद्योग पति और साहूकार अंग्रेजी के प्रति निष्ठवान बने रहे। अंग्रेजी आर्थिक शोषण के फलस्वरूप भारत के विभिन्न भागों की तरह पूर्वी उत्तर प्रदेश भी आर्थिक विपन्नता का शिकार बनता गया।

पूर्वी उत्तर प्रदेश के कर एव चुगी व्यवस्था पर विस्तृत अध्ययन करने के उपरान्त यह स्पष्ट होता है कि अदूरदर्शिता और असमानता पर आधारित व्यवस्था अनेक परिवर्तन और प्रयोग के बावजूद भी दोषपूर्ण ही बनी रही। इसका मुख्य कारण भेद भाव और व्यक्तिगत स्वार्थ था। मुगल काल से चली आ रही दोषपूर्ण व्यवस्था ब्रिटिश शासन काल में अव्यवस्थित और जर्जर हो गयी। ब्रिटिश सरकार ने पूर्वी उत्तरप्रदेश के विभिन्न स्थानों पर गंज की स्थापना करके सौदागरों को व्यापारिक और सुरक्षात्मक सुविधा देने का दावा किया। किन्तु उन पर इतना अधिक प्रशासनिक नियंत्रण लागू कर दिया कि प्रदत्त सुविधायें व्यर्थ सिद्ध हुईं। चूने के व्यापारको स्वतंत्र घोषित कर व्यापारिक प्रतिस्पर्धा उत्पन्न करना और पुनः प्रतिबन्धित कर देना आर्थिक शोषण का उदाहरण है। रेह को हानिकारक बताकर बन्द कर दिया गया।

लकड़ी, पत्थर, काँच और सोने के लिए पहले महल बनाये गये और उन पर तरह-तरह के कर आरोपित किये गये। इन पर पूर्वी उत्तर प्रदेश का एकाधिकार था किन्तु डकन की सिफारिश पर सभी एकाधिकार समाप्त कर दिये गये। पूर्वी उत्तर प्रदेश के लिए १८वीं शताब्दी में यह एक बहुत बड़ी क्षति थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस मंडल विश्व प्रसिद्ध व्यापारिक केन्द्र रहा है। इसी से जुड़ा हुआ मिर्जापुर अवध, तिब्बत, नेपाल, बंगाल, से अपना व्यापारिक सम्बन्ध बनाये हुये था। स्वाभाविक रूप से यहाँ चुगी का प्रबन्ध होना आवश्यक था। ब्रिटिश शासन ने इस प्रबन्ध को माल की गुणवत्ता पर ध्यान दिये बिना जारी रखा। चुगी का निर्धारण और उसकी

वसूली न तो वैध थी औन न विश्वसनीय। सौगन्ध, अनुमान और प्रचलित मूल्य के आधार पर चुगी लगाना ब्रिटिश शासन की व्यवस्था पर एक प्रश्न चिन्ह है। १७७३ में वारेनहेस्टिंग्स ने यद्यपि कुछ वस्तुओं को कर मुक्त कर दिया किन्तु १७८१ के बाद व्यापारी इस छोटे लाभ से भी वंचित रह गये। प्रदेश के प्रत्येक भाग में चुगी घर खुल जाने से व्यापारी असन्तुष्ट एवं परेशान थे। सरकार ने समय समय पर अनेक नियम और कानून बनाये किन्तु इनके पालन में जिस तरह से अनियमितता और शोषण की नीति अन्तर्निहित थी उससे व्यापार में भारी गिरावट आयी। माल के माप का कोई वैज्ञानिक आधार न होना भी दुर्भाग्यपूर्ण था। तौलने की फीस, दुकान टैक्स, चूरा चौकियों द्वारा हर छोटी बड़ी वस्तुओं पर टैक्स देना व्यापारियों के लिए असुविधा का कारण था। यद्यपि देश के आन्तरिक भाग में कर की दर कम थी किन्तु माल के इच्छित स्थान तक पहुँचाने में जो राजस्व भार पड़ता था वह असहनीय था। व्यापारियों में सरकार का ध्यान आकृष्ट करने एवं निवेदन करने की चेष्टा की किन्तु इसके बावजूद भी ब्रिटिश शासन ने किसी प्रकार का सुधार नहीं किया। यदि कुछ तथाकथित सुधार हुए भी तो वे ठोस नहीं थे। परिणाम यह हुआ कि माल महंगा होता गया और विक्रय घटता गया। व्यापारियों ने तंग आकर व्यापार बन्द कर दिया। निश्चय ही यह ब्रिटिश शासन की एक ऐसी साजिश थी जो भारत वर्ष के साथ-साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को नष्ट करने में सहायक थी।

पूर्वी उत्तर प्रदेश का बनारस प्रान्त एक क्षेत्रीय प्रशासनिक मुख्यालय था जहाँ इस क्षेत्र के बैक, व्यापार, वाणिज्य, मुद्रा, नियंत्रित किये जाते थे।

वैश्य, अग्रवाल, खत्री, गोसाई, आदि बनारस के बैकरो मे अपना विशिष्ट स्थान एव आधिपत्य रखते थे। किन्तु इन सुविधाओ से पूजीपति एव उद्योगपति ही लाभान्वित होते थे। किसी अन्य समुदाय के लाभान्वित होने के कोई दृष्टान्त नही आये है।

राजस्व का सृजन देश की वास्तविक स्थिति को ध्यान मे रख कर ही होना चाहिए। यह सत्य है कि 'कर' राजस्व की आय का प्रमुख स्रोत है किन्तु इसका सुनियोजित, विवेकपूर्ण, जन हितार्थ एव स्थिर आर्थिक प्रणाली के अनुरूप होना भी सर्वप्रमुख है। इन मौलिक नियमो के विपरीत स्वार्थ पर आधारित राजस्व व्यवस्था किसी भी प्रशासन को तुरन्त लाभ तो दे सकती है किन्तु उसका दूरगामी परिणाम निश्चित रूप से विरोधात्मक होगा। जब कोई विरोध मुखर होता है तब उसका परिणाम सत्ता को परिवर्तित कर देने तक हो सकता है जैसा कि भारत के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश मे भी हुआ।

जहाँतक भू-राजस्व व्यवस्था मे श्रेय का प्रश्न हैतो वह अकबर को है जिसके प्रयासों के फलस्वरूप मुगलकालीन भू-राजस्व व्यवस्था सगठित एवं सुव्यवस्थित हुई। इसी स्थापित नियम मे कुछ सामान्य एव आवश्यक परिवर्तन करने के उपरान्त प्रचलित रूप मे सब ने इसे स्वीकार किया किन्तु वास्तविकता यह थी कि उपयोगी, सगठित, प्रशसनीय होने के बाद भी मुगल काल की इस व्यवस्था मे कई दोष थे। प्रचलन यह था कि भूमि के विभाजन तथा उपज की तालिका के अनुसार अर्थात् दोनों का औसत निकाल कर मालगुजारी वसूल की जाती थी। वे किसान जिनके पास प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, तृतीय श्रेणी में से किसी एक प्रकार की ही

जमीन थी। किन्तु राजस्व निर्धारण एव वसूली का क्रम सब के साथ एक ही था। इसके अलावा लगान उपज के $\frac{1}{2}$ से अधिक था। गैर स्वीकृत कर वसूल होते थे। शिकायत और दंडित होने के उपरान्त भी देश की विशालता और यातायात के साधन के अभाव में दूरवर्ती प्रदेशों में इन नियमों का कठोरता से पालन नहीं हो पाता था। पटवारी, चौधरी, मुकद्दम, सभी किसानों को त्रस्त करते और अधिक से अधिक वसूलते थे किन्तु उतना जमा न करते अर्थात् लगान की चोरी कर्मचारियों के स्तर से थी। किन्तु समस्त व्यवस्था पर नियंत्रण रखना कभी सम्भव नहीं हो पाया अतः मुगल काल में भी इसकी उम्मीद करना अस्वाभाविक था।

टोडरमल की रैयतवारी व्यवस्था मुगल शासन के सभी शासकों ने यथावत चलाया किन्तु औरंगजेब के शासन काल के आते आते यह व्यवस्था बिगड़ने लगी। इसका मुख्य कारण सम्बन्धित अधिकारियों में व्यवस्था सम्बन्धी ज्ञान का अभाव था। अब राजस्व वसूलने के लिए ठेकेदार नियुक्त हुए जिन्हें जमींदार कहा गया। १८वीं शताब्दी में दीवानी का अधिकार ब्रिटिश को प्राप्त होते ही पूरा देश बड़े-बड़े राज्यों में विभक्त हो गया। इन राज्यों पर जमींदारों का आधिपत्य स्थापित हो गया और कहीं-कहीं इनकी स्थिति राजा की भांति थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश में जमींदारों की तीन श्रेणियाँ थी (स्वायत्त, मध्यस्थ, प्राथमिक) थी। ये सभी ब्रिटिश शासन के प्रति निष्ठावान होते थे। जमींदार राज्य की आय का बड़ा माध्यम था और वह विदेशी आर्थिक शोषण की प्रक्रिया में सोझेदारी भी कर रहा था। यद्यपि किसानों से इनके सम्बन्ध घनिष्ठ होते थे किन्तु राजस्व वसूली में वे क्रूर भी हो जाया करते थे। सरकारी आदेशानुसार

राजस्व की दर साढ़े नौ प्रतिशत से बढ़ा कर १६ प्रतिशत कर दिये जाने से जमींदार पर दबाव बढ़ गया। सरकारी कर्मचारी राजस्व वसूली में जमींदारों के साथ जिस प्रकार कठोरता का व्यवहार कर रहे थे उसी के फलस्वरूप तरह-तरह की विसंगतियाँ सामने आयीं। मेहदी अली ख़ाँ द्वारा आत्म हत्या का प्रयास इस संदर्भ में महत्वपूर्ण उदाहरण है। यद्यपि डकन ने राजस्व व्यवस्था ठीक करने के लिए अनेक उपाय किये किन्तु उसके परिणाम ब्रिटिश सत्ता के लिए उचित नहीं थे। निश्चित राजस्व की धनराशि न मिल पाने के कारण राज्य में कर्मचारियों की संख्या कम कर दी गई। विभिन्न भत्तों में कटौती करना तरह-तरह के टैक्स लगा देना आमदनी बढ़ाने का माध्यम तो था किन्तु इन सब के बदले ब्रिटिश सरकार जनता का अपने प्रति विश्वास नहीं खोना चाहती थी। इन्हीं सब पहलुओं पर विचारोपरान्त बोर्ड ने देश की सुख सुविधा के परिपेक्ष्य में स्थायी समझौते पर बल दिया। १७६५ में डकन ने स्थायी समझौते के प्रश्न पर विचार करने के लिए बनारस के कमच्छा नामक मुहल्ले में राजा और उनके सहयोगियों की एक मीटिंग बुलाई। राजा पहले तो इस समझौते को मानने के पक्ष में नहीं था। किन्तु अन्ततोगत्वा उसे मानना पड़ा। पूर्वी उत्तर प्रदेश में बनारस मंडल के उन जिलों के साथ दस वर्षीय समझौता किया गया जहाँ पाँच वर्षीय पट्टे नहीं थे। ईमानदारी पर बल दिया गया, प्रचलित प्रमाणिक बीघा प्रणाली लागू की गई और न्यायालय के माध्यम से विवादों को निपटाने का प्रयास किया गया।

राजस्व वसूली के लिए १९८७ फसली के नियम को मान्य किया गया। यात्रियों की सुरक्षा का दायित्व जमींदारों को सौंपा गया। डकन ने

उचित लगान निर्धारण हेतु ग्रामीण एव परगना स्तर पर सूची तैयार करायी जिसमे गाव का नाम, जमींदार का नाम, नदियो की सख्या, उद्योग धधे के ब्यौरे आदि तैयार कराये। उपरोक्त व्यवस्था पूर्ण होने पर चार वर्षीय पट्टे देने के आदेश हुये। अन्य मागो को प्रतिबधित किया गया। बनारस के पूरे प्रान्त मे ऐसा ही समझौता हुआ। १७८६-६० मे बकाया राशि जो ८५०००/- रु० थी वसूल हुई। डकन ने समय समाप्त होने वाले पट्टो को छोड दिया, अवैधानिक मागो को रोका, कर्मचारियो के लिए दड विधान की व्यवस्था बनायी, प्रमाणिक तलबा चिट्ठी वितरित कराया। सग्रह की हुई अतिरिक्त धन राशि का प्रयोग हिन्दू कालेज के विकास पुल, सडक आदि मे लगाई। बोर्ड भूमि मालिक एव लगान मे एकरूपता का पक्षधर था। पट्टेदारो को मैनेजर रखने के निर्देश दिये गये। अधिकार सम्पन्न लोगो के साथ समझौते करने का निश्चय किया गया। बोर्ड ने कलेक्टरो को न्यायिक कार्य से मुक्त रखा एव स्थानीय आमिलो को कलेक्टर की संज्ञा देकर दीवानी के अधिकार दिये। कानूनगो को रजिस्ट्रार का पद दिया एव हिसाब किताब का कार्य पटवारियो के दायित्व मे सौपा गया। डकन कुछ मामलो मे बोर्ड के विचारो से सहमत नही था जैसे राजा का हित, कलेक्टरों के अधिकार, आदि। बोर्ड ने १७६५ मे नियम को स्थायित्व प्रदान किया। १९८७ फसली के अनुरूप राजस्व निर्धारित किया गया। बनारस का समझौता बगाल से भिन्न था। यद्यपि सुधार मे उदार दृष्टिकोण अपनाये गये थे, किन्तु फिर भी कमी रह ही गयी थी। क्योकि नम्बरदार, जमिंदार, योग्य अनुभवर्त्ती नही थे। डकन ने अनेक बार पैमाइश करायी किन्तु हर प्रयत्न अव्यवहारिक सिद्ध हुआ। १७६९ के डकन के रेकार्ड से स्पष्ट होता है कि उपरोक्त कठिनाइयो के कारण विवाद उत्पन्न

होता है एव अदायगी में बाधा आती है। अव्यवस्थाओं के मध्य १७६० से १७६४ के सभी पट्टों को स्वीकार किया गया। स्थायी समझौता अनेक प्रयासों के उपरान्त भी सफल नहीं हो पा रहा था। यद्यपि जमींदार वर्ग ब्रिटिश शासन का सहयोगी था किन्तु लार्ड कार्नवालिस की स्वार्थी नीति समझौते के दोषों को उजागर कर दे रहा था। कर्मचारियों की संख्या घटाई गई, सम्बद्ध अपराधी पाये गये लोगों को दंडित किया गया तथा दस वर्षीय समझौता लागू किया गया। बकाया लगान नीलामी द्वारा वसूल किया जाता था। प्रत्येक जिले की पृथक् प्रशासनिक सत्ता स्थापित की गई। समझौते का प्रबन्ध नियंत्रित करने के दृष्टिकोण से बोर्ड ने कलेक्टरों के ऊपर एक प्रेसीडेन्ट एव चार सदस्य नियुक्त किये। यह अदालत के मामले को पुनः सुनती थी तथा एक कोर्ट आफ वार्ड्स की स्थापना की गई। दोनों के अधिकार विभाजित किये गये। बोर्ड अपने अधीनस्थ अधिकारियों पर नियंत्रण रखता था। कलेक्टरों के माग, आय, बकाया, का प्रति वर्ष १८ जुलाई तक ब्यौरा भेजना पड़ता था। सम्पूर्ण आय, माग, बकाया, रजिस्टर पर लिपिबद्ध किया जाता था। अंग्रेजी और फारसी भाषा में नियमित डायरी भरी जाती थी। जमींदार, ताल्लुकेदार, पर प्रतिबन्ध लगाया गया कि वह भू-स्वामियों से उपहार नहीं ले सकते थे। न्यायालय के कार्य को एकरूपता के सूत्र में बाधने के लिए लिखित बयान, मौखिक बयान, गवाहों को स्वयं उपस्थित कराने के प्राविधान बनाये गये। कलेक्टर को निर्देश था कि वह अपने कार्य का संचालन १७६५ के नियम—५ अनुभाग—७ के अनुसार ही करे। इसी प्रकार तहसीलदार, कानूनगो, पटवारी आदि को भी निर्देश दिये गये कि अपने अधिकार और सीमा के अन्तर्गत ही अपने कार्य का संचालन करे।

परवर्ती मुगल काल से ही पूर्वी उत्तर प्रदेश के बनारस प्रान्तके राजस्व सकलन का दायित्व जमीदारो को प्राप्त हो गया था। म्युटनी बस्ता मे उपलब्ध उद्धरण से स्पष्ट हैकि अधिकाश जमीदार राजपूत, ब्राह्मण, मुसलमान तथा अन्य जाति के थे। इसके अतिरिक्त बहुत से कुर्मी एव अभिजात्य कुल के जमीदार थे जिन्हे परम्परागत रूप से राजा की उपाधि मिली थी, उदाहरण स्वरूप—राजा शिव गुलाम दूबे (जौनपुर) राजा इरादत जहान (मुबारकपुर) राज बेनी माधव सिंह (कन्तिथ) राजा बेनी बहादुर सिंह (अठरौली)। इन्हे राजस्व सकलनके व्यापक अधिकार थे तथा इनकी प्रतिष्ठा उच्च थी। क्रमशः इनके अधिकार समाप्त हो रहे थे। पूर्वी उत्तर प्रदेश से सम्बद्ध बनारस प्रान्त का राजस्व बन्दोबस्त अनेकानेक गभीर दोषो से युक्त था जिसके परिणाम स्वरूप जमीदारियो मे पारस्परिक वैमनस्य एव सरकार को दी जाने वाली बकाया राशि की मात्रा बढ़ती ही गई। बनारस प्रान्त की अधिकाश जमिदारियो मे अनेक व्यक्तियो का हिस्सा था और बन्दोबस्त के समय (इनके) दो या दो अधिक तीन प्रतिनिधि स्वेच्छा से चुन लिये गये एव उनके साथ राजस्व देय का निर्धारण कर पट्टे प्रदान किये गये। इन व्यक्तियो, जिनके प्रतिनिधि के रूप मे यह चुने गये थे। की इच्छाओ पर ध्यान न देते हुए तथा स्वेच्छाचारी चुनाव व्यवस्था द्वारा नियुक्त यह पट्टेदार ही जमिदारियो के प्रबध के निमित्त स्वामियो के रूप मे पजीकृत किये गये। इसमे कोई हानि तो नही थी किन्तु जहाँ प्रबध दोषपूर्ण था वहाँ बकाया राजस्व प्राप्ति के लिए किये गये नीलाम विक्रयो से सम्पत्ति के उन हिस्सेदारो जिनकी प्रबंध में कोई भूमिका नही थी, के अधिकार 'निर्दयतापूर्वक' समाप्त कर दिये गये। इस प्रबध से अधिकाश जमीदारो मे असन्तोष की भावना उत्पन्न हुई क्योकि अपनी ही जमीदारियो मे वे स्वयं

को शक्ति हीन समझने लगे। कालान्तर में मालगुजारी की किश्तों की यथा समय अदायगी न होने की परिस्थिति में जमींदारियों की भूमि के नीलाम की व्यवस्था ने इस असन्तोष को और तीव्र रूप प्रदान किया। दीर्घकाल से चले आ रहे जमींदार परिवार इस प्रबन्ध के अन्तर्गत अपनी पैतृक जमींदारियों के एक बड़े भाग से वंचित हुये तथा कुछ जमींदार तो पूर्णतः अपनी जमींदारियों से हाथ धो बैठे। इस प्रकार जमींदारों के अधिकार एवं उनकी सम्पदा अधिकांश सीमा तक नष्ट हो गई। जमींदारियों के दो वर्ग हो गये एक वर्ग था भूमि एवं सम्पत्ति से वंचित जमींदार एवं दूसरा वर्ग था (नीलाम के माध्यम से प्राप्त जमीन का स्वामी या जमींदार)। दोनों ही एक दूसरे के परस्पर बैरी थे। इस प्रकार न केवल नवनिर्मित जमींदार वर्ग पुरातन जमींदार के बैरी थे अपितु पुरातन जमींदार ब्रिटिश सत्ता के कठोर विरोधी थे। किन्तु जनता का एक बड़ा वर्ग इन पुरातन जमींदार से भावनात्मक रूप से जुड़ा था क्योंकि उन्हीं के साथ लम्बे समय से कार्य कर रहा था। नवनिर्मित जमींदार वर्ग के साथ न तो किसान वर्ग और जनता का स्नेह जुड़ सका। इस प्रकार उत्पन्न होने वाले प्रतिद्वन्द्विता ने न केवल परस्पर विरोधी समुदाय को ही जन्म दिया अपितु इससे भू राजस्व व्यवस्था भी अधिकांश रूप में प्रभावित हुई।

परिशिष्ट

ऐपेन्डिक्स-बी० (अ)

पूर्वी उत्तर प्रदेश के महत्वपूर्ण व्यापारिक केन्द्र

अठ्ठारवीं शताब्दी में

व्यापारिक केन्द्र	आयात	निर्यात	टिप्पणी
(१) बनारस	मुख्य रूप से तेल उत्पादित करने वाले बीज, चीनी	सूती कपड़े, नमक एवं अन्य सामग्री	मुहम्मदाबाद के नाम से विख्यात था १८वीं शताब्दी में
(२) राम नगर बनारस जनपद	अनाज, चाबुक, गेट, स्टूल, कुर्सी		राजा बनारस का निवास स्थान राजा बलवन्त सिंह द्वारा स्थापित
(३) मिर्जापुर	पत्थर, वारनिश बनाने वाले चूरे, घी, कालीन ब्रास, लोहे के वर्तन, तेल के बीज, मसाला, पान, कच्चे रेशम, एवं बन में उत्पन्न होने वाली सामग्री,	वाले चूरे, लोहा, ब्रास, कापर, नमक, सूती वस्त्र के टुकड़े,	मुख्य ट्रेडिंग केन्द्र पूर्वी उत्तर प्रदेश का १८ वी० शताब्दी में
(४) चुनार (मिर्जापुर जनपद)	वर्तन, पत्थर, पामशुगर,		मिलेट्री स्टेशन आफ पूर्वी उत्तर प्रदेश का (ई०आई० कम्पनी) १८ वी० शताब्दी में
(५) गाजीपुर	चीनी, अफीम जानवरो के खाल, गुलाबजल इत्र, अनाज,	सूती कपड़े, अच्छे कपड़े, नमक मसाला, धातु	तैयार अफीम चीन के व्यापारिक केन्द्र के लिए
(६) सैदपुर (गाजीपुर जनपद)	सूती वस्त्र, तेल के बीज, तम्बाखू, जानवरो के खाल, सब्जी,		दक्षिण भाग की तहसील (गाजीपुर जनपद)
(७) जमानिया (गाजीपुर जनपद)	चीनी एवं चावल		स्थापित हुआ १५६० में अली कुली खान द्वारा
(८) बलिया	तेल सम्बन्धित बीज, घी	चावल, मसाला, नमक, धातु,	प्रसिद्ध ददरी का मेला यहाँ वर्ष में एक बार लगता है।

(६) मनियार (बलिया जनपद)	चीनी, तेल उत्पादक बीज, सूती कपडा आयात होता था बगाल को	अनाज, मुख्य रूप से निर्यात होता है गोरखपुर बस्ती एव नेपाल	-----
(१०) रसडा (बलिया जनपद)	चीनी, कारबोनेट आफ सोडा	सूती वस्त्र, मसाला, लोहा,	शहर का मुख्य व्यापारिक केन्द्र
(११) सहतवार (बलिया जनपद)	कच्चा माल एव चीनी	सूत, तम्बाखू, नमक, इंगलिश पीस सामग्री	अंग्रेजी पीस गुड्स के प्रमुख वितरक केन्द्र
(१२) शिकन्दरपुर (बलिया जनपद)	गुलाब इत्र एव अन्य प्रकार के इत्र बगाल को जाते थे।	-----	स्थापित हुआ था सिकन्दर लोदी के शासन काल में
(१३) जौनपुर	इत्र, चीनी, अनाज,	-----	-----
(१४) मुगराबादशाह पुर (जौनपुर जनपद)	चीनी	सूत इलाहाबाद से	सुल्तान इब्राहिमशाह द्वारा स्थापित हुआ था, जो जौनपुर का सुल्तान था।
(१५) शाहगज (जौनपुर जनपद)	अनाज	सूत,	बड़ा अनाज का गोदाम था जो नबाव सुजाउद्दौला द्वारा स्थापित था।
(१६) जफराबाद (जौनपुर जनपद)	कागज	-----	प्रसिद्ध क्षेत्र था कागज उत्पादन का १८वीं शताब्दी में

१- स्रोत- यह टेबुल तैयार किया गया है उस आधार पर जो वर्णित है एव दिया हुआ है इम्पीरियल गजेटियर में भारत के (प्रोविंसियल सिरीज) जिल्द (दो) (कलकत्ता १६०८)

**विभिन्न फसली वर्षों के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग
बनारस जनपद में**

परगना एव तहसील	१७७५	१८४०	१८८२
निर्धारित नौ परगनो से सृजित चन्दौली तहसील	२,६४,८६८	२,८२,८५५	२,८०,६६६
निर्धारित एक परगने से सृजित भदोही तहसील	१,७६,६५६	—	—
निर्धारित ग्यारह परगनो से सृजित बनारस (सदर) तहसील	६,१२,५६२	६,३४,५५४	६,१५,५३४
सम्पूर्ण राजस्व योग	१०,८७,११६	६,१७,४०९	८,९६,२००

एफ०डब्लू० फारेस्ट० — फाइनल रिपोर्ट आफ दी सर्वे एण्ड रीविज
आफ रेकार्ड

विभिन्न फसली वर्षों के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग
मिर्जापुर जनपद में

परगना एव तहसील	१८४२-४७ R. A. P.	१८८५ R. A. P.
निर्धारित आठ परगनो से सृजित मिर्जापुर तहसील	३,१७,६३८-०-०	१,६६,६२६-६-०
निर्धारित सात परगनो से सृजित चुनार तहसील	२,८७,५६१-६-२	२,७२,४८८-१२-१
निर्धारित चार परगनो से सृजित दृग्धी समेत राबर्ट्सगज	६३,६०४ - ० - ०	— —
सम्पूर्ण राजस्व योग	६,६८,८०३-६-२	४,३६,११५—२-१

जी० एल० — फाइल रिपोर्ट ऑफ मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट १८८७ एव
डी० एल० बी० ब्राचमैन डिस्ट्रिक्ट गजेटियर मिर्जापुर १६११ (संस्करण)

ऐपेन्डिक्स- (जी)

(द)

विभिन्न फसली वर्षों के अनुसार की गई भू-राजस्व माँग जौनपुर जनपद में

परगना एवं तहसील	१७-६	१७६३	१८४१	१८८१
निर्धारित पंच परगनों से सृजित केराकत तहसील	१,३३,३५१	१,३४,१८६	१,३६,६७८	१,८०,०६७
निर्धारित चार परगनों से सृजित खुटहन तहसील	१,४७,४३५	१,४८,१५०	२,२८,०७२	२,२५,८२३
निर्धारित तीन परगनों से सृजित मछली शहर तहसील	२,६३,८६३	२,७४,१०२	२,८२,३४६	२,८२,३६४
निर्धारित तीन परगनों से सृजित मडियाहू तहसील	३,१६,८१८	३,२६,६११	३,२५,३३७	३,२२,३८०
निर्धारित छ परगनों से सृजित जौनपुर तहसील	२,६२,३६८	२,६५,६०६	२,७७,२३०	२,३६,१०२
सम्पूर्ण राजस्व योग	११,५६,८६५	११,८१,६५८	१२,५२,६६३	१२,४६,७६६

चेस्टर- रिपोर्ट ऑफ़ दी रिवीजन ऑफ़ रेकार्ड सेटिलेमेंट औपरेशन इन दी डिस्ट्रिक्ट ऑफ़ जौनपुर १८७७-१८८६ एव

एच० आर नेविल डिस्ट्रिक्ट गजेटियर ऑफ़ जौनपुर (१६०८ संस्करण)

ऐपेन्डिक्स- (एच०)

(य)

विभिन्न फसली वर्षों के अनुसार की गई भू-राजस्व मॉग गाजीपुर जनपद में

परगना एवं तहसील	१७८८-८९	१७९४	१८४०	१८८०
निर्धारित तीन परगनो से सृजित गाजीपुर तहसील	२,३३,६८६	२,५६,८३१	२,६८,८६२	२,७३,७४४
निर्धारित तीन परगनों से सृजित मुहमदाबाद तहसील	२,२७,०६६	२,३६,४१७	२,५८,६५३	२,४५,१३६
निर्धारित दो परगनो से सृजित जमानिया तहसील	२,३०,६८२	२,३३,३२५	२,३५,०८०	२,४२,७८१
निर्धारित चार परगनो से सृजित सैदपुर तहसील	७८,३५४	७६,०६७	२,७३,११८	२,७१,०३३
सम्पूर्ण राजस्व योग	७,७०,१२४	८,०८,६४०	१०,३५,७१३	१०,३२,६६७

डब्लू इरविन - रिपोर्ट एण्ड सेटिलमेण्ड ऑपरेशन ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (१८६५-१९८०)

विशिष्ट शब्दावली की सूची

विशिष्ट शब्दावली सूची

अब्जवाब— निर्धारित भू-राजस्व के साथ कृषको पर लगाये जाने वाले विविध कर

अमला— सेवको का समूह

अमीन—स्थानीय स्तर पर जॉच पडताल करने हेतु नियुक्त राजस्व अधिकारी

असली मौजा— मूल ग्राम जिसका आकार बड़ा हो

आमिल— राजस्व संग्राहक, राजस्व ठीकेदार,

अषाढ—वर्ष का दसवा महीना

आसामी—खेत जोतने वाला कृषक

अदालत—न्यायिक कोर्ट

अमानत दफ्तर— मुस्लिम काल का एक कार्यालय जिसमे अधीक्षक होता था, सिविल सूट के लिए

आमिलनामा— आमिल के लिए वारन्ट अथवा लिखित आदेश

इजारा— कर उगाहने की एक पद्धति

इकरारनामा—सामान्य स्वीकृति पत्र

इस्तमरारी— स्थाई अवधि

उपायन—भेट

कट्ठा— भूमि पैमाइश की एक इकाई

करघई— बुनकरो पर लगने वाला टैक्स

काछी— कृषको की एक जाति

काजी—न्याय अधिकारी

कानूनगो—भू—अभिलेख रखने वाला

कारिन्दा—सेवक प्रतिनिधि

काश्ताकार—दखलकारी अधिकार रखने वाला कृषक

किलादार—किले का गवर्नर

कोर्ट आफ वार्डस—मृतक लोगो के सम्पत्ति के सदर्थित उत्तराधिकार की अदालत

किश्त— राजस्व भुगतान का अंश

कोस—भूमि पैमाइश इकाई

खानाशुमारी—गृह कर

खाम—सरकार द्वारा कृषको से भू—राजस्व की सीधे व्यवस्था

खिलवत—सम्मान सूचक वस्त्र

खुदकाशत रैयत—वे कृषक जो स्वयं अपनी भूमि पर खेती करते हो स्थाई कृषक

खून बहा वित्त—मृत्यु के पश्चात् प्राप्त वित्त (जीविका हेतु)

गजर—बाजार कर, हाट कर,

गुमास्ता—जमिंदार द्वारा नियुक्त व्यक्ति या अधिकारी जो किराया वसूल करे।

घर दुआरी—गृह कर

चक— विभाजित भूमि का भाग

चकलादार—दीवानी एवं फौजदारी अधिकार सम्पन्न चकला का प्रशासक

चेला—घेरलू सेवक

चौधरी—गाँव अथवा पेशे का मुखिया, कहीं जमिंदार का भी सूचक है।

चौधरी कलवारान—कलवार चौधरी

छटाक—तौल का वाट १/१६ सेर के बराबर

छपर बन्द रैयत—गाव में निवास करने वाला कृषक

जमा—सरकारी राजस्व

जलकर—जल में उत्पन्न होने वाले वनस्पतियों एवं जीवों पर लगने वाला कर

जागीर— वह भूमि जो सेवाओं के करने के उपरान्त प्राप्त हुई हो अथवा जीवन यापन के लिए दी गई हो।

जिलादार— जिले का राजस्व अधिकारी जो आमिल द्वारा भी नियुक्त किये जाते हो।

जेष्ठ—बड़ा—वर्ष नवा महीना

झरी—अनाज पर लगने वाला कर

टकी— जमिंदार को मिलने वाला मालिकाना

डोम—भारत की सब से निम्न जाति

डोम कहार—क्षत्रियों की एक जाति

तकावी—अग्रिम राशि जो कृषकों को पशु एवं बीज के लिए दिये जाते थे।

तप्पा— कई गावों के समूह की ईकाई

ताल्लुका—आधीनस्थ राज्य, राजस्व प्रशासन की दृष्टि से एक जमींदार अथवा जमींदारों के एक परिवार के आधिपत्य में रहने वाले अनेक गावों की ईकाई भू—राजस्व की दृष्टि से परगने का एक ईकाई

तलबाना—आधीनस्थ अधिकारी को देय प्रतिदिन की तनखाह

तसखीस—सशोधित कर निर्धारण

ताल्लुकदार—ताल्लुके का धारक अथवा राजस्व संग्राहक

ताहुद—पट्टा, राजस्व सम्बन्धी अनुबन्ध

थोदार—विभाजित जमींदारी के अनुभाग का स्वामी

दरमाह— प्रतिमाह की दर से

दस्तूर—उल—अमल—सामान्य नियम या व्यवहारिक नियम

दस्तूरी—प्रथागत मजदूरी

दइयक—स्वामित्व के अधिकार के कारण जमींदार को दिया जाने वाला धन जो १० प्रतिशत की दर से हो।

दखिली मौजा— उजडा गाव पूर्णरूपेण अथवा आश्रित पुरवा

दीवान—राजस्व विभाग का प्रमुख अधिकारी

दो विस्वी—जमिंदार को दो विस्वा पर दिया जाने वाला धन राशि

नजराना—कृषको द्वारा जमिंदार को दिया जाने वाला समय—समय पर भेट या उपहार

नाजिम—सूबे का गवर्नर

नाजिर—दरबार का अधिकारी जो जॉच पडताल का अधिकार रखता हो

नानकार—स्वामित्व अधिकार के कारण जमिंदारों को दिया जाने वाला धन जो सरकारी राजस्व हेतु अनुबधित होने की दशा में मिलता हो।

नायब—सहायक

निजजोत—जमीदारों द्वारा स्वयं खेती की जाने वाली भूमि

पट्टा—राजस्व भुगतान सम्बन्धी अनुबध

पट्टादार—राजस्व भुगतान सम्बन्धी अनुबध का धारक

पट्टीदार—विभाजित जमींदारी के एक अनुभाग का स्वामी

परगना—सरकार अथवा जिले का राजस्व प्रशासन सम्बन्धी एक इकाई

परवाना— लिखित आदेश उच्च अधिकारी का अपने अधीनस्थ के लिए

पाही काश्त कृषक—वे कृषक जो जमिंदारों के बाहर के गावों से आते थे।

पुरजोत—भूमि कर जो निवास योग्य भूमि पर लिया जाता हो।

पेशकश—जमिंदारों द्वारा सरकार को दी जाने वाली भेंट या उपहार

फसलीसन—फसल के अनुसार तय किया गया वर्ष

फौजदार—मजिस्ट्रेट के समान का पुलिस अधिकारी

बख्शी—सेना की भर्ती या वेतन देने वाला अधिकारी

बनकर—बाग, बगीचे, फल, फूल पर लगने वाला टैक्स

बनरखा—बनरक्षक

बासिल बाकी—बकाया कलेक्शन

बबुआई— जमिंदार के छोटे लड़के को जीवन यापन हेतु प्राप्त होने वाला

भू—भाग सम्बन्धी अधिकार

वित्त—जीविका हेतु प्रदान किया जाने वाला भूमि अनुदान

वित्तिया—वित्त के रूप में भूमि अनुदान प्राप्त करने वाला

विस्वा—बीघे का १/२० भाग

बीघा—३१३६ वर्गगज भूमि के बराबर के भू-भाग

बेगार लेना— निशुल्क कार्य कराना

भर—आदिम जाति

भययाचारा—जमिंदार परिवार के सदस्यों द्वारा संयुक्त रूप से विशिष्ट अधिकार एवं अनुलाभ रखना

मडवानी शादी—विवाह कर

मन—तौल की इकाई ४० सेर के बराबर

मत्स्य कर—मछली मारने पर लगने वाला कर

भरवट विर्त—सघर्ष में मरने वाले के परिवार को जमिंदार की ओर से दिये जाने वाले वित्त

महतो—मुखिया

महाल—राजस्व प्रशासन की दृष्टि से भूमि सम्बन्धी ईकाई परगना के समकक्ष

माफी— राजस्व मुक्त

मालगुजार—राजस्व दाता, जमिंदार का द्योतक

मालवाजिब—पैमाइश के आधार पर दिया जाने वाला भू—राजस्व

मालिकाना—भूमि सम्बन्धी अधिकार के कारण सरकारी राजस्व हेतु अनुबन्धित न होने की दशा में जमींदार को दिया जाने वाला धन

मुकद्दम—गाव का मुखिया

मुजारा—वे किसान जो अन्य साधनों से कृषि कार्य करते थे।

मुफिसल कचहरी—आन्तरिक भागों में स्थित कार्यालय

मुसहर—एक आदिम जाति।

मुहाफिजखाना—अभिलेखागार

मोचबिन्दी विर्त्त—जमींदारी की सीमाओं की रक्षा हेतु दिया जाने वाला ऋण

मौजा—गाव

मौरूसी—बशानुगत

रसूम—ए—जमींदारी—अनाज या धन नगद रूप में जमींदार को मिलने वाला नानकार

राजगी—प्रमुख जमींदारों द्वारा एकत्रित किये जाने वाले विविध कर

राहदारी—गमन कर केवल सड़कों से संबंधित कर

रियाया—प्रजा

रिसालादार—अश्वारोहियों की टुकड़ी का प्रमुख अधिकारी

रेजीडेंट—ईस्ट इंडिया कम्पनी द्वारा नियुक्त प्रतिनिधि

रैयत—कृषक

रैयती—कृषको से सम्बन्धित

वकील—अधिकार सम्पन्न प्रतिनिधि

वासिल बाकी—एकत्रित राजस्व का बकाया राजस्व

सजावल—राजस्व एकत्रित करने हेतु नियुक्त अधिकारी

सदर कचहरी— प्रमुख कार्यालय, केन्द्रीय कार्यालय

सदावर्त— भोजन दान, लगर

सनद—दस्तावेज

सपथ—राहदारी

सरकार—प्रशासनिक इकाई

सरबराकार—प्रबधक

सरिश्तादार—प्रधान लिपिक—कानूनगो की पदवी

सीर—जामिदार स्वयं की खेती की जाने वाली भूमि

सूबा—प्रान्त, मुगल साम्राज्य की सब से बड़ी इकाई

सेर जमींदारी—भू—राजस्व के अतिरिक्त जमींदारी में लगाने वाले विविध कर
हुक्क—ए—जमींदारी—नानकार या मालिकाना के अतिरिक्त जमींदार के
अन्य अनुलाभ

हरी बेगारी— जमींदार द्वारा बेगार के रूप में कृषकों के हल बैल की
परम्परा के अनुसार निजी लाभ लेना

लट्ठा—माप करने वाला राड एक बीघा बराबर २० लट्ठे के

लम्बरदार— जो सरकारी देय के लिए नियुक्त किया गया हो।

अनुक्रमणिका

अनुक्रमणिका

मूल अंग्रेजी रेकार्ड (अप्रकाशित)

(अ) बनारस रेजीडेन्सी करसपान्डेन्स

रेकार्ड्स आफ दी बनारस डिवीजन

(१) पोलिटिकल लेटर्स इशूड बाई दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल
(१७६५—१८१०)

(२) मिस्लेनियस लेटर्स रिसीब्ड बाई दी एजेन्ट टू दी गवर्नर जनरल
(१७६५—१८१०)

(३) ओरिजनल करसपान्डेन्स ऑफ दी रेजिडेन्ट (१७७६—१७६५)

(ब) बनारस करसपान्डेन्स (बनारस कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) रेवेन्यू करसपान्डेन्स लेटर्स इशूड फ्राम (१७६६—१८१०)

(२) लेटर रिसीब्ड फ्राम १७६६ टू १८१०

जुडीशियल करसपान्डेन्स

(१) लेटर रिसीब्ड फ्राम १७६६ टू १८१०

(२) लेटर इशूड एण्ड रिसीब्ड फ्राम १८००—१८१०

(स) मिर्जापुर करसपान्डेन्स (मिर्जापुर कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) लेटर इशूड फ्राम दी गवर्नमेन्ट टू दी मजिस्ट्रेट (१७६५-१८१०)

(२) लेटर इशूड फ्राम निजामत अदालत एण्ड कोर्ट आफ सर्किट टू दी मजिस्ट्रेट, (१७६५-१८११)

(३) कापीज आफ लेटर्स रिलेटिंग टू मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट सेन्ट टू दी कलेक्टर आफ बनारस (१७६५-१८१०)

(४) लेटर इशूड वाई दी मजिस्ट्रेट, (१८०३-१८१०)

(५) सरकुलर आर्डर्स इशूड वाई दी निजामत अदालत (१७६५-१८२७)

(द) गाजीपुर करसपान्डेन्स (गाजीपुर कलेक्ट्रेट रिकार्ड्स)

(१) करसपान्डेन्स विद कलेक्टर आफ बनारस रिलेटिंग टू गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (१८०२-१८२०)

राष्ट्रीय अभिलेखागार, नई दिल्ली

(१) बगाल सीक्रेट कन्सल्टेशन (१७६४-१७७५)

(२) बगाल सेलेक्टेड कमेटीज प्रोसीडिंग्स (१७६५-१७७५)

(३) बगाल पोलेटिकल कन्सल्टेशन (१७६५-१७७५)

(४) होम पब्लिक कन्सल्टेशन (१७६५-१८०१)

(५) सेप्रेट रेवेन्यू लेटर्स फ्राम एण्ड टू दी कोर्ट (१७६६-१७६६)

(६) फारेन सीक्रेट कन्सल्टेशन (१८५०—१८५६)

(७) सीक्रेट सेलेक्ट कमेटी प्रोसीडिंग (१७६५—१७७५)

(८) फारेन पोलिटिकल कन्सल्टेशन (१८५४—१८५६)

बोर्ड आफ रेवेन्यू रिकार्ड्स

(१) प्रोसीडिंग्स आफ दी बोर्ड आफ रेवेन्यू एट फोर्ट विलियम
(१८०३—१८०७)

(२) करसपान्डेन्स रिगार्डिंग डोमिनियन्स आफ राजा आफ बनारस
(१८२८—१८४६)

सचिवालय रेकार्ड

(१) आगरा नरेटिव फारेन डिपार्टमेन्ट

(२) टेलीग्राम सेन्ट टू एण्ड रिसीव्ड बाई ई ए रीड

मूल अंग्रेजी रेकार्ड्स (प्रकाशित)

(१) कलेन्डर आफ इंडियन स्टेट पेपर्स (सीक्रेट सिरीज) १७७४—१७७५

(२) डाडवेल, एच०— वारेन हैस्टिंग्स लेटर्स टू जान मेकफर्सन लन्दन
१६२७

(३) फर्मिन्गर, डब्लू ० के०— दी फिफ्थ रिपोर्ट फ्राम दी सेलेक्टेड
कमेटीज आफ हाउस आफ कामन्स आन दी अफेयर्स आफ दी ईस्ट
इन्डिया कम्पनी १८१२ तीन जिल्द मे (कलकत्ता १६१७—१६१८)

(४) फारेस्ट, जी० डब्लू— लेटर्स डिस्पैचेज एण्ड अदर स्टेट पेपर्स (१७७२—१७८५) तीन जिल्द मे १८६२

(५) फारेस्ट, जी० डब्लू— सेलेक्शन फ्राम दी स्टेट पेपर्स आफ दी गवर्नर जनरल आफ इन्डिया, वारेन हैस्टिंग्स दो जिल्द मे आक्सफोर्ड १६१०

(६) ग्रिजर, सेडने, सी०—दी लेटर्स आफ वारेन हैस्टिंग्स टू हिज वाइफ (लन्दन १६०५)

(७) हैस्टिंग्स, डब्लू० ए० —नरेटिव आफ इन्सरेक्सन व्हिच हैपेन्ड इन दी जमिन्दारी आफ बनारस (रुढकी १७८२)

(८) मेम्बायर्स रिलेटेड टू दी स्टेट आफ इन्डिया (लन्दन १७८६)

(९) हैस्टिंग्स जी० डब्लू—ऐ विन्डिकेशन आफ वारेन हैस्टिंग्स, आक्सफोर्ड—१६१६

(१०) रिपोर्ट्स (१—IX) फ्राम दी सेलेक्ट कमेटी एप्वाइन्टेड टू टेक इनटू कनसिडरेशन दी स्टेट आफ एडमिनिस्ट्रेशन आफ जस्टिस इन बंगाल

(११) यूनियन फाइनेन्स मिनिस्टर्स वजट स्पीच फार (1951-1952)

(१२) गवर्नमेन्ट आफ इडिया टैक्सेशन्स इन्क्वाइरी कमेटी रिपोर्ट (१६५४) बिहार, उडीसा, (१७८२—१७८३)

(१३) रिपोर्ट्स फ्राम दी कमेटी आफ दी हाउसआफ कामन्स जिल्द (५) ईस्ट (१७८१—१७८२) १८०४

(१४) मिनट्स आफ ऐवीडेन्स टेकेन बिफोर दी सेलेक्ट कमेटी आन दी अफेयर्स आफ दी ईस्ट इन्डिया कम्पनी (पार्लिमेन्टरी पेपर्स) १८५५, नम्बर ४४५-१)

(१५) सेलेक्शन फ्राम रेवेन्यू रेकार्ड्स आफ दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज (१८१८-१८२०) कलकत्ता १८६६

(१६) ए० कैटेलाग आफ स्टेट पेपर्स एन० डब्लू० पी० जुडीशियल सिरीज इलाहाबाद-१६५६

(१७) सेलेक्शन फ्राम इंगलिश रेकार्ड्स-बनारस एफेयर्स (१७७६-१८५८) दो जिल्द मे इलाहाबाद १६५४-५६

(१८) सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्ड्स, दो जिल्द मे वाई- सेक्सपीयर, ए० (बनारस १८७३)

(१९) शेक्सपीयर्स, एच०-एन ऐब्सट्रेक्ट आफ रेग्युलेशन इनऐक्टेड फ्राम दी ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ पुलिस एण्ड क्रीमिनल जस्टिस इन दी प्राविन्स आफ बंगाल, बिहार एण्ड उडीसा, कलकत्ता- १८२४

(२०) शार्प, एच०- सेलेक्शन फ्राम ऐजुकेशनल रेकार्ड्स पार्ट (१) १७८१-१८६६ कलकत्ता १६२०

(२१) ऐचकिसन, सी०यू०- दी ट्रीटीज इन्वोजमेन्ट एण्ड सनद जिल्द (२) कलकत्ता १६०६

(२२) ट्राटर जे० एल- वारेन हैस्टिग्स 'ए बायोग्राफी'

(२३) बौन्ड, ई०ए०—स्पीचेज आफ दी मैनेजर्स एण्ड कौंसल्स इन दी ट्रायल आफ वारेन हैस्टिग्स चार जिल्द मे लन्दन (१८५६—६१)

(२४) हिस्ट्री आफ ट्रायल आफ वारेन हैस्टिग्स (१७८६—६५) लन्दन १७६६

(२५) मिन्दस आफ ऐविडेन्स टेकेन बिफोर ए कमेटी आफ दी होल हाउस आफ काम्स लन्दन १७८७

(२६) डेवीज सी० जी० — दी बनारस डायरी (ऐडिटेड) लन्दन १६४८

(२७) डेवीज, जे० एफ०— वजीर अली खॉ आर दी मेराकर आफ बनारस (ऐ चैप्टर न इन्डियन हिस्ट्री) बनारस १६३८

(२८) इरविन, डब्लू— रिपोर्ट आन सर्वे एण्ड रीवीजन आफ रिकार्ड्स बनारस डिस्ट्रिक्ट इलाहाबाद १८३६

(२९) ओल्डम्, डब्लू—हिस्टारिकल एण्ड स्टेटिस्टिकल मेम्बयर्स आफ दी गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट (दो जिल्द मे) इलाहाबाद १८७०

(३०) डगलस डेवर— ऐ हैन्ड बुक टू दी प्रीम्प्यूटनी रेकार्ड

(३१) कलेण्डर आफ पर्शियन करसपाण्डेन्स

गजेटियर्स

(१) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (बनारस) १६०६ नेवेल एच० आर०

(२) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (गाजीपुर) १६०६ नेवेल एच०
आर०

(३) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (मिर्जापुर) १६११ नेवेल एच०
आर०

(४) डिस्ट्रिक्ट गजेटियर आफ यू०पी० (जौनपुर) १६०८ नेवेल एच०
आर०

(५) फिशर, एफ०एच०एव हेवेट, जे० पी०, गजेटियर आफ एन० डब्लू०
पी० (बनारस, जौनपुर, मिर्जापुर) जिल्द XIV इलाहाबाद १८८४

(६) इम्पीरियल गजेटियर आफ इन्डिया जिल्द XII

जर्नल एण्ड रिपोर्ट्स (अंग्रेजी)

(१) जर्नल आफ ऐशियाटिक सोसाइटी आफ बंगाल जिल्द IXII पार्ट

(१) १८६३ पृष्ठ ५५-५६ "हिस्ट्री आफ द ईस्ट इन्डिया कम्पनीज
क्वायनेज, वाई-एस० थर्सटन

(२) ऐशियाटिक रिसर्चेज जिल्द (५) दी ऐकाउन्ट आफ दी डिस्कवरी
आफ टू टर्न्स इन दी विसिन्टी आफ बनारस, वाई जे० डकन

(३) जर्नल आफ गंगा नाथ झा रिसर्च इन्स्टीट्यूट नम्बर १६४३ 'टू
सस्कृत मेमोरेन्डा आफ १७८७' वाई एस० एन० सेन

(४) जर्नल आफ इन्डियन हिस्ट्री जिल्द (३) पार्ट (१) मार्च १६२६, वारेन
हैस्टिंग्स एण्ड हिज ऐक्युजर्स बाई पी० ई० राबर्ट

(५) प्रोसीडिंग आफ दी इण्डियन हिस्टारिकल रेकार्ड्स कमीशन जिल्द
XXX पार्ट (१) हैदराबाद सेशन १९५४. ' चेतसिंह एण्ड हैस्टिंग्स,
बाई हसन अस्करी

(६) प्रोसीडिंग आफ दी इण्डियन हिस्ट्री कांग्रेस सत्ताइसवा सेशन
इलाहाबाद १९६५, "दी वकील्स इन दी अर्ली ब्रिटिश जुडीशियरी
आफ बगाल बाई पी०एन० बेनर्जी

(७) प्रोसीडिंग आफ दी इण्डियन हिस्ट्री रिकार्ड्स कमीशन जिल्द XIV
१९३७ 'सम साइड लाइट्स आन दी हिस्ट्री आफ बनारस' बाई के०
आर० कानूनगो

(८) चटर्जी, एच०सी०—नोट्स आन दी इन्डस्ट्रीज इन यू०पी०
इलाहाबाद—१९१८

(९) डैम्पियर, जी० आर०—ए मोनोग्राफ आन दी ब्रास एण्ड कापर वर्क्स
इन दी एन०डब्लू पी० एण्ड अवध, इलाहाबाद, १८९४

(१०) गनी, सी० डब्लू—मोनोग्राफ आन दी मेन्यूफेक्चर आफ वायर एण्ड
टिनसेल इन दी यू०पी० इलाहाबाद—१९१०

(११) रिपोर्ट आफ दी रायल कमीशन आफ ओपियम, १८९४—१८८५

(१२) रिपोर्ट आन दी रिवीजन आफ रेकार्ड्स एण्ड सेटिलमेन्ट औपरेशन
इन जौनपुर डिस्ट्रिक्ट १८८६

(१३) रिपोर्ट आन दी कम्पलीशन ऑफ दी रिवीजन ऑफ रेकार्ड्स एण्ड सेटिलमेण्ट ऑपरेशन इन मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट, इलाहाबाद १८८७

(१४) बर्नाड एस० कोन०— पोलेटिकल सिस्टम इन ऐट्टीन्थ सेन्चुरी इन इंडिया (जर्नल आफ अमेरिकन सोसाइटी जिल्द ८२ अक (३)

शोध ग्रन्थ (अप्रकाशित)

(१) एस०एन० सिन्हा—‘सूबा आफ इलाहाबाद अण्डर दी ग्रेट मुगल्स’

(२) एम० एम० खान—‘ट्रेड एण्ड इन्डस्ट्रीज आफ इंडिया’ (१७००—१७५०)

(३) सैयद नजमुल रजा रिजवी ‘ स्टडी आफ जमिदार्स आफ इस्टर्न यू०पी० इन एट्टीन सेन्चुरी’

(४) मदन गोपाल श्रीवास्तव ‘ आस्पेक्ट आफ अर्बन सोसाइटी आफ इस्टर्न यू० पी० इन एट्टीन्थ सेन्चुरी

(५) नीरा दरबारी—नार्दर्न इंडिया अण्डर औरगजेब सोशल एण्ड एकोनामिकल कण्डीशन ।

परशियन स्रोत

(१) हदीकद-उल-अकलिम

मुर्तजा हुसैन बिलग्रामी द्वारा लिखित जो सचिव था कैप्टन जोनाथन स्काट का साथ ही परशियन सचिव था वारेन हैस्टिंग्स का, उसने लेखन का यह कार्य उनके व्यक्तिगत निवेदन पर पूर्ण किया। १७८०—८१ तक के

लिए यह पुस्तक उपयोगी है। उपरोक्त पुस्तक सादत खॉ, सफदरजग, चेतसिह, के सदर्थ में व्याख्या करती है।

(२) तहजीह-उल-गफलिन

इसके मूल लेखक लन्दोनी है जो रेवेन्यू अधिकारी थे आसफुद्दौला के समय में। यह १२११ में कलकत्ते से प्रकाशित हुई जिसका अनुवाद १८८५ में डब्लू० होये० द्वारा हुआ। यह आसफुद्दौला के समय का इतिहास है।

(३) यादगारी-बहादुरी

बहादुर सिंह भटनागर द्वारा लिखित १८४२ में अपने तरह का विशिष्ट कार्य है जो मेम्बायर एव गजेटियर की तरह का है। यह देश के भौगोलिक, औद्योगिक, वाणिज्यिक, सामग्रियों से युक्त है और साथ ही परशियन कवियों के जीवन की व्याख्या भी प्रस्तुत करता है।

(४) तोफाय-ताज अथवा बलवन्तनामा

खैर उद्दीन मोहम्मद द्वारा १७८० में रचित यह विश्वसनीय सामग्री प्रस्तुत करता है। उपरोक्त पुस्तक बनारस के शासकों के सदर्थ में व्याख्या करता है। ११६६ से १७८०, तक के अर्थात् मनसाराम से प्रारम्भ होकर यह सादत खान, सफदरजग, सुजाउद्दौला, एव वारेन हैस्टिंग्स तक के विषय में प्रकाश डालता है। दूसरी तरफ मनसाराम, बलवन्त सिंह, चेतसिह के सदर्थ में भी विचार प्रस्तुत करता है। इसका अनुवाद १८७५ में फ्रेडिक कार्वेन द्वारा हुआ।

(५) जौनपुर-नामा

खैर उद्दीन द्वारा लिखित १७६६ में यह जौनपुर के इतिहास से सम्बन्धित है। यह वारेन हैस्टिंग्स पर भी यथेष्ट प्रकाश डालती है जो बाद में पोवायशन द्वारा अनुवादित हुआ।

उर्दू स्रोत

(१) तवारी खे-ईश्वरी (इलाहाबाद म्यूजियम) सैयद अमीर अली द्वारा लिखी गई है। उपरोक्त पुस्तक बनारस के शासक परिवार के राजनैतिक इतिहास का एक रूप है जो मनसारांम से प्रारम्भ होकर ईश्वरी नारायण सिंह तक का है। यह पुस्तक १८५० में लिखी गई।

(२) दीक्षित-एस० मजहर-तारीखे बनारस (दो जिल्द में बनारस १६१६)

संस्कृत अभिलेख अप्रकाशित

(१) दीक्षित शकर-चीतो बिलास-काशीराज विद्यामन्दिर ट्रस्ट वाराणसी में सुरक्षित (हस्तलिपि)

(२) बलभद्र-चेतसिंह विलास-काशीराज विद्यामन्दिर ट्रस्ट वाराणसी में सुरक्षित (हस्तलिपि)

हिन्दी स्रोत

(१) सतीश चन्द्र- उत्तर मध्यकालीन भारत का इतिहास

(२) नोमान अहमद सिद्दीकी—मुगलकालीन भू—राजस्व प्रशासन
(१७००—१७५०)

(३) मोरलैण्ड—मुगलकालीन ग्रामीण व्यवस्था

(४) हरीशकर श्रीवास्तव—मुगल प्रशासन

(५) सम्पूर्णानन्द—चेतसिंह और काशी का विद्रोह

(६) सुन्दर लाल—भारत में अंग्रेजी राज्य

(७) शेफाली चटर्जी—शर्की राज्य जौनपुर का इतिहास

(८) ए०एल० श्रीवास्तव अवध के दो नवाब

(९) ए०एन० सिंह— इतिहास की दृष्टि में गाजीपुर

हिन्दी अभिलेख (अप्रकाशित)

चेत चन्द्रिका —गोकुल नाथ बदीजन

उपरोक्त १८०१ में लिखित सामान्य वशावली है बनारस राज की खित्तू
मिश्रा से लेकर राजा चेतसिंह तक की।

समाचार पत्र जर्नल एवं रिपोर्ट हिन्दी में

(१) हंस प्रकाशन ' हंस काशी अक, अक्टूबर, नवम्बर, १९३३

(२) काशी नागरी प्रचारणी सभा 'अक—३,४,—पत्रिका १९३३

(३) कल्याण पत्रिका

(४) 'भारत' समपचार पत्र

(५) 'आज' समाचार पत्र

सहायक ग्रन्थों की सूची

ग्रन्थ सूची

अरनाल्ड, एडविन—दी मारक्विस आफ डलहौजी एडमिनिस्ट्रेशन आफ ब्रिटिश इन्डिया भाग २ (लन्दन १८६५)

अल्तेकर ए० एस०— हिस्ट्री आफ बनारस (बनारस १६३७)

अशरफ, के०एम०—लाइफ एण्ड कडीशन आफ दि पीपुल्स आफ हिन्दुस्तान (१२००—१५००) कलकत्ता (१६३५)

अगनाइड्स एन०पी०—मुहम्मडन थ्योरीज आफ फाइनेन्स (न्यूयार्क १६१६)
आकलैण्ड, रेव (टी०ए०) — पापुलर ऐकाउन्ट आफ मैन्स एण्ड कस्टम्स इन इंडिया (१८४७)

अल्तेकर, ए० एस० एण्ड मजूमदार आर०सी०—एन्यू हिस्ट्री आफ इंडियन पीपुल्स जिल्द (६) लाहौर—१६४६

आर्चर, डब्लू०—इंडिया एण्ड दी फ्यूचर—१६१७

अस्कोली, एफ० डी०—अर्ली रेवेन्यू हिस्ट्री आफ बंगाल एण्ड फिफथ रिपोर्ट (आक्सफोर्ड) १६१७

अस्पिनाल, ए०— कार्नवालिस इन बंगाल (मेन्चेस्टर १६२३)

एरिक स्टोक्स—दी इंगलिश यूटिलिटेरियन्स एण्ड इंडिया (आक्सफोर्ड १६५६)

एन्स्टी वीरा—दी इकोनामिक डेवेलोपमेन्ट आफ इंडिया (लन्दन १६३६)

ऐडवर्ड डब्लू-पर्सनल ऐडवेन्चर्स डयूरिंग दी इंडिया

वाकिल सी०एन०— गान्धीयन एकनामिक थाट

विश्वेशरैया— ऐन इन्ट्रोडक्शन टू दी स्टडी आफ इंडियन ऐकोनामिक्स

बेबरीज हेनरी— ए कम्प्रहेसिव हिस्ट्री आफ इन्डिया (दिल्ली १७७४)

ब्राउन पर्सी—इंडियन आर्किटैक्चर (इस्लामिक पीरियड) तारापुर वाला
(१९६४)

ब्लोच मैन एच०— आईने अकबरी का अनुवाद जिल्द (१) द्वितीय संस्करण
(१९६५)

बेनर्जी ए०सी०—कास्टीट्यूशनल डाक्यूमेन्ट जिल्द (१) द्वितीय संस्करण
(१९६५)

बेनर्जी ए०सी०—कास्टीट्यूशनल डाक्यूमेन्ट जिल्द (१) १९४८

भटनागर जी०डी०—अवध अण्डर वाजिद अली शाह (बनारस १९६८)

वाट जी०—डिस्कवरी आफ इकोनामिक प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया जिल्द (४)
कलकत्ता १८६०

भार्गव एम० एल० —हिस्ट्री आफ मार्डन इण्डिया (१९७०)

बुकनान—ऐ जर्नी फ्राम मद्रास थ्रू मैसूर केनरा एण्ड मालाबार/बेडेन पावेल
बी० एच०—लैण्ड सिस्टम आफ ब्रिटिश इण्डिया, जिल्द (३)

(आक्सफोर्ड १८६२)

बासू, बी०डी०—ऐजुकेशन इन इण्डिया अण्डर दी ईस्ट इण्डिया कम्पनी
(कलकत्ता)

बर्नियर, फ्रान्सिस—ट्रेवेल्स इन मुगल इम्पायर (१६५—६८) A.D. १८६१

बोमन बरहम बी०के०—ऐजुकेशनल कन्ट्रोवर्सीज इन इंडिया बम्बई (१६४३)

ब्रिज, जान—हिस्ट्री आफ राइज आफ मोहम्मडन पावर इन इण्डिया टिल दी
इयर १६१२ ए०डी० (कलकत्ता १६०८)

भारतीय, विद्याभवन—हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ इण्डियन पीपुल्स जिल्द
१—४ (बम्बई १६६०—६५)

चन्द्र सुधीर— डिपेन्डेन्स एण्ड डिसइल्यूजमेन्ट (मानस पब्लिकेशन) (१६७५)

चेटर्जी एच० सी०—नोट्स आन इन्डस्ट्रीज इन यू०पी०

चन्द्र, विपिन— दी राइज एण्ड ग्रोथ आफ एकोनामिक नेशनलिज्म इन
इण्डिया (लन्दन १६३६)

सी० राइक्स— नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इण्डिया

चौधरी के० के०— स्टडीज इन दी हिस्ट्री आफ बंगाल सूबा

(१७४०—१७७०) कलकत्ता १६३६

चोपडा पी०एन०— लाइफ एण्ड लेटर्स अण्डर दी मुगल्स (दिल्ली १६७६)/

डो० ऐलेक्जेण्डर—दी हिस्ट्री आफ इण्डिया जिल्द (२) लन्दन (१७६८)

डेवीज जे०एफ० वजीर अली खॉ ऑन दी मेसेकर इन बनारस (ए चैप्टर इन इण्डियन हिस्ट्री) बनारस १९३८

डे० यू०एन० एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम आफ दिल्ली सल्तनत इलाहाबाद (१९५६)

दत्त आर० पी०—'इंडिया टुडे' बम्बई (१९४६)

दत्त—रमेश—एकोनामिक हिस्ट्री आफ इंडिया अण्डर दी अर्ली ब्रिटिश रूल (संस्करण—५) लन्दन

डेवर डगलस—ए हैन्डबुक टू दी इंग्लिश प्री म्यूटनी रेकार्ड (इलाहाबाद १९१६)

डब्लू क्रूक—दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज ऑफ इंडिया देयर हिस्ट्री ऐथोलॉजी एण्ड एडमिनिस्ट्रेशन

डे० वी०—तबकाते अकबरी (अग्रेजी अनुवाद) जिल्द (१) ऐशियाटिक सोसाइटी कलकत्ता (१९७३)

डी० पन्थ— दि कामर्शियल पालिसी आफ मुगल्स

डा० एलेक्जेण्डर—हिस्ट्री आफ हिन्दुस्तान (जिल्द ३,२,) लन्दन (१८०३)

डे० यू०एन०—दि गर्वनमेन्ट आफ दी सल्तनत दिल्ली १९७२

डे० नन्द लाल— दि जियोग्राफिकल डिक्शनरी आफ ऐन्शेन्ट एण्ड मेडिवल इंडिया दिल्ली (१९७१)

दत्ता, के० के०—सर्वे आफ इन्डीयाज सोशल लाइफ एण्ड ऐकोनामिक कडीशन इन दी ऐट्ठीन्थ सेन्चुरी (१७०७—१८१३) कलकत्ता १६६१

डब्लू वर्ड— व्यू आफ हिस्ट्री लिट्रेचर एण्ड रिलीजन आफ हिन्दूज

डेविस, ए० एम०— वारेन हैस्टिग्स, मेकर आफ ब्रिटिश इण्डिया लदन १६०२

डुप्लेन— ऐसेन्सियल आयल (पी० आफ० दी का०)

डेविस, सी०सी०—वोरन हैस्टिग्स एण्ड अवध लन्दन १६३५

डाडवेल, एच० एच०— दी कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इण्डिया (जिल्द ५)
(कैम्ब्रिज १६२२)

डैमपियर जी०बी०—ऐमोनोग्राफ आन ब्रास एण्ड कापर वायर एन०डब्लू० पी०
इलियट एण्ड डाउसन—हिस्ट्री आफ इण्डिया ऐज टोल्ड बाई दी
हिस्टोरियन्स जिल्द (८) लन्दन (१८६७)

ई० बुड—दी रिवोल्ट इन हिन्दूस्तान

इरैस्किन, ई०—मेम्बयार्स आफ बाबर—लन्दन (१६२६)

इ० थर्सटन—हिस्ट्री आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी क्वायनेज

इरविन एच०सी०—दी गार्डेन्स आफ इण्डिया (१८८०)

फारुकी जहीरुद्दीन—औरगजेब एण्ड हिज टाइम

फार्बर, जेम्स— ओरियन्टल मेम्बयार्स जिल्द (२) लन्दन (१८१३)

फारेस्ट, जी० डब्लू०— लाइफ आफ लार्ड क्लाइव जिल्द (२) १६१८

फारेस्ट, जी० डब्लू—सेलेक्शन फ्राम स्टेट पेपर्स आफ गवर्नर जनरल आफ इण्डिया, वारेन हैस्टिंग्स, जिल्द (२.५) आक्सफोर्ड (१६१०)

फास्टर, जी०— जर्नी फ्राम बंगाल टू इंग्लैण्ड जिल्द (१)

फर्बर, होल्डेन—दी प्राइवेट रिकार्ड आन इण्डियन गर्वनर जनरलशिप

फिन्डले एस०—साइस आफ पब्लिक फाइनेन्स

फिज— अर्ली ट्रेवेल्स

फ्यूहरर ए० एव स्मिथ ई० डब्लू०—दि शर्की आर्किटेक्चर आफ जौनपुर (कलकत्ता १८८६)

जाफर एस०एम०—ऐजुकेशन इन मुस्लिम इण्डिया दिल्ली (१६७३)

गिन्च— अर्ली ट्रेवेल्स

ग्लिंग, जी० आर०—मेम्वायर्स आफ लाइफ आफ वारेन हैस्टिंग्स जिल्द (३) लन्दन १८४१

घोषाल, जी० आर०—एकोनामिक ट्रान्जिशन इन दी बंगाल प्रेसीडेन्सी (१७६३—१८३३) पटना

हजेला टी०एन— आर्थिक विचारो का इतिहास

हेमिल्टन, सी० जे० दी ट्रेड रिलेशन बिटवीन इंग्लैण्ड एण्ड इडिया (१६००—१८६६) कलकत्ता १६१६

हेवेल, ई० बी०— बनारस—दी सेक्रेट सिटी, द्वितीय संस्करण लंदन

हेबर, ई० आर०— ए नरेटिव आफ जर्नी थू दी अपर प्राविन्सेज आफ इंडिया फ्रॉम कलकत्ता टू बाम्बे २ (जिल्द) लंदन १८४६

हेबर आर—हिस्ट्री आफ प्राविन्स आफ बनारस, देहरादून १८३२

हबीब, आई०—ऐंग्रीगेरियन सिस्टम इन मुगल इंडिया दिल्ली १९६३

हसन, आई—दी सेंट्रल स्ट्रक्चर आफ मुगल इम्पायर

हन्टर, डब्लू०डब्लू०—इंडियन मुसलमान्स— १९४५

हेनरी एडवर्ड फेन—फाइव इयर्स इन इंडिया

होरीवाला, बी० आर०—स्टडीज इन इन्डोमुस्लिम हिस्ट्री, सप्लीमेन्ट जिल्द (२) पूना १९५७

हबीब, एम० एव निजामी के० ए०— कैम्ब्रिज हिस्ट्री आफ इंडिया जिल्द (५) दिल्ली १९७०

इलियट एव डाउसन—भारत का इतिहास जिल्द (२) १९६८

इरविन, डब्लू—लेटर मुगल्स, जिल्द (२) कलकत्ता

खैरुद्दीन, मोहम्मद—हिस्ट्री आफ जौनपुर (अनुवाद पाउसन) कलकत्ता १८७८

खैरुद्दीन मोहम्मद 'तोकाय ताज' (बलवन्त नामा)

के, जे० डब्लू-ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी लन्दन १८५३

कीथ, ए० बी०- ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इण्डिया कम्पनी लन्दन १८५३

कीथ, ए० बी०-स्पीचेज एण्ड डाक्यूमेन्ट्स आन इण्डियन पालिसी, लन्दन
(जिल्द २) १६२२

कुरैशी आई० एच०- ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ सुल्तान्स आफ देहली

क्रिक पैट्रिक-एकाउन्ट आफ नेपाल

लीवारनर, डब्लू-लाइफ आफ मारक्विस आफ डलहौजी भाग (२) लन्दन
(१६०४)

लॉ, एन०एन०-प्रमोशन आफ लरनिंग इन इंडिया बाई अर्ली यूरोपियन
सेटलर्स, लन्दन (१६१५)

ली० वार्नर, डब्लू-प्रोटक्टेड प्रिन्सेज आफ इण्डिया (लन्दन १८७८)

लेनपूल, स्टेनली, मेडिवल इण्डिया अडर मुहम्मडन रूल दिल्ली १६६३

लाल, के० एस०-स्टडीज इन मेडिवल इण्डियन हिस्ट्री दिल्ली-१६६६

लाडलो, जौन० मालकम्-ब्रिटिश इण्डिया इट्स रेस एण्ड इट्स हिस्ट्री
जिल्द (२) कैम्ब्रिज-१८५८.

म्यूथिएट, जे० आर०- स्माइलिग बनारस (मद्रास १६११)

मिश्रा बी० बी०- दी सेन्ट्रल एडमिनिस्ट्रेशन आफ ईस्ट इंडिया कम्पनी
(१७७३-१८३४) बम्बई (१६५८)

मैलकम् ले०जे०—स्केच आफ दी पोलिटिकल हिस्ट्री आफ इन्डिया

मजुमदार, आर०सी०—दी हिस्ट्री एण्ड कल्चर आफ दी इंडियन पिपुल भाग
१ बम्बई (१९६३)

मोरलैण्ड, डब्लू० एच०—दी एंग्रेरियन सिस्टम आफ मुस्लिम इन्डिया
(इलाहाबाद, १९२६)

मनूची ट्रेवेल्स—खंड (२)

मार्टिन आर० एम०—दी हिस्ट्री आफ दी इंडियन इम्पायर भाग (२) लन्दन

मिश्रा बी० आर०—लैण्ड रेवेन्यू पॉलिसी इन यूनाइटेड प्राविन्स अण्डर दी
ब्रिटिश रूल (बनारस १९४२)

मार्शमैन, जे०सी०—दी हिस्ट्री आफ इण्डिया भाग २ (सीरमपुर १८६७)

मित्रा किशोरी चन्द्र—गवर्नमेन्ट आफ पीपुल—कलकत्ता १८५८

मुखर्जी आर० के०—फाउन्डेशन आफ इन्डियन इकॉनामी

मखकौल्म, जे०एल०—स्केच आफ दी पोलिटिकल हिस्ट्री आफ इन्डिया

मैक्फर्सन, डब्लू सी०—सोल्डरिंग इन इंडिया (१७०४—१७८७) लन्दन १९२८

मैलसन, जी०बी०—लाइफ आफ वारेन हैस्टिंग्स लन्दन १८४४

मिल, जेम्स०—दी हिस्ट्रीआफ ब्रिटिश इंडिया जिल्द (५) १८५८

मोरलैण्ड, डब्लू० एच०—दी रेवेन्यू ऐडमिनिस्ट्रेशन आफ यू०पी० (कलकत्ता १६११)

मुखर्जी, आर० के०—लैण्ड प्रॉब्लम इन इन्डिया (लन्दन १६३३)

मिश्रा, के० पी०—ट्रान्जिशन इन बनारस

मैकाले टी० बी०—एसे आन वारेन हैस्टिंग्स

नारायण, वी०ए०—जोनाथन डकन एण्ड बनारस—कलकत्ता १६५६

नियरिंग स्काट—दी ट्रेजडी आफ इम्पायर—कलकत्ता १६५६

निजामी, के०ए०—स्टडीज इन मेडिवल इंडियन हिस्ट्री एंड कल्चर (इलाहाबाद—१६६६)

ओल्डम डब्लू—मेम्बार्स आफ गाजीपुर (इलाहाबाद १८७०)

ओल्डम डब्लू—टेनेन्ट्स राइट्स एण्ड ऑक्सन सेल्स इन गाजीपुर एण्ड दी प्राविन्स आफ बनारस (इलाहाबाद) (१८७३)

प्रिन्सेप, जे०—बनारस इलस्ट्रेशन इन ए सीरीज आफ ड्राइंग्स (कलकत्ता १८३०)

पुरी, वी०ए०—दी हिस्ट्री आफ गुजरात एण्ड प्रतिहाराज' (बम्बई १६५७)

प्रयाग दयाल—कैटेलाग आफ क्वायनेज आफ किंग्स आफ अवध

प्रसाद एस०एन०—पैरामाउन्टसी अण्डर डलहौजी (संस्करण १६६४)

पी० मुन्डी— मुन्डी ट्रेवेल्स

प्रसाद, ईश्वरी—हिस्ट्री आफ माडर्न इडिया (इलाहाबाद १९५१)

प्रेल्डेन, टी०सी०—सेटिलमेन्ट आफ एन० डब्लू० पी० (इलाहाबाद)

कुरैशी, आई० एच०— एडमिनिट्रेशन आफ सुल्तान्स आफ देलही (दिल्ली १९७१)

राबर्ट्स, पी० ई०—हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडिया अन्डर दी कम्पनी एण्ड दी क्राउन (आक्सोर्ड—१९३८)

रैमजेबूथम, आर०बी०—स्टडी इन दी लैण्ड रेवेन्यू हिस्ट्री आफ बंगाल (आक्सफोर्ड—१९२६)

रिकार्ड्स, आर०—हिस्ट्री आफ इडिया, जिल्द (२) लन्दन १९२६

रशीद ए०—सोसाइटी एण्ड कल्चर इन मेडिवल इडिया कलकत्ता १९६६

राइक्स, चार्ल्स—नोट्स आन दी नार्थ वेस्टर्न प्राविन्सेज आफ इडिया (लन्दन १८५२)

रेनल, जे०—मेम्वायर्स आफ हिन्दुस्तान, लन्दन १७८८

शर्मा, एस० आर०—दी क्रेसेन्ट इन इडिया (हिन्दी रुपान्तर आगरा १९७१)

सिंह, विजय बहादुर—ऐकोनामिक हिस्ट्री आफ इडिया (बम्बई १९६५)

स्पीयर, पर्साइवल— मार्लन इडियन हिस्ट्री (१९६१)

सरकार, जदुनाथ—मुगल शासन पद्धति (आगरा १६६४)

शर्मा, एस०आर०—भारत मे मुस्लिम शासन का इतिहास

शेक्सपीयर, ऐ०—सेलेक्शन फ्राम डकन रेकार्डस— १८७३

स्टोक्स, ई०— दी इंगलिश यूटेलीटेरियन एण्ड इडिया

सिन्हा, एन०के०— दी ऐकोनामिक हिस्ट्री आफ बगाल फ्राम प्लासी टू परमानेन्ट सैटिलमेन्ट जिल्द (१) १६५६

सरकार जे० एन —इण्डस्ट्रीज इन मुगल इडिया

सरन पी०—प्राविन्शियल गवर्नमेन्ट आफ दी मुगल्स

सरकार, जदुनाथ— औरंगजेब एन्ड हिज टाइम्स

सिन्हा, जे०सी०— ऐकोनामिक ऐनल्स आफ बगाल (लन्दन १६२७)

शेसाद्री, पी०—बनारस (१६२५)

सरकार, जे० एन०— हिस्ट्री आफ औरंगजेब जिल्द (३) कलकत्ता १६४६

सेटन, कर, डब्लू एस०—दी मारक्वीस आफ कार्नवालिस एण्ड कनसालीडेशन आफ ब्रिटिश रूल आक्सफोर्ड—१६१४

सेरिंग, एम०ऐ०—सेक्रेड सिटी आफ हिन्दूज— लन्दन १८६८

स्माइलिग, जे० आर०— बनारस (मद्रास १६११)

श्रीवास्तव, ए०एल०—दी फर्स्ट टू नवाब्स आफ अवध (आगरा—१६४२)

शाह के० टी०—ऐकनामिक स्ट्रक्चर आफ फ्री इन्डिया

सदर, लैण्ड डी०—दी रेग्युलेशन आफ बगाल कोड (जिल्द—१) कलकत्ता
१८६२

एस० नूरुल हसन— जमीदार्स अण्डर दी मुगल्स

सदरलैण्ड, डी०—ऐपेन्डिक्स टू दी कोड आफ बगाल रेग्युलेशन जिल्द (१)
कलकत्ता (१८६४)

ट्राटर, जे० एल०—वारेन हैस्टिंग्स— ए बायोग्राफी (आक्सफोर्ड) १८७८

तारा चन्द— इन्फ्लूयेन्स आफ इस्लाम आन इडियन कल्चर (इलाहाबाद
१६७६)

ट्रेवर्नियर—ट्रेवेल्स

त्रिपाठी, राम प्रसाद — सम आस्पेक्ट्स आफ मुस्लिम ऐडमिनिस्ट्रेशन,
इलाहाबाद

थॉर्नटन, ई०— दी हिस्ट्री आफ ब्रिटिश इडियन इम्पायर जिल्द (२) लन्दन
(१८४२)

टामस ए०—लैण्ड सिस्टम इन बनारस राज

ट्रेवेलियन, सी० ई०— आन दी ऐजुकेशन आफ दी पीपुल्स आफ इण्डिया
(कलकत्ता १८३८)

वाट, जी०—डिस्कवरी आफ ऐकोनामिक प्रोडक्ट्स आफ इण्डिया जिल्द (४)

कलकत्ता १८६०

वेलेन्टिया, सी० वी० —वायेजेज एण्ड ट्रेवेल्स टू इंडिया जिल्द १

लन्दन—१८११

वार्ड, डब्लू—व्यू आफ दी हिस्ट्री, लिट्रेचर एण्ड रिलिजन आफ दी हिन्दूज

जिल्द (२) लन्दन (१८१७)

वीलर, जे० टी०—अर्ली रेकार्ड्स आफ ब्रिटिश इण्डिया कलकत्ता १८७६

विल्सन, हारेस हेमैन,— ए ग्लासरी आफ जुडिशियल एण्ड रेवेन्यू टर्म्स,

लन्दन १८५५

विन्टर निट्ज, एम०—दी हिस्ट्री आफ इण्डियन लिट्रेचर, कलकत्ता १६५६